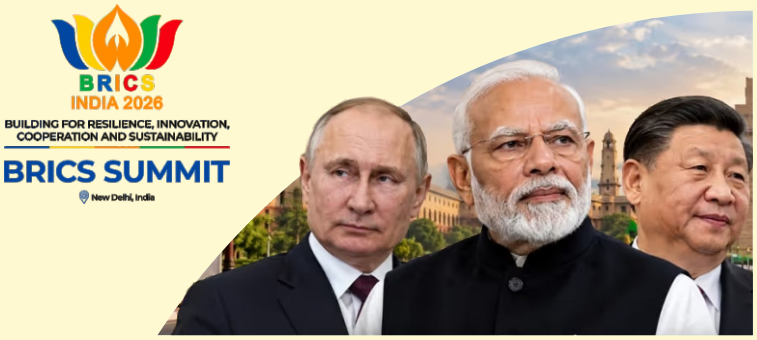
मासिक पत्रिका | अक्टूबर 2026

PRGI NO. RJHIN/26/A2336

सम्यक् करेंट अफेयर्स

▶ अंतरराष्ट्रीय ▶ राष्ट्रीय ▶ राजस्थान











संजय कुमार अग्रवाल बने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति











वर्ष 01, अंक 06, अक्टूबर 2026,मूल्य 100/- प्रति, वार्षिक शुल्क 1000/-, पृष्ठ संख्या 112

Samyak

An Institute For Civil Services

03 दिवसीय नि:शुल्क कक्षा के साथ

ऑफलाइन व LIVE FROM CLASSROOM

बैच प्रारम्भ

IAS
FOUNDATION
@3PM to 7PM

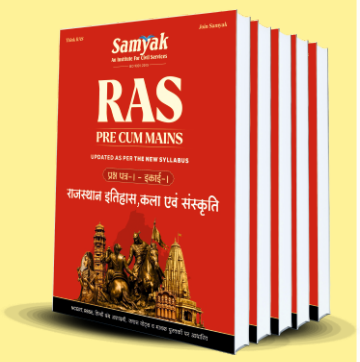
RAS
FOUNDATION
@8AM to 12PM

COMBO COURSE PSI
PAPER I & II
E.O/R.O
@3PM to 7PM

क्लास 12th के बाद
IAS & RAS
ग्रेजुएशन के साथ 2 & 3 वर्षीय कोर्स
@3PM to 7PM

ONLINE COURSE FEATURES
- Live From Classroom
- Printed Booklets
- Personal Mentorship
- Test Series

SCAN QR & DOWNLOAD APP NOW



बैच की विशेषताएँ

- विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लासेज
- टेस्ट सीरीज
- लाइब्रेरी सुविधा*
- प्रिंटेड बुकलेट्स
- पर्सनल मेंटरशिप

SEPARATE BATCHES FOR **HINDI & ENGLISH MEDIUM**

H.O: NEAR RIDDHI - SIDDHI, JAIPUR 9875170111

–:: अनुक्रमणिका ::–

अध्याय	पृष्ठ संख्या
◆ मासिक सारांश	7
◆ राजस्थान परिदृश्य	11
महोत्सव/सम्मेलन/अभियान/आपरेशन	22
चर्चित व्यक्ति/स्थान/अन्य	24
खेल/खेल व्यक्तित्व	25
◆ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य	27
◆ राष्ट्रीय परिदृश्य	32
◆ आर्थिक परिदृश्य	43
◆ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	49
◆ खेल परिदृश्य	53
◆ पुरस्कार एवं सम्मान	59
सम्मेलन/बैठक/मेला/ महोत्सव/प्रदर्शनी	64
निर्वाचन और नियुक्ति निर्वाचन एवं नियुक्ति	79
निधन	81
अभियान/युद्धाभ्यास	82
◆ महत्वपूर्ण दिवस	86
◆ **विशेष लेख : भारत में परमाणु ऊर्जा**	88
◆ **भारत के संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग**	97
◆ करेंट अफेयर्स- October-2026 अंक वस्तुनिष्ठ टेस्ट	113

स्वत्वाधिकारी सम्यक एड्यूटेक,

प्रकाशक एवं सम्पादक वैष्णवी भारद्वाज द्वारा SP-21, गंगाराम नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राजस्थान)-302018 से प्रकाशित एवं महारानी प्रिन्टर्स, प्लॉट नं. 17, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर, राजस्थान-302012 से मुद्रित।

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर, राजस्थान होगा।)

Gmail id - currentaffairs@samyakias.com

मो. 9460480423 | इस अंक का मूल्य : 100 | वार्षिक सदस्यता शुल्क : 1000

इस अंक मे प्रकाशित किसी भी सामग्री अथवा चित्र के लिए संपादक की सहमति होना आवश्यक नहीं है। इस पत्रिका मे प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापति किए गए हैं। यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया है तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक, उससे किसी व्यक्ति विशेष को पहुंची क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

संपादकीय

"समय के साथ चलने वाला ही मंज़िल तक पहुँचता है।"

यह पंक्ति सुनने में साधारण लगती है, पर वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए यह चेतावनी भी है और रास्ता भी। हमारे यहाँ समय को लेकर चेतावनियों की कमी नहीं रही। कबीर ने सदियों पहले कहा था, "काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।" गीता में श्रीकृष्ण ने समय को ही 'काल' रूप में सबसे बलवान बताया है। पर आज सवाल सिर्फ़ यह नहीं कि हम समय का पालन करते हैं या नहीं, बल्कि यह भी है कि हमसमय के साथ बदलते हैं या नहीं।

बदलती दुनिया, बदलती परीक्षाएँ-

कुछ साल पहले तक तैयारी का मतलब था मोटी किताबें और रटे हुए तथ्य। अभ्यर्थी का सबसे बड़ा हथियार उसकी याददाश्त मानी जाती थी। जिसने जितना ज़्यादा याद कर लिया, वह उतना ही आगे समझा जाता था। तारीख़ें, नाम, आँकड़े और सूचियाँ कंठस्थ करना ही तैयारी की कसौटी थी।

आज तस्वीर बदल चुकी है। परीक्षाएँ अब केवल यह नहीं पूछतीं कि आपको क्या पता है, वे यह भी परखती हैं कि आप जो जानते हैं उसका उपयोग कैसे करते हैं। समझ, विश्लेषण और समसामयिकी जागरूकता आज की परीक्षा की रीढ़ बन गई हैं। इंटरनेट के इस दौर में तथ्य एक क्लिक पर उपलब्ध हैं, इसलिए तथ्यों को जानना कम और उन्हें जोड़कर देखना ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हो गया है।

यह बदलाव केवल परीक्षा-कक्ष तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी रटंत पद्धति की जगह कौशल और अवधारणात्मक समझ पर ज़ोर दिया है। नीति का आशय स्पष्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य अंक लाना भर नहीं, बल्कि सोचने-समझने वाला, समस्याएँ सुलझाने वाला नागरिक गढ़ना है। जब शिक्षा की दिशा बदलती है, तो उसे परखने वाली परीक्षाओं का स्वरूप बदलना स्वाभाविक है।

पाठ्यक्रम से आगे, दुनिया की समझ-

आज समसामयिकी अलग से पढ़ा जाने वाला 'अतिरिक्त विषय' नहीं रहा है। वह हर विषय का आधार बन चुका है। अर्थव्यवस्था पढ़ते समय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, राजनीति पढ़ते समय संसद की बहसें और न्यायालय के निर्णय, भूगोल पढ़ते समय जलवायु सम्मेलन और आपदाओं की ख़बरें, ये सब पाठ्यपुस्तक के सूखे पन्नों में जान डालते हैं। जो इन्हें साथ-साथ पढ़ता है, उसकी तैयारी दोहरी मज़बूत होती है।

हालांकि यहाँ एक सावधानी भी ज़रूरी है। हर ख़बर को रटने की कोशिश उसी पुरानी रटंत का नया रूप है। असली कला यह है कि हर समसामयिकी घटना को देखकर तीन सवाल पूछे जाएँ-

- यह क्यों हुआ?
- इसका असर किस पर पड़ेगा?
- आगे क्या हो सकता है?

जो परीक्षार्थी ख़बर को इस नज़र से पढ़ता है, वह जानकारी का संग्रह नहीं करता, समझ का निर्माण करता है और लक्ष्य को प्राप्त का लेता है।

संपादक

Samyak
An Institute For Civil Services

निबन्ध प्रतियोगिता

निबन्ध का विषय-

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता - विकास की उड़ान या मानवता के अंत की शुरुआत।
2. सांस्कृतिक विरासत - अतीत का सम्मान, भविष्य का निर्माण

निबन्ध प्रतियोगिता के लिए आवश्यक शर्तें और निर्देश-

- निबन्ध लेखन पूरी तरह मौलिक होना चाहिए, नकल या एआई द्वारा जनरेटेड सामग्री मान्य नहीं होगी।
- निर्धारित शब्द सीमा का पालन करें- 600 शब्द (लगभग)
- निबन्ध में व्याकरण, वर्तनी और विराम चिह्नों की शुद्धता पर ध्यान रखें।
- निबन्ध में केवल प्रमाणित और सटीक आंकड़ों या ऐतिहासिक तथ्यों का ही उपयोग करें।
- निबन्ध को निर्धारित अंतिम तिथि और समय से पहले ही जमा करें। (31 अक्तूबर, 2026)
- निबन्ध केवल निम्न माध्यम से प्रेषित किये जा सकते हैं-

1. Whatsapp- 9875170111
2. Mail- samyakcurrentaffairs@samyakias.com
3. स्थानीय पता- Samyak- An Institute For Civil Services, Near Riddhi-Siddhi, Jaipur

- निबन्ध के साथ प्रतियोगी अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, आधिकारिक नाम और पता अवश्य भेजें।

पुरस्कार-

- प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पाने वाले प्रतिभागियों के फोटो को अगले माह की समसमायिकी पत्रिका में स्थान दिया जायेगा और संबंधित माह का अंक उनके निर्धारित पते पर भेजा जायेगा।

निबन्ध प्रतियोगिता- सितंबर, 2026 (सर्वश्रेष्ठ निबन्ध)

"राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और उसके समक्ष सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियाँ।"



अमित यादव
IAS Mains 2023, 2025

राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे जहन में राजपूती शान, रेतीले धोरे और वीरांगनाओं की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन इसके उलट, जमीनी हकीकत थोड़ी अलग रही है। सदियों से यहाँ एक ऐसी पितृसत्तात्मक सोच हावी रही है, जिसने महिलाओं को घर की चारदीवारी और चूल्हे-चौके तक समेट दिया। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ कागजी योजनाओं से नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है- बेटियों को वो आजादी और माहौल देना जहाँ वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें और समाज में बराबरी से सिर उठाकर जी सकें। यह एक खुशहाल राजस्थान की सबसे पहली सीढी है।

आज हवा का रुख थोड़ा बदल रहा है। बाड़मेर की रूमा देवी ने अपनी सुई-धागे की कला से हजारों महिलाओं को रोजगार दिलाया, तो वहीं अवनि लेखरा ने पैरालंपिक में गोल्ड जीतकर साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। गाँव-देहात में छवि राजावत जैसी पढी-लिखी सरपंचों ने जब पंचायत की कमान संभाली, तो लोगों का नजरिया बदला। सरकारी कोशिशों का भी कुछ असर दिख रहा है; 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5'के मुताबिक जन्म के समय लिंगानुपात सुधरकर 929 हो गया है। 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' ने बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाकर उन्हें स्कूल भेजा है, और 'उड़ान योजना' ने मुफ्त सैनिटरी पैड बांटकर एक पुरानी झिझक तोड़ी है। 'राजीविका' से जुड़कर आज लाखों महिलाएं छोटी-मोटी बचत कर रही हैं और खुद का काम शुरू कर रही हैं।

पर इन अच्छी बातों के पीछे एक बहुत कड़वी हकीकत भी है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। आज भी कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज का एक काला सच है। भले ही इसे रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू है, लेकिन चोरी-छिपे ये अपराध अब भी होते हैं, जो राज्य की शिशु मृत्यु दरको प्रभावित करते हैं।हालाँकि, 2011 के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में 0-6 वर्ष आयु वर्ग का बाल लिंगानुपात 888 बालिकाएँ प्रति 1000 बालक था।जो राज्य में लैंगिक असमानता की प्रारंभिक आयु में ही मौजूदगी को दर्शाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5का ही आंकड़ा बताता है कि आज भी करीब 25 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। बचपन छिन जाने से उनकी पढ़ाई और सेहत दोनों तबाह हो जाती हैं। गांवों में 'घूंघट' आज भी महिलाओं को खुलकर बोलने नहीं देता। और सबसे डराने वाली बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और घरेलू हिंसा के मामलों में राजस्थान की गिनती आज भी देश के शीर्ष राज्यों में होती है।

आर्थिक तौर पर भी मुश्किलें कम नहीं हैं। हम सब देखते हैं कि गाँव की महिलाएं दिन-भर खेतों में और घर पर खटकती रहती हैं, लेकिन उनके इस काम को 'रोजगार' नहीं माना जाता, न कोई पगार, न कोई छुट्टी। संपत्ति के नाम पर उनके हाथ खाली होते हैं; पुश्तैनी जमीन-जायदाद में उनका हक अक्सर सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है। ऐसे में अगर कोई महिला अपना काम शुरू करना चाहे, तो गारंटी न होने की वजह से बैंक से लोन मिलना लोहे के चने चबाने जैसा हो जाता है। इसके अलावा, जो महिलाएं असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करती हैं, उन्हें अक्सर उसी काम के लिए आदमियों के मुकाबले कम दिहाड़ी मिलती है।

अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं, तो सिर्फ योजनाओं का ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले बच्चियों की पढ़ाई को सीधे आज के हुनर (कौशल विकास और कंप्यूटर ज्ञान) से जोडना होगा। बाप-दादा की जमीन और संपत्ति में बेटियों का कानूनी हक सख्ती से लागू करवाना होगा ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हों। इसके अलावा, कन्या भ्रूण हत्या रोकने वाले पीसीपीएनडीटी एक्ट को और कड़ाई से लागू करना होगा और पुलिस-प्रशासन को इतना चुस्त बनाना होगा कि महिलाओं को न्याय के लिए दर-दर न भटकना पड़े।

कुल मिलाकर, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण का रास्ता आसान नहीं है। इसमें कुछ उजली उम्मीदें हैं, तो कई गहरी खाइयां भी। जब तक समाज की वो पुरानी सोच नहीं बदलेगी जो बेटी को 'पराया धन' या 'बोझ' मानती है, तब तक कोई भी कानून पूरी तरह कामयाब नहीं होगा। जिस दिन हमारी बेटियां बिना डरे, बिना किसी भेदभाव के आगे बढेंगी, सही मायनों में उसी दिन एक सशक्त राजस्थान बनेगा।

मासिक सारांश

- राज्य सरकार की 'एक जिला, एक उत्पाद' योजना के अंतर्गत राजस्थान की पहली प्याज प्रोसेसिंग यूनिट्स किस जिले में स्थापित की जाएंगी?- **सीकर और अलवर**
- भरतपुर-ब्यावर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई कितनी है?- **277 किलोमीटर**
- राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता है?- **अनिंदम सील**
- राजस्थान के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को 'ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम' के सफल क्रियान्वयन के लिए कौनसा सम्मान प्रदान किया गया है?- **गोल्ड स्कॉच अवार्ड**
- 110वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की कितनी अभिनव पहलों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?- **दो**
- 7 सितंबर, 2026 को राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है, यह राजस्थान उच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश है?- **44वें**
- राज्य सरकार ने 'राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग' का कार्यकाल बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 तक कर दिया है, वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष है?- **मदन लाल भाटी**
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'वनगिरि' के प्रथम शहद उत्पाद 'आदिपराग' को किस तिथि को लाँच किया?- **26 सितंबर, 2026 को**
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौनसा स्थान प्राप्त हुआ है?- **चतुर्थ स्थान**
- राज्य में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 लागू होने के दस वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम 'चिंतन-एक दशक की पहल' का आयोजन किसके द्वारा किया गया?- **राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति एवं पोक्सो समिति द्वारा**
- राजस्थान के घरेलू क्रिकेट में वर्ष 2025-26 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सीनियर वर्ग में किस खिलाड़ी को मथुरादास माथुर अवॉर्ड के लिए चुना गया है?- **अशोक शर्मा (जयपुर)**
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026' में श्रेणी-I (10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर) में जयपुर कौनसे स्थान पर रहा है?- **20वां**
- राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन को और अधिक मजबूत करने के लिये किस प्रक्रिया को लाँच किया गया है?- **ई-जनसुनवाई प्रक्रिया**
- "विकसित भारत-जन सेवा अभियान" के लिए किसे राज्य समन्वयक नियुक्त किया गया है?- **अभय कुमार को**
- जैन विश्व भारती में आयोजित आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार समारोह में वर्ष 2026 का आचार्य श्री तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार किसको प्रदान किया गया?- **दिया कुमारी को**
- विकसित भारत जन सेवा अभियान के अंतर्गत निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान द्वारा प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 'आंगन मिलन सेवा' का आयोजन किया गया है?- **25 से 27 सितम्बर, 2026 के मध्य**
- 15 सितम्बर, 2026 को राजस्थान सरकार द्वारा कहां पर प्रवासी राजस्थानी मीट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया?- **भुवनेश्वर, ओड़िशा**
- ग्लोबल नर्सिंग समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया?- **राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर**
- 30 सितम्बर, 2026 को कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल ने किस व्यक्ति को 'किसान ब्राण्ड एम्बेसेडर एवं ट्रेनर' नियुक्त किया है?- **श्री मोती लाल कुमावत को**
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एडीसी किसे नियुक्त किया गया है?- **मेजर नव्या शेखावत को**
- बांसवाड़ा की किस युवती ने येकातेरिनबर्ग (रूस) में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया?- **खनक उपाध्याय ने**
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए है- **जस्टिस विनीत माथुर**
- सब-जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जायेगा?- **अलंकार महिला पीजी महाविद्यालय, जयपुर**
- हॉकी राजस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया है?- **महिपाल सिंह**
- जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वैश टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया था?- **सुरभि मिश्रा को**
- हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ की रेफरी बनाया गया है?- **पूजा राठौड़ को**
- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 का विषय क्या था?- **"सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण"।**

- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में भारत का कौनसा स्थान रहा है?- **131वां**
- ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2026 में वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर कौनसा शहर रहा है?- **न्यूयार्क**
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गयी थी?- **डॉ. खलीलुर रहमान**
- हाल ही में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम भारत की यात्रा पर थे, यह है?- **शिया इस्माइली मुसलमानों के 50वें वंशानुगत इमाम**
- 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया?- **बिश्केक, किर्गिस्तान**
- देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आधारित ट्रेन का शुभारंभ कहां से किया गया है?- **साबरमती रेलवे स्टेशन से**
- इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है?- **नीति आयोग**
- हाल ही में झारखंड के किस पारंपरिक जनजातीय वाद्ययंत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है?- **'मांदर' को**
- मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2026 रैंकिंग में टॉप-100 में भारत के कितने है?- **14 संस्थान**
- 'आयुर्वार्ता' नामक विशेष डिजिटल संवाद श्रृंखला की शुरुआत किसके द्वारा की गयी है?- **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली ने**
- भारत के 7वें डाक प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी गयी है- **शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में**
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने तेलंगाना के कौनसे मंदिर को 'राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक' घोषित किया है?- **गोल्लाला गुड़ी मंदिर**
- भारत ने देश में बाल विवाह की प्रथा को कौनसे वर्ष तक पूरी तरह समाप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है?- **वर्ष 2030 तक**
- देश का पहला बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र कहां शुरू हुआ है?- **दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में**
- फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कौनसी फिल्म को वर्ष 2027 के ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री चुना है?- **'गोंधल' को**
- हाल ही में किस राज्य ने एयरोस्पेस पॉलिसी 2026-31 को मंजूरी दी है?- **कर्नाटक ने**
- भारत का कौनसा शहर वर्ष 2032 में 'यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप' की मेजबानी करेगा?- **पुणे शहर**
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स-2026 में भारत का कौनसा स्थान रहा है?- **31वां**
- हाल ही में यूनेस्को आईओसी कार्यक्रम के तहत ओडिशा के कितने गांवों को 'सुनामी रेडी' घोषित किया गया है?- **74 गांवों को**
- विपणन सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि किस फसल के लिए घोषित की गई है?- **कुसुम**
- हाल ही में ओडिशा के किस पोर्ट को मेगा पोर्ट का दर्जा दिया गया है?- **पारादीप पोर्ट को**
- आईएनएस निपुण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? - **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम**
- इलेक्ट्रिक इंटरसेप्टर ड्रोन 'आहुति Mk-II' का निर्माण किसके द्वारा किया गया है?- **अपोलियन डायनेमिक्स**
- भारतीय वायु सेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित खगांतक-243 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह क्या है?- **ग्लाइड बम**
- भारत का पहला उन्नत स्वदेशी महासागर अनुसंधान पोत कौनसा है?- **ओआरवी सागर मंथन**
- अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट-05 किस लाँच व्हीकल से लाँच किया गया?- **GSLV-F17**
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया?- **पेरिस, फ्रांस**
- हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रोबोटिक्स लैब ने एक अत्याधुनिक ह्यूमनॉइड अंडरवॉटर रोबोट विकसित किया है, इस रोबोट का नाम है?- **'OceanOneK'**
- महिला टी-20 एशिया कप, 2026 की विजेता और उपविजेता टीम है- **भारत (विजेता), श्रीलंका (उपविजेता)**
- टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे व भारत के पहले बल्लेबाज बने है?- **अभिषेक शर्मा**
- महिला टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 का आयोजन किस देश में किया जायेगा?- **भारत में**
- पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2026 में भारत ने किस देश को हराया है?- **दक्षिण कोरिया को**
- महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2026 की उपविजेता टीम रही है- **चीन**
- यूएस ओपन 2026 में पुरुष एकल का ख़िताब किसने जीता है?- **अलेक्जेंडर ज़्वेरेव (जर्मनी)**
- राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां हुआ था?- **लुधियाना (पंजाब)**
- एलीना मिश्रा जो चार साल की सबसे कम उम्र की शतरंज महिला खिलाड़ी है, यह किस राज्य की निवासी है?- **ओडिशा**
- शतरंज में 'वुमन इंटरनेशनल मास्टर' का प्रतिष्ठित टाइटल किसने हासिल किया है?- **निहारिका चल्ला**
- वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते है?- **15 पदक**
- हाल ही में मार्कोस लोरेंटे ने फ़ुटबाल से संन्यास की घोषणा की है, यह किस देश के खिलाड़ी है?- **स्पेन**

- अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड-2026 का आयोजन कहां हुआ था?- **तुरिन (इटली)**
- वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता के कौनसे संस्करण का आयोजन किया गया था?- **48वां**
- एशियाई खेल 2026 का आधिकारिक स्लोगन था- **IMAGINE ONE ASIA**
- अंतरराष्ट्रीय लेक्रोज प्रतियोगिता में भारतीय लेक्रोज टीम में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों (महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में) का चयन हुआ था?- **15 खिलाड़ियों का**
- हाल ही में एशिया बॉक्सिग कमेटी का निर्विरोध वाइस चेयरमैन चुना गया है?- **अरुंधति चौधरी**
- हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने और सबसे ज्यादा शतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है?- **स्मृति मंधाना**
- दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है?- **अनंत नाग**
- 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब किस फिल्म ने जीता है?- **आर्टिकल 370 (हिंदी)**
- 68वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार-2026 किसे प्रदान किया गया?- **टॉमी कोह, रुना खान, बो की**
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जन सेवा पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है?- **श्री किशोर मकवाना**
- हाल ही में डॉ. हिशाम एंडोमेंट अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया है?- **डॉ. रेशमा वी.आर. नायर**
- कटक में सरला साहित्य संसद ने किस व्यक्ति को 'कलिंग रत्न पुरस्कार' से नवाजा है?- **जस्टिस दीपक मिश्रा को**
- 'महादेवी वर्मा विश्व भूषण सम्मान-2026' से किसे सम्मानित किया गया है?- **कवि कन्हैयालाल भ्रमर को**
- जीवरान फाउंडेशन, प्रयागराज की ओर से किसे महात्मा गांधी गौरव सम्मान दिया गया?- **डॉ. विवेक शर्मा को**
- 9वां राष्ट्रीय पोषण माह 2026 अभियान का विषय क्या है?- **"हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी"**
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहां हुआ?- **पणजी, गोवा**
- वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम (डब्ल्यूसीईएफ) 2026 का आयोजन स्थल और विषय क्या था?- **गांधीनगर (गुजरात), विषय- 'सर्कुलर इकोनॉमी: लोगों और समृद्धि के लिए बदलाव'**
- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का कौनसा संस्करण आयोजित हुआ था?- **9वां**
- 'संयुक्त परिचालन समीक्षा एवं मूल्यांकन' (कोर) कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया था?- **एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय (आईडीएस)**
- हिंदी दिवस 2026 एवं छठा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहां आयोजित हुआ?- **नवी मुंबई, महाराष्ट्र**
- राज्य वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवो का सम्मेलन किस तिथि को हुआ है?- **18 और 19 सितंबर, 2026**
- प्रहार-CT (आतंकवाद-रोधी) नीति और रणनीति पर सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?- **अमित शाह (केन्द्रीय गृह मंत्री)**
- नैनोमेडिसिन पर विश्व कांग्रेस 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था?- **इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंसेज (आईएनएमएस), चिकित्सा विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय**
- एशियाई-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) के महासचिव के रूप में लगातार दूसरी बार चार वर्षीय कार्यकाल के लिए किसे पुनः चुना गया है?- **डॉ. विनय प्रकाश सिंह**
- मोरक्को के किंग मोहम्मद हसन ने किसे देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है?- **फातिमा जहरा मंसूरी**
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 सितंबर 2026 से किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है?- **सुमन राय**
- हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की विशेष जंगल वॉरफेयर कमांडो यूनिट 'कोबरा' की पहली महिला आईजी बनाया गया है?- **संजुक्ता पाराशर**
- अभ्यास तरंग शक्ति-2026 का आयोजन कहां किया गया था?- **जोधपुर वायु सेना स्टेशन**
- एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2026 के आयोजक थे?- **भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बल**

■■■■



Samyak
An Institute For Civil Services

श्रीगणेश करें अपनी RAS तैयारी का

सिद्धि विनायक बैच के साथ

RAS FOUNDATION

COMPLETE COURSE LIVE FROM STUDIO

हिंदी माध्यम



+



Complete Study Material + T-Shirt

- विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लासेज
- असीमित बार देखने की सुविधा
- पर्सनल मेंटरशिप
- लाइव क्लासेज
- टेस्ट सीरीज
- Printed booklets
- Intensive Attention

फीस मात्र:
₹27,000
~~₹54,000~~

BUY NOW

DOWNLOAD THE APP NOW
Samyak
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR
9875170111

राजस्थान परिदृश्य

शेखावाटी की हवेलियाँ यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल-

- यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 'शेखावाटी के चित्रित हवेली नगर' को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है।
- राजस्थान के तीन ज़िलों (झुंझुनू, चूरू और सीकर) की कुल 14 ऐतिहासिक नगरों में फैली इमारतों और स्थापत्य समूहों को इसमें शामिल किया गया है।
- **सम्मिलित-**
  - चूरू ज़िला-चूरू
  - सीकर ज़िला-लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, फतेहपुर और सीकर
  - झुंझुनू ज़िला-डूंडलोद, झुंझुनू, अलसीसर, बिसाऊ, चिड़ावा, खेतड़ी, महनसर, मंडावा और नवलगढ़
- Note- यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल होना विश्व धरोहर का दर्जा मिलने की अंतिम प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस दिशा में पहला जरूरी कदम है। इस सूची में उन स्थलों को रखा जाता है, जिन पर आगे चलकर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता है।

संजय कुमार अग्रवाल बने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति-

7 सितंबर, 2026 को राज्यपाल **श्री हरिभाऊ बागडे** ने **न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल** को राजस्थान उच्च न्यायालय के **44वें मुख्य न्यायाधीश** के रूप में शपथ दिलाई।

न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से स्थानांतरित हुए है।



उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति-

अनुच्छेद 217- इस अनुच्छेद के तहत किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।

नियुक्ति की प्रक्रिया- नियुक्ति कर्ता- भारत का राष्ट्रपति

संवैधानिक परामर्श-राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधि तराज्य के राज्यपाल से परामर्श।

- राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने किसे राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलगुरु (कुलपति) नियुक्त किया है?- **डॉ. भगवती प्रसाद सारस्वत**
- राजस्थान राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगरीय निकायों के चुनाव में अध्यक्षीय पद के चुनाव कार्यक्रम के लिए लोक सूचना किस तिथि को जारी की गयी थी?- **15 सितम्बर, 2026**
- जियोन कम्पनी ने राजस्थान के किस जिले में 10 मेगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजना चालू की है?- **फलोदी**
- प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर त्वरित, प्रभावी कार्रवाई करने और अपराध के नए तरीकों पर गहन अनुसंधान करने के लिए जयपुर पुलिस रेंज में कौनसी सेल का गठन किया है?- **राडार सेल**

राजस्थान उच्च न्यायालय



1 एकीकरण से पूर्व की स्थिति (1949 से पहले)

- एकीकरण से पहले राजस्थान की 5 रियासतों में पृथक उच्च न्यायालय संचालित थे-

1. जयपुर
2. जोधपुर
3. बीकानेर
4. अलवर
5. उदयपुर (इसकी एक खंडपीठ कोटा में कार्यरत थी)

2 पटेल समिति एवं उच्च न्यायालय की स्थापना (1949 - 1950)

उद्देश्य-
- नए राज्य की राजधानी एवं उच्च न्यायालय का स्थान तय करने हेतु समिति गठित की गई।

सदस्य-
- बी.आर. पटेल (अध्यक्ष)
- ले. कर्नल टी.सी. पुरी
- एस.पी. सिन्हा

सिफारिश (27 मार्च, 1949)-
- **राजधानी-** राज्य की राजधानी जयपुर होगी।
- **उच्च न्यायालय-** उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित किया जाएगा।

3 स्थापना एवं उद्घाटन-

अध्यादेश-
- राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 जो 21 जून, 1949 को लागु हुआ तथा पाँचों रियासती उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया।

उद्घाटन-
- 29 अगस्त, 1949 को जोधपुर में

उद्घाटनकर्ता-
- राजप्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह

प्रथम मुख्य न्यायाधीश-
- न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा (इलाहाबाद एवं उदयपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश)।
- उनके साथ 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली।

प्रारंभिक पीठ-
- जोधपुर प्रधान पीठ के अतिरिक्त जयपुर (कोटा क्षेत्राधिकार सहित) और उदयपुर में पीठें शुरू की गई।
- बाद में बीकानेर व कोटा में भी लंबित मामलों हेतु सुनवाई की अनुमति दी गई।

पीठों की समाप्ति-
- 8 मई, 1950 की अधिसूचना द्वारा 22 मई, 1950 से बीकानेर, कोटा और उदयपुर की पीठें समाप्त कर दी गई, केवल जयपुर पीठ को बनाए रखा गया।

4 राज्य पुनर्गठन एवं सत्यनारायण राव समिति-

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

1 नवंबर, 1956- पुनर्गठित
राजस्थान राज्य के लिए नया उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया।

प्रधान पीठ- जोधपुर

अस्थायी पीठ- जयपुर

पुनर्गठन के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश-
न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू

5 पी. सत्यनारायण राव समिति (1957 - 1958)

गठन- 11 जुलाई, 1957

सदस्य-
- पी. सत्यनारायण राव (अध्यक्ष)
- वी. विश्वनाथन
- बी.के. गुप्ता

सिफारिश (26 फरवरी, 1958)-
1. राजधानी जयपुर में ही रहे।
2. उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में बनी रहे।
3. जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया जाए।

परिणाम- वर्ष 1958 में जयपुर पीठ समाप्त कर दी गई।

6 जयपुर स्थायी पीठ की स्थापना (1976)-

आदेश-
"राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर में स्थायी बेंच की स्थापना) आदेश, 1976" (8 दिसंबर, 1976 को राष्ट्रपति द्वारा जारी)।

पुनः कार्य प्रारंभ-
31 जनवरी, 1977 से जयपुर पीठ ने स्थायी रूप से कार्य करना शुरू किया।

वर्तमान में स्वीकृत न्यायाधीश पद- 50



राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों में नए कुलगुरु (कुलपति) नियुक्त-

- 25 सितम्बर,2026 को राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने आदेश जारी करके राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों में नए कुलगुरु (कुलपति) नियुक्त किए।
- कार्यकाल की अवधि-पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो)।

नवनिर्वाचित कुलगुरु एवं विश्वविद्यालय-

विश्वविद्यालय का नाम	स्थान	नवनिकुलगुरु (कुलपति)
राजस्थान विश्वविद्यालय	जयपुर	डॉ. भगवती प्रसाद सारस्वत
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय	सीकर	डॉ. युद्धवीर सिंह
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय	बीकानेर	प्रो. नरसी राम विश्नोई

नगरीय निकाय आम चुनाव-2026

- राजस्थान राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन के अन्तर्गत नगरीय निकायों के चुनाव सम्पन्न कराये गये और पंचायती राज संस्थाओ के चुनाव करवाए जा रहे है।
- **राज्य के 309 नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों के करवाए गये-**
  - नगरनिगम-10
  - नगरपरिषद- 47
  - नगरपालिका- 252
- **सदस्य पद के लिए चुनाव कार्यक्रम-**
  - लोक सूचना जारी करने की तिथि- 27 अगस्त, 2026
  - मतदान की तिथि-
    - प्रथम चरण- 9 सितम्बर, 2026
    - द्वितीय चरण- 11 सितम्बर, 2026
  - मतगणना की तिथि- 14 सितम्बर, 2026
- **अध्यक्षीय पद के लिए चुनाव कार्यक्रम-**
  - लोक सूचना जारी करने की तिथि- 15 सितम्बर, 2026
  - मतदान की तिथि- 21 सितम्बर, 2026
  - मतगणना की तिथि- 21 सितम्बर, 2026
- **पंजीकृत मतदाताओं का विवरण-**
  - कुल मतदाता- 1,44,03,853
  - पुरुष- 73,98,415
  - महिला- 70,04,927
  - थर्ड जेंडर- 511
  - सबसे अधिक मतदाता- नगर निगम जयपुर में
  - सबसे कम मतदाता- नगरपालिका इन्द्रगढ में
- नोट- नगरीय निकाय आम चुनावों में दलबदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू नहीं होते है।

संबंधित नगर निगम के महापौर और राजनीतिक पार्टी-

क्र. सं.	नगर निगम	निर्वाचित महापौर का नाम	सम्बद्ध दल
1.	जयपुर नगर निगम	सुनील कोठारी	भारतीय जनता पार्टी
2.	जोधपुर नगर निगम	प्रसन्न चंद्र मेहता	भारतीय जनता पार्टी
3.	कोटा नगर निगम	अनुसुइया गोस्वामी	भारतीय जनता पार्टी
4.	अजमेर नगर निगम	अनामिका शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
5.	उदयपुर नगर निगम	पारस सिंघवी	भारतीय जनता पार्टी
6.	अलवर नगर निगम	सुमनलता अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
7.	पाली नगर निगम	नमिता बुबकिया	भारतीय जनता पार्टी
8.	भरतपुर नगर निगम	अनुराधा सिंह	भारतीय जनता पार्टी
9.	भीलवाड़ा नगर निगम	जसवंत कंवर	भारतीय जनता पार्टी
10.	बीकानेर नगर निगम	अनिल कल्ला	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

जियोन का 10 मेगावाट का बैटरी ऊर्जा भंडारण संयंत्र शुरू-

- जियोन ने राजस्थान के फलोदी में 10 मेगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजना चालू की है।
- इसको राज्य विद्युत प्रसारण निगम की जरूरतों के हिसाब से चालू किया गया है।

सीकर व अलवर में स्थापित होगी प्रदेश की पहली प्याज प्रोसेसिंग यूनिट-

- राज्य सरकार की 'एक जिला, एक उत्पाद' योजना के अंतर्गत राजस्थान की पहलीप्याज प्रोसेसिंग यूनिट्स सीकर (यालसर गांव, लक्ष्मणगढ़ तहसील) और अलवर जिले में स्थापित की जाएंगी।
- इन दोनों जिलों में 25-25 लाख रुपये की लागत वाले इन प्रोजेक्ट्स को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राडा रसेल-

- प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर त्वरित, प्रभावी कार्रवाई करने और अपराध के नए तरीकों पर गहन अनुसंधान (Research) करने के लिएजयपुर पुलिस रेंज में राडार सेल का गठन किया गया है।
- RADAR- Real Time Anti Cyber Crime Detection and Response
- **मुख्य कार्य व उद्देश्य-**
  - जयपुर रेंज के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में साइबर अपराध के विरुद्ध दैनिक आधार पर होने वाली कार्रवाई की मॉनिटरिंग करना।
  - साइबर ठगी एवं अपराध के नित-नए तरीकों और पैटर्नों पर अनुसंधान करना तथा उसके आधार पर जिला टीमों को त्वरित कार्रवाई हेतु टास्क सौंपना।
- नोडल अधिकारी-जिला स्तर पर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के साइबर थानों के थानाधिकारियों कोनोडल अधिकारीबनाया गया है।

भरतपुर-ब्यावर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे-

- प्रदेश में पूर्व से पश्चिमी राजस्थान के मध्य यात्रा समय को घटाने और आवागमन को तेज व सुगम बनाने के उद्देश्य सेभरतपुर-ब्यावर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वेके निर्माण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।
- कुल लंबाई- 277 किलोमीटर (4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस-वे)।
- अनुमानित कुल लागत- ₹8,656 करोड़
- वाहनों की अधिकतम गति सीमा- 120 किमी प्रति घंटा
- संबंधित जिले (6 जिले)-जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर
- प्रारंभिक व अंतिम बिंदु-जयपुर जिले के दूदू स्थित ग्राम झागसे शुरू होकर यह एनएच-21 पर भरतपुर के ऊंचा नगला तक जाएगा।

राजस्थान फिल्म फेस्टिवल-

- संस्करण-14वें संस्करण
- आयोजन तिथि- 26 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- दीप स्मृति आडिटोरियम, मानसरोवर (जयपुर)
- मंच संचालन- शर्मन जोशी और ईशा कोप्पिकर
- लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड-ममता कुलकर्णी
- राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स- रीजनल सिनेमा कैटेगरी

कैटेगरी	विजेता
बेस्ट डायरेक्टर	अनिंदम सील
बेस्ट राइटर	अखिल अनिल कुमर और अप्पु असलम
बेस्ट सिनेमैटोग्राफर	सौगंध एसयू
बेस्ट एक्टर मेल	जिम्मी शेरगिल
बेस्ट एक्टर फीमेल	रिंकु राजगुरु
बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर	सुनील
बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर	मानव विज
म्यूजिक डायरेक्टर	केदार और मिस्टर भार्गव
सिंगर मेल	सुहास सावंत
सिंगर फीमेल	जयति चक्रवर्ती
लिरिक्स राइटर	मुथु
बेस्ट मूवी	कोरपुर

- **राजस्थान फिल्म कैटेगरी के अवॉर्ड-**

कैटेगरी	विजेता
बेस्ट डायरेक्टर	डक्सिन छाहरा
बेस्ट राइटर	सोनू रनदीप चौधरी
बेस्ट सिनेमैटोग्राफर	वीरधावल पुरानिक
बेस्ट एक्टर मेल	आशीष शर्मा
बेस्ट एक्टर फीमेल	निशा शर्मा
बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर	नगेन्द्र सिंह
बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर	निर्मल चिरानिया
म्यूजिक डायरेक्टर	गाजी खान
सिंगर मेल	मोती खान
सिंगर फीमेल	मोनिका भारद्वाज
लिरिक्स राइटर	जीत
बेस्ट मूवी	ओमलो

राजस्थान के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को 'ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम' के सफल क्रियान्वयन के लिए गोल्ड स्कॉच अवार्ड-

- पुरस्कार की श्रेणी- ई-गवर्नेंस एवं सुशासन
- पुरस्कार प्रदाता- स्कॉच फाउंडेशन (109वां सम्मिट)
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- सम्मानित विभाग- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (राजस्थान सरकार)।
- पुरस्कार का कारण- ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के विकास एवं उसके सफल क्रियान्वयन हेतु।
- ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम- भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन तथा परिणाम-उन्मुख लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग के मार्गदर्शन में यह सॉफ्टवेयर विकसित किया गया।

राजस्थान की दो नवाचारी शैक्षिक पहलों को स्कॉच पुरस्कार-

- नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित 110वें स्कॉच शिखर सम्मेलनमें राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की दो अभिनव पहलों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पहल निम्न है-
- **खुशीशाला खुद की खोज-**
  - यह विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण।
  - **मुख्य उद्देश्य-**
    - स्कूली विद्यार्थियों में आत्म-जागरूकता, करुणा और मानसिक संबल को बढ़ावा देना।
    - कक्षाओं में सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना।
- **एआई आधारित दक्षता आकलन-**
  - केंद्रित क्षेत्र-तकनीक आधारित आधुनिक शिक्षण एवं मूल्यांकन।
  - **मुख्य उद्देश्य-**
    - कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति का सटीक आकलन करना।
    - कमजोरियों की पहचान कर आवश्यकतानुसार लक्षित सुधारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाना।

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के कार्यकाल का विस्तार-

- राज्य सरकार ने 'राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग' का कार्यकाल बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 तक कर दिया है।
- **आयोग की संरचना (5-सदस्यीय)-**
  - अध्यक्ष-मदन लाल भाटी (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विख्यात विधिवेत्ता)
  - सदस्य-मोहन मोरवाल, प्रो. राजीव सक्सैना, एडवोकेट श्री गोपाल कृष्णा, पवन मंडाविया
- राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 09 मई,2025 को इस आयोग का गठन किया गया था।
- आयोग ने 5 अगस्त,2026 को निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़ी अपनी विस्तृत रिपोर्ट एवं सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपी थीं।

'आदिपराग' वाइल्ड फॉरेस्ट हनी लाँच-

- 26 सितंबर, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'वनगिरि' के प्रथम शहद उत्पाद 'आदिपराग' को किया लाँच किया।
- नोडल संस्था-राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड (राजससंघ)
- ब्रांड का नाम- 'वनगिरि'
- उद्देश्य- जनजातीय क्षेत्रों की लघु वन उपज के संग्रहण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देना।

पीएमएफबीवाई के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर चतुर्थ स्थान-



- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है।
- भारत सरकार द्वारा राज्यों के योजना-विशिष्ट 10 प्रदर्शन मापदण्डों के आधार पर जारी राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान ने 43.5 अंकप्राप्त कर देश मेंचौथा स्थान हासिल किया है।
- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य-**
  - असम (55.5 अंक) - प्रथम
  - उत्तर प्रदेश (47.5 अंक) - द्वितीय
  - राजस्थान (43.5 अंक) - चतुर्थ स्थान (उत्तराखंड, हरियाणा, पुडुचेरी और महाराष्ट्र से आगे)
- फसल कटाई प्रयोगों को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रिकॉर्ड करने में राजस्थान को 10 में से 10 अंकमिले। राज्य में लगभग 90% फसल कटाई प्रयोग ऐप से ऑनलाइनकिए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक है।
- येसटेक (YES-TECH) क्रियान्वयन-तकनीक आधारित उपज आंकलन हेतु 90% से अधिक जिलों में येसटेक अपनाने के मापदण्ड पर राजस्थान को पूरे 10 अंक प्राप्त हुए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-

- प्रारम्भ- वर्ष 2016 में
- प्रीमियम दरें-
  - खरीफ फसलें- 2.0 प्रतिशत
  - रबी फसलें- 1.5 प्रतिशत
  - वाणिज्यिक/बागवानी फसलें- 5.0 प्रतिशत
- विशेष सब्सिडी-पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए प्रीमियम पर सरकार द्वारा विशेष/पूर्ण सब्सिडी दी जाती है।
- यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा देती है।
- इसमें प्रीमियम का भार किसान, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वहन करते हैं।

सुर्खियों में- ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना-

- यह परियोजना मुख्य रूप सेदौसाऔरसवाई माधोपुरजिलों तथा इनके आसपास के क्षेत्रों को दीर्घकालीन और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्मित की जा रही है।
- कुल स्वीकृत लागत-लगभग ₹3,588 करोड़।
- **परियोजना का मुख्य लक्ष्य-**
  - 1,256 गांवोंऔर 6 कस्बोंको पेयजल नेटवर्क से जोड़ना।
  - 3,06,198 से अधिकघरेलू जल कनेक्शन देना।
  - लगभग 35 लाख की आबादीको गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।
- **225 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट-**
  - परियोजना के तहत 225 एमएलडी क्षमता का विशाल जल शोधन संयंत्र निर्मित।
- **मुख्य ट्रांसमिशन लाइन (प्रथम पैकेज)-**
  - ईसरदा इंटेक वेल से महुआ तक कुल 341 किमीमुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन प्रस्तावित है।

राजस्थान ने डिजिटल कृषि एवं एग्रीस्टैक के क्रियान्वयन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की-

- राजस्थान ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है।
- राजस्थान ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित 90.19 लाख किसान आईडीके लक्ष्य को शत-प्रतिशत (100%) प्राप्त कर लिया है।
  - राजस्थान 100 प्रतिशत किसान आईडी का लक्ष्य हासिल करने वाला उत्तर भारत का पहला तथा देश का छठा राज्य बन गया है।
- वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राज्य में 76.54 लाख ऑपरेशनल होल्डिंग हैं। इसके मुकाबले किसान आईडी की उपलब्धि लगभग 118 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिसके आधार पर राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
- **पीएम-किसान एवं क्षेत्र कवरेज-**
  - प्रदेश के लगभग 50 लाख पीएम-किसान लाभार्थियोंको किसान आईडी से जोड़ा जा चुका है।राज्य के कुल बोए गए कृषि क्षेत्र कालगभग 62 प्रतिशत हिस्साकिसान आईडी के अंतर्गत कवर हो चुका है।
  - राज्य के लगभग 99 प्रतिशत गांवोंका जियो-रेफरेंसिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- **एग्रीस्टैक एवं एग्रीस्टैक आयुक्तालय-**
  - एग्रीस्टैकभारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है।
  - जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों, उनकी कृषि भूमि और फसलों के सत्यापित डेटा को एकीकृत कर सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और लक्षित बनाना है।
  - राज्य के कृषि विभाग के अंतर्गतएग्रीस्टैक आयुक्तालय की स्थापना की गई है।कृषि आयुक्तको एग्रीस्टैक आयुक्तालय के आयुक्त के रूप में नामांकित किया गया है।

राजस्थान के ग्रामीण विकास, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि एवं युवा कल्याणको लेकर निर्णय/घोषणा-

- 2 सितम्बर, 2026 को मुख्यमंत्री ने राजस्थान के ग्रामीण विकास, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि एवं युवा कल्याण को लेकर प्रमुख निर्णय/घोषणाएं की।
- **निर्णय/घोषणाएं**

विकास का क्षेत्र	मुख्य निर्णय एवं स्वीकृत योजनाएं
डिजिटल सशक्तीकरण एवं शिक्षा	❑ प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केन्द्रस्थापित होंगे। ❑ इन केंद्रों पर आधुनिक लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर मार्गदर्शन और सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलेगी।
सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी	❑ PMGSY चतुर्थ चरण-प्रदेश के गांवों में कुल 3,219 किलोमीटरलंबी सड़कें बनेंगी (1,500 किमी सड़कें 2026-27 तक पूरी होंगी)। ❑ अटल प्रगति पथ योजना- 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाई जा रही हैं। ❑ स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों तक कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाएगी।

कृषि एवं जल संरक्षण	❑ फार्म पौण्ड व डिग्गी-खेतों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 18,000 फार्म पौण्डऔर 8,000 डिग्गियोंका निर्माण किया जाएगा। ❑ कृषि यंत्र अनुदान-इस वर्ष 50,000 कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी (अनुदान) दी जाएगी। ❑ तारबंदी योजना-फसलों को आवारा व जंगली जानवरों से बचाने के लिए 200 लाख मीटर तारबंदी हेतु अनुदान दिया जाएगा।
युवा कल्याण एवं अन्य योजनाएं	❑ खेल मैदान-ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण होगा। ❑ वीबी-जी राम जी योजना-गांवों के सर्वांगीण एवं सुनियोजित विकास के लिए राजस्थान मॉडल विकसित किया जाएगा।

राजस्थान के 29 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 'स्मार्ट क्लासरूम' व 'कंप्यूटर लैब' की स्थापना-

- 15 सितंबर,2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने राजस्थान के 11 जिलों में 29 कार्यरत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में एकीकृत कंप्यूटर लैब-सह-स्मार्ट क्लासरूम सुविधाओं की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापनपर हस्ताक्षर किए हैं।
- परियोजना का कुल बजट-₹16.01 करोड़ (HPCL बोर्ड द्वारा CSR मद के तहत स्वीकृत)
- लाभार्थी जिले- अलवर, बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर।

चिंतन- एक दशक की पहल

- 6 सितंबर, 2026 को राज्य में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 लागू होने के दस वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम 'चिंतन-एक दशक की पहल' का आयोजन किया जाएगा।
- **कार्यक्रम-** चिंतन- एक दशक की पहल (राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम)
  - ❑ आयोजन तिथि- 6 सितंबर, 2026
  - ❑ आयोजन स्थल- राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
  - ❑ आयोजक- राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति एवं पोक्सो समिति के तत्वावधान में।
  - ❑ सहयोगी संस्थाएं- राजस्थान उच्च न्यायालय, बाल अधिकारिता विभाग तथा यूनिसेफ।
  - ❑ उपलक्ष्य- राज्य में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू होने के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में।
- **मुख्य उद्देश्य-**
  - बच्चों (दिव्यांग बच्चों सहित) की सुरक्षा, देखरेख, पुनर्वास और न्याय सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुधारों पर चर्चा करना।
  - मिशन वात्सल्य योजनाके पहलुओं, कानूनी सहायता, गवाहों की सुरक्षा, संस्थाओं के समन्वय तथा बच्चों के पुनर्वास पर विमर्श करना।
- इसमें पाँच तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया।

33वें मथुरादास माथुर अवॉर्ड-



- राजस्थान के घरेलू क्रिकेट में वर्ष 2025-26 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीन खिलाड़ियों को राज्य के प्रतिष्ठितमथुरादास माथुर अवॉर्ड के लिए चुना गया है।
- पुरस्कार संस्करण- 33वां
- **वर्ष 2025-26 के पुरस्कार विजेता-**

सीनियर वर्ग	अशोक शर्मा (जयपुर)	गेंदबाज
जूनियर वर्ग	कुशाग्र ओझा (भीलवाड़ा)	बाएं हाथ के ऑलराउंडर
सब-जूनियर वर्ग-	शिफान खान (जयपुर)	दाएं हाथ के बल्लेबाज

- विशेष सम्मान-भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में टेस्ट डेब्यू करने के उपलक्ष्य में राजस्थान के खिलाड़ी मानव सुथार को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

भारत ओडीओपी संगम 2026 में राजस्थान के जिला-विशिष्ट उत्पादों का राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन-

- भारत ओडीओपी संगम 2026 में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान के समन्वय से प्रदेश के विभिन्न जिलों के 38 चयनित ओडीओपी उद्यम एवं कारीगरसंगम में भाग लेंगे।
- ओडीओपी संगम 2026 में भाग लेने इन ओडीओपी एमएसएमई को राजस्थान ओडीओपी नीति-2024 के तहत अनुदान राशि भी उपलब्ध करवाई जायेगी-
  - ❑ किराया अनुदान- स्टॉल किराये का 75 प्रतिशत अथवा 50 हजार रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपये तक प्रति आयोजन अनुदान।
  - ❑ प्रतिनिधि अनुदान- दो प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित यात्रा सहायता अनुदान।

राजस्थान एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) नीति 2024-

- 8 दिसंबर 2024 को घोषित।
- उद्देश्य- प्रत्येक जिले के निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना और जिलों को संभावित निर्यात केंद्र बनाना।
- मुख्य उपाय- नए उद्यमों को वित्तीय सहायता, तकनीकी अपनाने, गुणवत्ता प्रमाणन, नवीकरणीय ऊर्जा पहल, अवसंरचना विकास, विपणन सहायता और ई-कॉमर्स को बढ़ावा।
- ओडीओपी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- लक्ष्य- मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना।
- **एक जिला एक उत्पाद सूची-**

क्र. सं.	जिला	ODOP उत्पाद का नाम
1	अजमेर	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
2	अलवर	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
3	बालोतरा	वस्त्र उत्पाद
4	बांसवाड़ा	मार्बल उत्पाद
5	बारां	लहसुन उत्पाद
6	बाड़मेर	कशीदाकारी
7	ब्यावर	क्वार्ट्ज एवं फेल्स्पार पाउडर
8	भरतपुर	कृषि आधारित उत्पाद
9	भीलवाड़ा	वस्त्र उत्पाद
10	बीकानेर	बीकानेरी नमकीन
11	बूंदी	सैंडस्टोन
12	चित्तौड़गढ़	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
13	चूरू	लकड़ी के उत्पाद
14	दौसा	पत्थर आधारित उत्पाद
15	डीडवाना–कुचामन	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद
16	डीग	पत्थर आधारित उत्पाद
17	धौलपुर	पत्थर आधारित उत्पाद
18	डूंगरपुर	मार्बल उत्पाद
19	हनुमानगढ़	कृषि आधारित उत्पाद
20	जयपुर	रत्न एवं आभूषण
21	जैसलमेर	येलो स्टोन उत्पाद
22	जालोर	ग्रेनाइट उत्पाद
23	झालावाड़	कोटा स्टोन उत्पाद
24	झुंझुनूं	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद
25	जोधपुर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
26	टोंक	सैंडस्टोन उत्पाद
27	खैरथल–तिजारा	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
28	कोटा	कोटा डोरिया
29	कोटपूतली–बहरोड़	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
30	नागौर	पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण
31	पाली	वस्त्र उत्पाद
32	फलौदी	सोनामुखी उत्पाद
33	प्रतापगढ़	थेवा आभूषण
34	राजसमंद	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
35	सलूम्बर	क्वार्ट्ज
36	सवाई माधोपुर	मार्बल उत्पाद
37	सीकर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
38	सिरोही	मार्बल उत्पाद
39	श्रीगंगानगर	सरसों का तेल
40	टोंक	स्लेट स्टोन उत्पाद
41	उदयपुर	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद

- **भारत ओडीओपी संगम 2026-**
  - आयोजन तिथि- 7 से 11 अक्टूबर, 2026
  - आयोजन स्थल- भारत मंडपम, नई दिल्ली
  - आयोजक- उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार
  - उद्देश्य- देशभर केएक जिला एक उत्पाद उत्पादों की पहचान, बाजार पहुंच और दृश्यता को मजबूत करना।
  - यह राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी-सह-विक्रय कार्यक्रमहै जिसमें विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की 600 से अधिक इकाइयों एवं प्रदर्शकों की भागीदारी प्रस्तावित है।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026-

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026' के परिणाम जारी किए गए हैं।
- **राजस्थान के शहरों की श्रेणीवार रैंकिंग-**
  - श्रेणी-I (10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर)-
    - 20th - जयपुर (174 अंक)
    - 24th - जोधपुर (163.2)
    - 37th- कोटा (146.3)
  - श्रेणी-II (3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर)-
    - 6th -अलवर (192)
    - 8th- उदयपुर (187.5)

बावल-बहरोड़ आरआरटीएस की पूरक विस्तृत परियोजना की समीक्षा-

- 2 सितम्बर, 2026 को नमो भारत रेल कॉरिडोर के तहत दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के बावल से बहरोड़ खंड के लिए श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में पूरक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर बैठक आयोजित हुई।



मिशन कर्मयोगी रैंकिंग में राजस्थान शीर्ष स्थान पर-

- मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता निर्माण एवं लर्निंग आउटकम पर आधारित नवीनतम रैंकिंग में राजस्थान ने 62.49 के कम्पोजिट स्कोर के साथ राज्य श्रेणी 'C' (जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य) में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- यह राजस्थान के लिए लगातार दूसरे माह प्रथम स्थान की उपलब्धि है।
- **मिशन कर्मयोगी-**
  - लाँच- वर्ष 2021 में
  - उद्देश्य- सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण और अधिकारियों के पेशेवर विकास को सुनिश्चित करना।
  - यह 'राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम' का एक हिस्सा है, जिसे सिविल सेवाओं में पेशेवर विकास और क्षमता निर्माण के लिए शुरू किया गया है।

किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना के लिए समझौता-

- 15 सितंबर, 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना के लिए एमओयू हस्ताक्षरित हुआ।
- 15,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिएनिम्न लोगों ने हस्ताक्षर किए-
  - **केन्द्रीय प्रतिनिधत्व-** श्री सी.आर. पाटिल (केंद्रीय जल शक्ति मंत्री)
  - **राज्य प्रतिनिधत्व- संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री)-** भजन लाल शर्मा (राजस्थान), सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश), पुष्कर सिंह धामी (उत्तराखंड), योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), नायब सिंह सैनी (हरियाणा),रेखा गुप्ता (दिल्ली)
- **किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना-**
  - अवस्थित- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर
  - संबंधित नदी- टोंस नदी (यमुना नदी की सहायक नदी)
  - बांध का प्रकार- रोलर-कम्पैक्टेड कंक्रीट (RCC) ग्रेविटी डैम
  - बांध की ऊंचाई- 232.6 मीटर
  - कुल जलाशय क्षमता- 1,824 मिलियन घन मीटर
  - उपयोगी जल भंडारण- 1,561.91 मिलियन घन मीटर
  - कुल जल लाभ- 1,324 मिलियन घन मीटर

- बिजली उत्पादन क्षमता- 422 मेगावाट (105.5 मेगावाट की 4 टर्बाइन)
- सिंचाई/कृषि कमांड एरिया- करीब 1.02 लाख हेक्टेयर
- पानी का मुख्य उपयोग-सिंचाई, पेयजलऔर बिजली उत्पादन में
- कुल परियोजना लागत- करीब ₹14,037 करोड़
- परियोजना क्षेत्र- करीब 3,000 हेक्टेयर, जबकि करीब 2,950 हेक्टेयर डूब क्षेत्र दर्ज है।

- **पानी का वितरण (1,324 MCM में से) -**

राज्य	पेयजल एवं औद्योगिक जल आवंटन
हरियाणा	633 MCM
उत्तर प्रदेश	411 MCM
राजस्थान	124 MCM
दिल्ली	80 MCM
उत्तराखंड	34 MCM
हिमाचल प्रदेश	42MCM

- **किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड-**
  - परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 'किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड' का गठन किया गया था।
  - हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिव दो-दो साल के अंतराल पर इसके अध्यक्ष बनते हैं।
- इस परियोजना में जल घटक की कुल लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में वहन करेगी, बाकी 10 प्रतिशत लागत छह राज्यों के बीच साझा की जाएगी।

राजस्थान में तीन निजी औद्योगिक पार्क के लिए भूमि आवंटित-

- राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 (मॉडल-ए) के तहत राज्य में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 552 एकड़ भूमि आवंटित की गयी।
- **भूमि आवंटन और प्रमुख स्थल-**
  - कुल आवंटित भूमि- कुल 552 एकड़ भूमि।
  - **चयनित स्थान-**
    - दौसा- राजाहेड़ा, गुड़ा आशीकपुरा और नूरपुर
    - बालोतरा- वेदरलाई
    - धौलपुर- बिजौली

रीको भूमि नियमों में संशोधन-

- हाल ही में रीको नेरीको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स, 1979 केनियम 21 एवंनियम 3(एजे) में आंशिक संशोधन किया है।
- संशोधन- किसी उद्यमी को अविकसित औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आवंटित होता है, तो उसे वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की समय-सीमा में राहत मिलेगी।
- **संशोधित समय-सीमा के प्रावधान-**
  - **पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना वाली परियोजनाएं-** भूखण्ड आवंटन की तिथि से 2 वर्षकी अवधि अथवा क्षेत्र के विकसित घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि, जो भी बाद में हो।
  - **पर्यावरणीय स्वीकृति वाली परियोजनाएं-** भूखण्ड आवंटन की तिथि से 3 वर्षकी अवधि अथवा क्षेत्र के विकसित घोषित होने की तिथि से 1 वर्षकी अवधि, जो भी बाद में हो।
  - ये प्रावधान प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के लागू होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
- **उद्देश्य-**राज्य में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मजबूती देना, उद्यमियों को व्यावहारिक राहत प्रदान करना तथा परियोजनाओं को धरातल पर उतारकर औद्योगिक विकास और रोजगार को गति देना।

अटल भूजल योजना की लंबित देनदारियों का भुगतान-

- राजस्थान सरकार द्वाराअटल भूजल योजनाके तहत किसानों की लंबित सब्सिडी राशि (156 करोड़ रूपये) के भुगतान किये जाने की घोषणा की है।
- केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर,2025 के बाद योजना का क्रियान्वयन न किए जाने के कारण किसानों की कुल 158 करोड़ रुपयेकी सब्सिडी राशि बकाया रह गई थी।
  - कृषि विभाग- 90.91 करोड़ रुपये
  - उद्यानिकी विभाग- 66.16 करोड़ रुपये
- केंद्र सरकार द्वारा अनुदान देने में असमर्थता जताने के बादराज्य सरकार ने इस देनदारी का भुगतान करने का फैसला किया है। इस भुगतान के लिए बजटराज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से स्वीकृत किया जायेगा है।

- **अटल भूजल योजना-**
  - केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से राज्य के 17 जिलों में यह योजना संचालित थी।
  - इसके तहत फार्म पौंड, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी, कृषि यंत्र, फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप आदि के निर्माण पर सब्सिडी दी जाती थी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 'PAVITRA' तकनीक का आयोजन एवं प्रदर्शन-

- आयोजन तिथि- 18 सितम्बर, 2026, आयोजन स्थल- जयपुर (राजस्थान)
- आयोजक- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे।

- **PAVITRA क्या है?-**
  - PAVITRA भारत के लिए विकसित एकवैज्ञानिक एवं डेटा-आधारित निर्णय-सहायक मंच है।
  - यह विभिन्न नीतिगत और नियंत्रण उपायों के आधार पर उत्सर्जन में संभावित कमी तथा वायु में सूक्ष्म कण PM-2.5 की सांद्रता में होने वाले परिवर्तनों का वैज्ञानिक आकलन करता है।

- इसका उपयोग आधारभूत मूल्यांकन, कार्ययोजनाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारण, संभावित परिस्थितियों के आधार पर योजना निर्माण और कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग के लिए किया जाता है।

प्रदेश में फैटी लिवर की व्यापक स्क्रीनिंग और 'मिशन लिवर स्माइल'-

- **19** सितम्बर, 2026 कोफैटी लिवर की स्क्रीनिंग, उपचार एवं आगे की कार्ययोजना हेतु स्वास्थ्य भवन, जयपुर में उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।
- 'मिशन लिवर स्माइल' एवं स्वास्थ्य व्यवस्था-
  - राजस्थान में गैर-संचारी रोग व्यवस्था के तहत फैटी लिवर की व्यवस्थित स्क्रीनिंग को शामिल किया गया है।
  - लिवर स्माइल क्लीनिक- प्रदेश के सभी 63 जिला अस्पतालोंमें लिवर स्माइल क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं। ये क्लीनिक प्रत्येकमंगलवार और शुक्रवारको संचालित होते हैं।
- **स्कूलों में 'डब्ल्यू जोन'-**
  - प्रदेश के सभी स्कूलों में 'डब्ल्यू जोन' बनाए जाएंगे।
  - इनमें विद्यार्थियों केवजन, ऊंचाई और कमर की नाप की जाएगी।
- **'मिशन ओवी लॉस'-**
  - मोटापे को नियंत्रित करने के लिए 'ईट राइट कैंपेन' के अंतर्गत 'मिशन ओवी लॉस' चलाया जाएगा।
  - इसका मुख्य फोकस स्वस्थ खान-पान और बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देने पर है।
- Note- राजस्थान में फैटी लिवर की स्क्रीनिंग में देश में प्रथम स्थान परहै।

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राज्य में 2 बिलियन डॉलरकी परियोजनाओं में सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की-

- 7 सितंबर, 2026 को मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास से एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने शिष्टाचार भेंट की।
- **निवेश एवं वित्तीय प्रतिबद्धता-** राजस्थान के साथ आगामी 5 वर्षों में दीर्घकालिक साझेदारी के तहत**लगभग 2 बिलियन डॉलर**की परियोजनाओं में सहयोग देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- एडीबी द्वारा वित्त-पोषितजयपुर मेट्रो, राजस्थान अर्बन लाइवेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्टऔर PRITHWI परियोजना के लिए सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है।
- सहयोग के नए क्षेत्र-एडीबी ने राज्य में सिंचाई, नवीकरणीय ऊर्जा और एसेट मोनेटाइजेशनजैसे नए क्षेत्रों में परियोजनाओं को विकसित करने की बात उल्लेखित की है।

राजस्थान संपर्क (181) ई-जनसुनवाई पहलः मुख्य बिंदु-

- 9 सितंबर, 2026 को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन को और अधिक मजबूत करने के लिये अब ई-जनसुनवाई प्रक्रिया को लाँच किया गया है।
- इस पहल की शुरूआत जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन (181) पहुंचकर की।
- ई-जनसुनवाई के माध्यम से परिवादियों से वीडियो कॉल के जरिए सीधी बात कर उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सकेगा।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड पोर्टल-** शिकायतों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, डेटा विश्लेषण और प्राथमिकता आधारित कार्रवाई के लिए संपर्क पोर्टल को एआई सक्षम बनाया जा रहा है। इससे समस्याओं के निस्तारण की गति, गुणवत्ता और आमजन के संतुष्टि स्तर में सुधार होगा।

अभय कुमार "विकसित भारत-जन सेवा अभियान" के राज्य समन्वयक नियुक्त

- प्रदेश में "विकसित भारत-जन सेवा अभियान"के लिए जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार को राज्य समन्वयक नियुक्त किया गया है।
- यह राज्य में इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध संचालन, निगरानी तथा विभिन्न विभागों और जिलों से समन्वय व मार्गदर्शन की मोनिटरिंग करेंगे।
- विकसित भारत-जन सेवा अभियान-
- आयोजन-17 सितम्बर से 17 अक्टूबर,2026
  - उद्देश्य- विद्यार्थियों एवं आमजन में जनसेवा, जागरूकता, सामाजिक सहभागिता तथा जिम्मेदार नागरिकता की भावना को बढ़ावा देना है।
  - इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न जन-जागरूकता एवं सेवा गतिविधियों के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को जनभागीदारी से साकार किया जाएगा।

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति का राजस्थान दौरा

- 22-23 सितम्बर, 2026 को सांसद (लोकसभा) भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने दो दिवसीय राजस्थान दौरा किया।
- इस दौरान समिति ने राजस्थान में आकांक्षी जिला कार्यक्रम एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा विभिन्न विकास संकेतकों की प्रगति पर चर्चा की।

आचार्य श्री तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार-2026-

- 23 सितम्बर,2026 को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को जैन विश्व भारती में आयोजित आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार समारोह में वर्ष 2026 का आचार्य श्री तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया।
- यह पुरस्कार उन्हें नारी जागरण, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक उत्थान एवं जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं बहुआयामी योगदान के लिए आचार्य श्री महाश्रमण के सान्निध्य में प्रदान किया गया।

आंगन मिलन सेवा-

- विकसित भारत जन सेवा अभियान के अंतर्गत 25 से 27 सितम्बर,2026 तक निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान द्वारा प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 'आंगन मिलन सेवा' का आयोजन किया गया है।
- इसमें पोषण एवं स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी, नवीन लाभार्थियों का पंजीकरण, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में पंजीकरण, गोदभराई, अन्नप्राशन, लाभार्थी संवाद एवं अनुभव साझाकरण, पोषण थीम पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

'माय भारत' पोर्टल के संबंध में समीक्षा बैठक-

- 9 सितंबर, 2026 को मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के 'माय भारत' पोर्टल के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
- **राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की स्थिति-**
  - 'माय भारत' पोर्टल पर प्रदेश में अब तक 22,59,929 युवाओं का पंजीकरण हो चुका है, जो देश के कुल पंजीकरण का 8.25% है।
  - विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (VBYLD) 2027 की क्विज में राजस्थान के 60 हजार युवाभाग ले चुके हैं, जिससे राजस्थान देश भर में तीसरे स्थान पर है।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की समीक्षा बैठक-

- 2 सितम्बर, 2026 को प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएमएचए) की अध्यक्ष गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में एसएमएचए की दूसरी समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
- उद्देश्य- प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, आत्महत्या की रोकथाम, और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की निगरानी व पंजीकरण व्यवस्था को बेहतर बनाना।
- **प्रमुख निर्णय-**
  - संभाग स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड्स गठन के प्रस्ताव विचार-विमर्श।
  - नशा मुक्ति केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की श्रेणी में शामिल कर, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत उनका पंजीकरण शुरू किया जाएगा।
  - **अभियान-** 10 सितंबर (विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस) से 10 अक्टूबर (विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस) तकविशेष जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

महोत्सव/सम्मेलन/अभियान/आपरेशन

9वां राष्ट्रीय पोषण माह-

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह जन-आंदोलन के रूप में मनाया जा रहा है।
- संस्करण- 9वां
- आयोजन अवधि- 9 सितंबर से 8 अक्टूबर,2026 तक
- राष्ट्रीय शुभारंभ- 9 सितंबर 2026 को वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में।
- उद्देश्य-आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, देखभाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए सुदृढ़ करना तथा सामुदायिक स्वामित्व विकसित करना।
- विषय- "हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी"
- **प्रमुख उप-विषय- इसके 5 प्रमुख उप-विषय है-**
  1. आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन।
  2. आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा एवं गर्म पका हुआ भोजन।
  3. सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही।
  4. बाल्यावस्था विकास हेतु पोषण एवं प्रारंभिक उद्दीपन।
  5. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-मातृ स्वास्थ्य हेतु नकद हस्तांतरण।

समयसामयिकी स्मरणीय तथ्य-

प्रदेश में कृषि-प्रसंस्करण अवसंरचना की वर्तमान स्थिति-

- राजस्थान फूड पार्क डेवलपमेंट पॉलिसी-2026-इसके तहत 39 फूड पार्क प्रस्तावित हैं, जिनमें से 35 स्थानों पर भूमि आवंटित हो चुकी है।
- मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर- 2 मेगा फूड पार्क, 4 एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, 6 रीको/स्पाइस पार्क, 1,500 से अधिक एग्रो-प्रोसेसिंग इकाइयां तथा PMFME योजना समर्थित 1,850+ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां कार्यरत हैं।
- **10 प्रस्तावित एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स-** मूंग, सरसों, सोयाबीन, किन्नू, अनार, अमरूद, संतरा, इसबगोल, जीरा और लहसुन पर आधारित क्लस्टर्स का विकास।

'ऑक्टेव 2026' के अंतर्गत सात दिवसीय नॉर्थ-ईस्ट पेंटर्स कैंप-

- आयोजन तिथि- 28 सितंबर से प्रारंभ (सात दिवसीय)
- आयोजन स्थल-आरआईसी (राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर)
- आयोजक-पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर और केन्द्रीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के सहयोग से
- यह शिविर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 1 से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने जा रहे 'ऑक्टेव 2026' के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।

विशेष मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम जागरूकता अभियान-

- विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (10 सितंबर, 2026) से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (10 अक्टूबर,2026) तक प्रदेशभर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
- इस अभियान के तहत मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम का संदेश देने के लिए रैलियां, कार्यशालाएं, क्विज, पोस्टर व निबंध प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियानों का आयोजन किया जा रहा है।

प्रवासी राजस्थानी मीट-

- 15 सितम्बर, 2026 को राजस्थान सरकार द्वारा भुवनेश्वर, ओड़िशा में प्रवासी राजस्थानी मीट कासफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- **उद्देश्य-**
  - प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव को सशक्त बनाना।
  - राज्य में निवेश एवं साझेदारी के नए अवसरों को प्रोत्साहित करना।
- इस आयोजन के माध्यम से देश एवं विदेश में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ा गया।
- राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल ने किया। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है।

हरियालो राजस्थान अभियान-

- प्रदेशमें 'हरियालो राजस्थान अभियान' के तहत वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही सफलतापूर्वक पूर्णकर लिया गया है।
- **हरियालो राजस्थान मिशन-**
  - नरेन्द्र मोदी जी के 'एक पेड़ माँ के नाम' से प्रेरित मिशन
  - शुरुआत- 7 अगस्त 2024 (जाहोता - दूदू जिला - जयपुर से)
  - विभाग-वन विभाग, राजस्थान सरकार।
  - लक्ष्य-मिशन के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य।
  - (वर्तमान वर्ष में 10 करोड़पौधे लगाने का लक्ष्य)
  - **अन्य मुख्य बिन्दु-**
    - 2028 तक 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा।
    - ग्रीन बजट 2025-26 की अवधारणा से प्रेरित

18वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक-

- आयोजन तिथि- 18 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- शासन सचिवालय (जयपुर)
- अध्यक्षता-श्री वी. श्रीनिवास (मुख्य सचिव, राजस्थान)
- बैठक में प्रदेश के दूरदराज, जनजातीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों ('वाइब्रेंट विलेज') तक निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में रखा गया है।

'पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट-इंडियन स्टेट्स' पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-

- आयोजन तिथि-21-25 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- जयपुर (राजस्थान)
- आयोजक-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता केंद्र (SARTTAC - South Asia Regional Training and Technical Assistance Center)
- समारोह का उद्घाटन-मुख्य सचिवश्री वी. श्रीनिवासद्वारा किया गया।
- **उद्देश्य-**
  - सार्वजनिक निवेश का बेहतर प्रबंधन करना।
  - परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
  - सार्वजनिक निवेश से अधिकतम परिणाम प्राप्त कर आमजन और अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाना।
- **SARTTAC (South Asia Regional Training and Technical Assistance Center) संस्था-**
  - **स्थापना-** जनवरी,2017
  - **निदेशक-** श्री हेराल्ड फिंगर
  - **सदस्य देश-** भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका
  - SARTTAC अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दक्षिण एशिया के सदस्य देशों और विकास साझेदारों की एक सहयोगात्मक पहल है।
  - उद्देश्य- सदस्य देशों की संस्थागत एवं मानव संसाधन क्षमता को मजबूत करना है ताकि वे प्रभावी व्यापक आर्थिक एवं वित्तीय नीतियां तैयार कर उनका सफल क्रियान्वयन कर सकें।

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस- राज्य स्तरीय समारोह-

- संस्करण- 11वां
- आयोजन तिथि- 23 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल-कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर
- मुख्य विषय- 'स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद'
- आयोजक-आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार

एजुस्किल्स समिट-2026

- आयोजन तिथि- 23 सितम्बर,2026
- आयोजन स्थल- जयपुर (एक निजी होटल में)
- **उद्देश्य-**
  - शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से "विकसित भारत" के संकल्प को पूरा करना।
  - बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाना।
  - बच्चों की राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाना तथा युवाओं को नौकरी पाने वाले के बजाय 'नौकरी देने वाला' बनाना।

कॉनफेड की 41वीं वार्षिक साधारण सभा आयोजित-

- 30 सितम्बर, 2026 को सहकार भवन, जयपुर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफेड) की 41वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया।
- कॉनफेड की वित्तीय एवं व्यावसायिक गतिविधि- कॉनफेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 94,667.39 लाख रुपये का कुल व्यवसाय किया गया तथा संस्था ने 1,663 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड-

- स्थापना-मार्च,1967, मुख्यालय-जयपुर
- प्रशासनिक नियंत्रण एवं संबद्धता- सहकारिता विभाग
- यहराष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (NCCF) से संबद्ध राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था है।
- **प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य-**
  - राज्य में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक दैनिक उपभोग की वस्तुएं उचित व नियंत्रित दरों पर उपलब्ध कराना।
  - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,राजस्थान सरकार के समन्वय से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री के सुगम वितरण में सहयोग प्रदान करना।
  - उपभोक्ता जिला स्तर पर संचालित 'प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारों'को थोक आपूर्ति प्रदान करना तथा उनके नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना।
  - बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर हस्तक्षेप कर रियायती दरों पर सामग्री उपलब्ध कराकर मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

ग्लोबल नर्सिंग समिट 2026-

- आयोजन तिथि- 5-6 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर
- आयोजक– आरएच हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
- थीम- "ट्रांसफॉर्मिंग नर्सिंग: शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थकेयर थ्रू एआई, इनोवेशन, लीडरशिप, एंड सिमुलेशन-बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन"
- उद्देश्य- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार, नेतृत्व और सिमुलेशन-आधारित शिक्षा के माध्यम से नर्सिंग और स्वास्थ्य सेवा में बदलाव लाना एवं भविष्य को आकार देना।

चर्चित व्यक्ति/स्थान/अन्य

रामनिवास बाग-

- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामनिवास बाग में एक नवीन एवं आकर्षक चौपाटी विकसित की जायेगी।
- अनुमानित लागत- ₹637.50 लाख
- इस परिसर में दोनों ओर कुल 15 फूड ट्रककी व्यवस्था प्रस्तावित है, जहाँ नागरिकों को विविध व्यंजन एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे।

मोती लाल कुमावत-

- 30 सितम्बर, 2026 को कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल नेग्राम बिचून (तहसील मौजमाबाद) के प्रगतिशील कृषकश्री मोती लाल कुमावत को 'किसान ब्राण्ड एम्बेसेडर एवं ट्रेनर' नियुक्त किया है।
- यह राज्य में जैविक, परंपरागत एवं प्राकृतिक खेती के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देंगे।

नव्या शेखावत-

- मेजर नव्या शेखावत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एडीसी नियुक्त किया गया है। वह भारतीय थल सेना से इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। वह सीकर जिले के केरपुरा गांव की मूल निवासी है।

खनक उपाध्याय-

- बांसवाड़ा कीयुवा खनक उपाध्याय ने 11 से 17 सितंबर, 2026 को येकातेरिनबर्ग (रूस) में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

जस्टिस विनीत माथुर-

- हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशजस्टिस विनीत माथुर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वे वर्ष 2004 से 2014 तक भारत सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे।
- इससे पूर्व वर्ष 1995 से 2004 तक उन्होंने एडीशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेंडिंग कौंसल के रूप में भी कार्य किया।

सुधांश पंत-

- यह राजस्थान कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव है। इनको हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है।
- सुधांश पंत जनवरी,2024 से नवंबर,2025 तक राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं।

खेल/खेल व्यक्तित्व

नॉर्थ जोन शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप 2026-

- संस्करण- 45वां
- आयोजन तिथि- 2 से 9 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- ओसेस शूटिंग रेंज, जगतपुरा, जयपुर (राजस्थान)
- आयोजक- राजस्थान राइफल एसोसिएशन द्वारा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में
- **विजेता-**
  - स्कीट जुनियर मैन
    - स्वर्ण- अनन्त सिंह बुलर, पंजाब
  - स्कीट यूथ पुरुष-
    - स्वर्ण- अनन्त सिंह बुलर, पंजाब
    - कांस्य- अन्शदीप सिंह ढिल्लों, चण्डीगढ
  - स्कीट महिला-
    - कांस्य- अफरोज प्रीत कौर, पंजाब
  - स्कीट जुनियर महिला-
    - स्वर्ण- शिवांगी राठौड, राजस्थान
    - रजत- अम्बिकेश्वरी राठौड, राजस्थान
    - कांस्य- जहांन्वी सोनी, राजस्थान

सब-जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप-

- संस्करण- 51वीं सब-जूनियर एवं जूनियर
- आयोजन तिथि– 3 से 6 अक्टूबर, 2026
- आयोजन स्थल- अलंकार महिला पीजी महाविद्यालय, जयपुर
- आयोजक- जयपुर योग लीग (योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सहयोग से एवं योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में)
- **प्रमुख तथ्य-**
  - प्रतियोगिता में 29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 925 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
  - प्रतियोगिता में छह श्रेणियों (राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स, आर्टिस्टिक सोलो, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक योग, फ्री फ्लो योग, प्रोफेशनल वूमेन योग) में मुकाबले होंगे।
  - राष्ट्रीय योगासन स्पर्धा में 8 से 18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के पांच आयु वर्ग होंगे।

हॉकी राजस्थान के आम चुनाव-

- हाल ही में हॉकीराजस्थान की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत जारी इलेक्शन रुल्स एवं नियमों के अनुसार चुनाव हुए।
- **निर्वाचित-** अध्यक्ष- महिपाल सिंह
  - **उपाध्यक्ष-**
    - डॉ. आरती सिंह
    - मलकीत सिंह मान
    - मदन सिंह राठौड़
  - **महासचिव-** देवेंद्र सिंह शेखावत
  - **कोषाध्यक्ष-** रश्मि शुक्ला
  - **संयुक्त सचिव-**
    - अब्दुल रब नकवी
    - वर्षा कुमारी शर्मा
  - **कार्यकारिणी सदस्य-** अरुण कुमार सारस्वत, संपत कोठारी एवं लोकेश कुमार

स्नेहा लांबा-

- भीलवाड़ा (राजस्थान) में आयोजितनॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिपमें जयपुर की बैडमिंटन खिलाड़ीस्नेहा लांबाने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अंडर-19 बालिका एकल का खिताब (स्वर्ण पदक)अपने नाम किया।

सुरभि मिश्रा-

- यह जयपुर की निवासी है।
- इनको जापान के आइची-नागोया में आयोजित हो रहे 20वें एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वैश टीम का कोच नियुक्त किया गया है।
- वह भारतीय दल के कोचिंग स्टाफ में राजस्थान की एकमात्र सदस्य हैं।
- सुरभि मिश्रा वर्ष 2023हांगझोऊ एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम की कोच रही थीं।

जयराज और हारिस-

- यह जयपुर के निवासी है। यह भुवनेश्वर में आयोजित एशियन टेनिस फेडरेशन की अंडर-14 बालक एवं बालिका प्रतियोगिता में उपविजेता रहे।

सुरेन्द्र गुर्जर-

- यह राजस्थान ओलंपिक संघ के महासचिव है। इनकों एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एशियन गेम्स के लिए एथलेटिक्स पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
- एशियन गेम्स जापान के नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित हो रहे है।

पूजा राठौड़-

- राजस्थान के जोधपुर जिले के बारा खुर्द की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका के पद पर कार्यरतपूजा राठौड़अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघकी रेफरी बनी है। वह भारत की पहली (पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में) अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल रेफरी बनी है।

काजल शेखावत-

- यह जयपुर निवासी ताइक्वांडो खिलाड़ी है। हाल ही पुणे में आयोजित ताइक्वांडो कैडेट जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली काजल कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयनित हुई हैं।

राजेश शुक्ला-

- राजस्थान विश्वविद्यालय के तैराकी प्रशिक्षकराजेश शुक्ला का चयन एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए हुआ है। वे बेंगलुरु में 4 से 10 अक्टूबर, 2026 तक होने वाली प्रतियोगिता में वे 55-59 आयु वर्ग में 50 मीटर व 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में भारत और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे।

विविध तथ्य

- 3सितंबर, 2026 को प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (RIDCOR) की त्रैमासिक बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।
- काजरी मोठ-4, काजरी मोठ-5, काजरी मोठ-6 और काजरी मोठ-7 यह सभी मोठ की नवीन किस्में है।
- 21 सितंबर, 2026 कोकेंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज जयपुर में विश्व प्रकृति कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) वैश्विक संरक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- राजस्थान और रामबाग गोल्फ क्लब का प्रतिनिधित्व कर रहीं जयपुर शहर की गोल्फरओजस्विनी सारस्वतने मानेसर में अपना 14वां नेशनल टाइटलजीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
- हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी को पहली बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग- एशिया 2026 में एशिया में 1001-1100 रैंक बैंड मिला है, जबकि दक्षिण एशिया क्षेत्र में 330वीं रैंक हासिल हुई है।
- विजयराज कुमारी मेवाड़- यह मेवाड़ के राजपरिवार की सदस्य थी जिनका हाल ही में निधन हो गया।
- गूगल ने राजस्थान में 150 मेगावाटके सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी 'रिन्यू पावर' के साथ समझौता किया है।
- राजस्थान के युवा तेज गेंदबाज चेतन शर्मा और गणेश सुथार का चयन बीसीसीआई की शेष भारत अंडर-23 टीम में हुआ है।
- आमेर में देश का पहला रेरा से पंजीकृत लग्जरी रिसॉर्टबनाया जायेगा।
- राजस्थानविद्युत नियामक आयोग ने टेक्नोक्रेट राजकुमार शर्मा को विद्युत लोकपाल नियुक्त किया है।
- वेटरनरी विश्वविद्यालय, बीकानेर की वैज्ञानिक टीम ने ऊंटनी के दूध में प्रोटीन हाइड्रोलायटेट की जैव क्षमता बढ़ाने की तकनीक विकसित की है।
- राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा- राज्य सरकार ने राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र कच्छावाहा का कार्यकाल बढ़ा दिया है।
- हाल ही में किशनगढ़ के उदयपुर खुर्द औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार नें एक कंपनी को रक्षा एवं गोला-बारूद मैन्यूफेक्चरिंग के लिए 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना में लगभग 162 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और प्रत्यक्ष रोजगार के करीब 200 अवसर सृजित होने की संभावना है।
- जयपुर इंटरनेशनलएयरपोर्ट के टर्मिनल-2 परपर हुवाई यात्री खुद बैगेज टैग लगा सकेंगे।इसके साथ ही जयपुर एयरपोर्ट यह सुविधा शुरू करने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बन गया है।
- राजस्थानहाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल ने न्यायाधीश अरुण मोंगा को राजस्थान हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जोधपुर तथा न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह को राजस्थान हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जयपुर का अध्यक्ष नामित किया गया है।
- मुख्य सचिवों के 5वें सम्मेलन में तय 28 आर्थिक, नियामक एवं प्रक्रियात्मक सुधारोंमें से राजस्थान 22 प्राथमिकताएं पूर्णकर चुका है। 22 प्राथमिकताओं को पूरा करने के साथ राजस्थान इन सुधारों के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी राज्यबना है।
- 23 सितम्बर, 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में एस्केप चैनल निर्माण के लिए 785 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है।
- 24 सितम्बर, 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की 9वीं बैठक आयोजित हुई।
- केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र,उदयपुर द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 1 से 4 अक्टूबर तक 'ऑक्टेव 2026' आयोजन किया जायेगा।

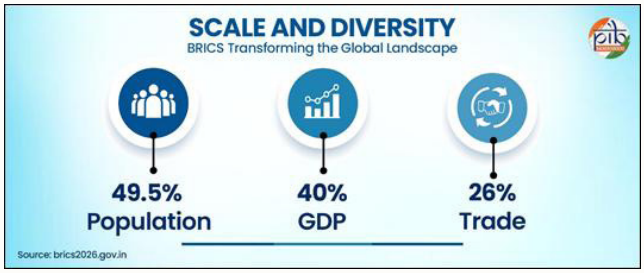
अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026

- संस्करण- 18वें
- आयोजन तिथि- 12-13 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- भारत मंडपम, नई दिल्ली
- अध्यक्षता और मेजबानी- भारत
- विषय- "सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण"।
- सदस्य देश- 11 देश (ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात)



- वर्ष 2026 में यह ब्रिक्स की अध्यक्षता करने का भारत का चौथा अवसर होगा। इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है।
- ब्रिक्स की अध्यक्षता इसके संक्षिप्त नाम में शामिल अक्षरों के क्रम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है। प्रत्येक अध्यक्षता अवधि संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को समाप्त होती है।
- **ब्रिक्स का वैश्विक योगदान-**



  - आबादी- विश्व की 49.5 प्रतिशत आबादी
  - जीडीप- वैश्विक जीडीपी का 40 प्रतिशत
  - विश्व व्यापार- विश्व व्यापार का 26 प्रतिशत
- **ब्रिक्स का उद्भव एवं ऐतिहासिक विकास क्रम-**
- **उद्भव एवं वैचारिक पृष्ठभूमि-** संक्षिप्त नाम का प्रतिपादन- वर्ष 2001 में प्रसिद्ध वैश्विक निवेश बैंकगोल्डमैन सैक्स द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिसर्च पेपर- 'The World Needs Better Economic BRICs' में पहली बार 'BRIC' शब्द गढ़ा गया था।
- **राजनयिक शुरुआत और शिखर सम्मेलन-**
  - प्रथम औपचारिक बैठक (सितंबर 2006)- संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण अधिवेशन के दौरान न्यूयॉर्क में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की पहली औपचारिक बैठक के साथ इसकी राजनयिक शुरुआत हुई।
  - पहला शिखर सम्मेलन (जून 2009)- रूस केयेकातेरिनबर्ग में पहला आधिकारिक 'ब्रिक' (BRIC) शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
  - 'BRICS' का गठन (दिसंबर 2010)- दक्षिण अफ्रीका को इस समूह में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया।
  - दक्षिण अफ्रीका की प्रथम भागीदारी (मार्च 2011)- चीन केसान्यामें आयोजित तीसरे शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार भाग लिया, जिसके बाद समूह का नाम बदलकर BRIC से BRICS हो गया।
- **संस्थागत विकास और न्यू डेवलपमेंट बैंक-**
  - वित्तीय पहल (जुलाई 2014)- ब्राजील केफोर्टालेजामें आयोजित छठे शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने वित्तीय क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया।
  - स्थापना व उद्देश्य- विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतुन्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना की गई।
  - मुख्यालय- न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालयशंघाई, चीनमें स्थित है।
- **ब्रिक्स प्लस-**
  - सदस्यता विस्तार (अगस्त 2023)- दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें शिखर सम्मेलन में छह नए देशों को समूह की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया।
  - जनवरी, 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने। इसके बाद जनवरी, 2025 में इंडोनेशिया 11वें पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ।
- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया है।

- **शिखर सम्मेलन के परिणाम-**
- **आर्थिक-**
  - ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स- स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान व अंतर-संचालनीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने की बात कही गयी है।
  - **ब्रिक्स रिस्क लैब (गिफ्ट सिटी, गुजरात)**-अवसंरचना परियोजनाओं हेतु पुनर्बीमा व भू-राजनीतिक जोखिम प्रबंधन की घोषणा।
  - जयपुर सहमति (एमएसएमई)-इनवॉइस डिस्काउंट मैकेनिज़्म द्वारा एमएसएमई को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने पर जोर।
  - आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था-आईएमएफपर निर्भरता घटाने हेतु आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था संधि संशोधन व 9वां परीक्षण प्रारंभ।
  - कर व सीमा शुल्क- 'ब्रिक्स टैक्स क्रॉस-लर्निंग लैब' व 'AEO Action Plan 2026' द्वारा अवैध वित्तीय प्रवाह पर रोक।
  - 'ब्रिक्स-एनडीवीनॉलेज पोर्टल' और 'ब्रिक्स स्टार्टअप नवाचार कोष' की स्थापना।
- **विज्ञान वप्रौद्योगिकी -**
  - ब्रिक्स अंतरिक्ष परिषद-रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूह का विस्तार व अंतरिक्ष डेटा का सामूहिक उपयोग।
  - पनडुब्बी केबल व स्मार्ट ग्रिड-सुरक्षित डेटा कनेक्टिविटी हेतु डायरेक्ट केबल नेटवर्क अध्ययन व एआई-आधारित स्मार्ट ग्रिड उत्कृष्टता केंद्र।
- **कृषि, खाद्य सुरक्षा व स्वास्थ्य-**
  - ब्रिक्स खाद्यान्न विनिमय-खाद्यान्न मूल्यों की स्थिरता व खाद्य सुरक्षा हेतु 2027 तक 'BRICS Grain Exchange' शुरू करने का लक्ष्य।
  - BRICS AGREEN-बीजों व जर्मप्लाज़्म पर किसान-केंद्रित स्वैच्छिक सहयोग ढाँचा।
  - स्वास्थ्य पहलें-स्वस्थ जीवनशैली रोडमैप (2026-29), NIMHANS के नेतृत्व में मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क, और AMTZ के नेतृत्व में 'ब्रिक्स बायोडिज़ाइन सेंटर'।
- **लॉजिस्टिक्स, जलवायु व सुरक्षा**
  - लॉजिस्टिक्स व GVC-आपूर्ति-शृंखला लचीलापन ढाँचा और 'GVC कार्य योजना 2026–2030'।
  - सतत परिवहन व जलवायु-सतत विमानन ईंधन मंच, ब्रिक्स शहरी गतिशीलता केंद्र, व वनाग्नि/हरितकरण सिद्धांत।
  - सुरक्षा व समाज-आतंकवाद-रोधी कड़ा रुख, भगोड़े अपराधियों हेतु संपत्ति पुनर्प्राप्ति नेटवर्क, गिग श्रमिकों हेतु 'ब्रिक्स कनेक्ट', और 'आर्टिस्ट रजिस्ट्री'।
- **भू-राजनीति व वैश्विक शासन-**
  - UNSC सुधार- 'एजुलविनी सर्वसम्मति' का समर्थन; भारत व ब्राजील की स्थायी सदस्यता का चीन-रूस द्वारा समर्थन।
  - 3Rs रोडमैप (भारत का प्रस्ताव)-वैश्विक शासन सुधार हेतु 3R (Representation, Responsibility, Rule-making) पर आधारित 10-सूत्रीय रोडमैप।
- वर्ष 2027 में 19वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेज़बान चीन होगा।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026-



- संस्करण- 20वां
- जारीकर्ता-विश्व आर्थिक मंच
- वैश्विक समानता स्कोर- 69.2 प्रतिशत
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देशआइसलैंड (93 प्रतिशत)
- शीर्ष क्षेत्रीय स्थान- यूरोप (75.7 प्रतिशत)
- समानता प्राप्त करने का वैश्विक अनुमान- 120 वर्ष
- सर्वश्रेष्ठ सुधरने वाला आयाम- राजनीतिक सशक्तिकरण (+8 प्रतिशत / 20- वर्षीय अवधि में)
- **सूचकांक के आयाम (चार)-**

आयाम	समानता का वर्तमान स्तर (%)	पूर्ण समानता प्राप्त करने में अनुमानित वर्ष
स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा	96.2 प्रतिशत	-
शैक्षणिक उपलब्धि	96.9 प्रतिशत	8 वर्ष
आर्थिक भागीदारी एवं अवसर	61.7 प्रतिशत	129 वर्ष
राजनीतिक सशक्तिकरण	22.1 प्रतिशत	194 वर्ष

- **शीर्ष स्थान-**
  - पहला स्थान आइसलैंड (93 प्रतिशत)
  - दूसरा स्थान- फिनलैंड (87.2 प्रतिशत)
  - तीसरा स्थान- नॉर्वे (85.7 प्रतिशत)
  - चौथा स्थान- नामीबिया (84.5 प्रतिशत)

- **निम्नस्थान-**
  - 143वां स्थान-पाकिस्तान (59.5 प्रतिशत)
  - 144वां स्थान-ईरान(58.5 प्रतिशत)
  - 145वां स्थान- चाड (57.8 प्रतिशत)
- **भारत का प्रदर्शन-**

सूचक/मानक	स्थिति/आँकड़े
भारत का स्थान	131वाँ
भारत का समग्र समानता स्कोर	64.5 प्रतिशत (वैश्विक औसत 69.2 फीसदी से कम)
वैश्विक औसत स्कोर	69.2 प्रतिशत
शैक्षणिक उपलब्धि स्कोर	96.6 प्रतिशत
स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता स्कोर	95.6 प्रतिशत
राजनीतिक सशक्तीकरण स्कोर	24.5 प्रतिशत
मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधित्व (महिला)	5.9 प्रतिशत
श्रम बल समानता	41.2 प्रतिशत
वरिष्ठ एवं प्रबंधकीय पदों पर महिला भागीदारी	13.1 प्रतिशत

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2026

- हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2026 जारी किया गया है।में दुनिया के 1,000 सबसे बड़े शहरों का मूल्यांकन किया गया है।
- इस सूचकांक वैश्विक स्तर परन्यूयार्क प्रथम स्थानऔर भारत में दिल्ली 268वें स्थानपर रहा है।
- **सूचकांक के आयाम (पांच)-**
  1. अर्थव्यवस्था
  2. मानव पूंजी
  3. जीवन की गुणवत्ता
  4. पर्यावरण
  5. शासन
- **वैश्विक शीर्ष शहर-**

वैश्विक रैंक	शहर	देश
1	न्यूयार्क	संयुक्त राज्य अमेरिका
2	लंदन	यूनाइटेड किंगडम
3	पेरिस	फ्रांस
4	सिएटल	संयुक्त राज्य अमेरिका
5	सैन फ्रांसिस्को	संयुक्त राज्य अमेरिका
6	डबलिन	आयरलैंड
7	बोस्टन	संयुक्त राज्य अमेरिका
8	सैन जोस	संयुक्त राज्य अमेरिका
9	टोक्यो	जापान
10	ज्यूरिख	स्विट्जरलैंड

- **भारतीय शहर-**
  - दिल्ली - 268वां स्थान (सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर)
  - बेंगलुरु - 311वां स्थान
  - मुंबई - 330वां स्थान
  - चेन्नई - 381वां स्थान
  - हैदराबाद - 421वां स्थान
  - पुणे - 427वां स्थान
  - कोलकाता - 496वां स्थान
  - अहमदाबाद- 564वां स्थान
  - जयपुर - 634वां स्थान

टाइम्स हायर एजुकेशनवर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027-

- हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027जारी की गयी है।
- इस साल की रैंकिंग में 118 देशों के 2,297 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।
- **टॉप 10 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027-**

संस्थान	देश/क्षेत्र	रैंक 2027
यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड	ब्रिटेन	1
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	अमेरिका	2
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी	अमेरिका	3
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी	अमेरिका	3
यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज	ब्रिटेन	5
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी	अमेरिका	6
कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	अमेरिका	7
इम्पीरियल कॉलेज लंदन	ब्रिटेन	8
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले	अमेरिका	9
येल यूनिवर्सिटी	अमेरिका	9

- **भारत के टॉप शिक्षण संस्थान और उनकी वैश्विक रैंकिंग-**
  - भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु-254वां स्थान (भारत में शीर्ष स्थान पर)
  - सवीथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज-326–350 बैंड
  - शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज-451–500 बैंड
  - जामिया मिलिया इस्लामिया-501–550 बैंड
  - केआईआईटी यूनिवर्सिटी-501–550 बैंड

करेक्ट द मैप प्रस्ताव-



- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मानचित्रों में सुधार और संतुलित भौगोलिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए 'करेक्ट द मैप प्रस्ताव' को स्वीकार किया है।
- **'करेक्ट द मैप' प्रस्ताव (A/80/L.104)-**
  - शीर्षक- "करेक्ट द मैप: रीबैलेंसिंग ग्लोबल कार्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रमोटिंग इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स रीजन्स, पर्टिकुलरली अफ्रीका"
  - **मतदान की स्थिति-**
    - पक्ष में- 164 देश
    - विरोध में- 1 देश (संयुक्त राज्य अमेरिका)
    - अनुपस्थित- 6 देश (एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोलदोवा गणराज्य, सर्बिया, यूक्रेन)
- **सिफारिश-** इक्वल अर्थ प्रोजेक्ट-प्रस्ताव में महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार को सही रूप में दर्शाने के लिए 'इक्वल अर्थ प्रोजेक्ट' के व्यापक उपयोग का आह्वान किया गया है। अफ्रीका संघ द्वारा इसे प्राथमिकता दी गई है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रस्ताव को अव्यावहारिक और विचलनकारी बताते हुए खारिज किया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र एवं आम सभा-

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की आम सभा 22 से 28 सितंबर, 2026 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित की गई।
- इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. खलीलुर रहमान (बांग्लादेश) ने की।
- विषय- "विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन: एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए परिणाम दे"
- उद्देश्य-बहुपक्षीय सहयोग में नए सिरे से विश्वास जगाना, वैश्विक परिवर्तनों के प्रभावी समाधान खोजना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर के लोगों के लिए ठोस व व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने पर बल देना।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा-**
  - यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है।
  - इसे दुनिया की लघु संसद कहा जाता है।
  - सदस्य- 193 सदस्य देश
  - इसमें प्रत्येक देश को महासभा में एक वोट का अधिकार मिलता है।
  - इसकी वार्षिक उच्च-स्तरीय बैठक हर साल सितंबर में न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में होती है।

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य-



- **सुर्ख़ियों में-** यमन के हूथी विद्रोहियों द्वारा इस सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण करने और सऊदी अरब पर नाकाबंदी लगाने के कारण यह सुर्खियों में है।
- यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर/हिंद महासागर से जोड़ने वाला वैश्विक समुद्री चोकपॉइंट है।
- **भौगोलिक स्थिति-**
  - अवस्थिति- यह अरब प्रायद्वीप और हॉर्न ऑफ़ अफ्रीकाके मध्य
  - जल निकाय- उत्तर-पश्चिम में लाल सागर को दक्षिण-पूर्व में अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है।
  - सीमावर्ती देश- एशियाई तट पर यमन तथा अफ्रीकी तट पर जिबूती और इरिट्रिया
  - पेरीम द्वीप- यह जलडमरूमध्य पेरीमद्वीप द्वारा दो चैनलों में विभाजित है।
  - नामकरण- इसे अरबी भाषा में "आँसुओं का द्वार"कहा जाता है, जिसका कारण यहाँ नौकायन के ऐतिहासिक खतरे और संकरा होना है।

बेल्जियम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा-



- बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 2 से 4 सितंबर,2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। फरवरी, 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की भारत की यह पहली यात्रा है।
- उनके साथ बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रेंकेन भी भारत आये।
- **ऐतिहासिक संबंध-**
  - बेल्जियम 1947 में भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती यूरोपीय देशों में से एक था।
  - वर्ष 2027 में दोनों देश राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ मनाएंगे।
- **प्रमुख समझौते और घोषणा-**
  - द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य-अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना।
  - निवेश तंत्र- 'भारत-बेल्जियम निवेश त्वरित समाधान तंत्र' की शुरुआत की गई।
  - भारत-बेल्जियम आर्थिक और निवेश गलियारेकी स्थापना की घोषणा की गयी।
  - बेल्जियम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मेंभारत की स्थायी सदस्यता का समर्थनकिया है।
  - नई दिल्ली में बेल्जियम के रक्षा अटैशे की नियुक्ति का स्वागत किया गया तथा भारत ने भी ब्रुसेल्स में स्थायी रक्षा अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है।

आगा खान पंचम-

- भारत के उपराष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रिंस रहीम आगा खान पंचम 9 से 15 सितंबर, 2026 तक भारत की यात्रा पर हैं।
- वे शिया इस्माइली मुसलमानों के 50वें वंशानुगत इमाम (आध्यात्मिक नेता) हैं। उनकी यह भारत की पहली यात्रा है।

शंघाई सहयोग संगठनशिखर सम्मेलन-

- संस्करण- 26वां
- आयोजन तिथि- 31 अगस्त से 1 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- बिश्केक, किर्गिस्तान
- विषय- SCO के 25 वर्ष: सतत शांति, विकास और समृद्धि की ओर साथ-साथ
- भारत का प्रतिनिधित्व- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- इस शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी प्रयास, कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा सहयोग, साइबर अपराध, संगठित अपराध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर सहमती बनी।
- इस शिखर सम्मेलन में में अंग्रेजी को इस संगठन की आधिकारिक और कामकाजी भाषा के रूप में मंजूरी देने का फैसला भी किया गया।

विविध तथ्य

- सेशेल्स गणराज्य की नेशनल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष सुश्री अज़ारेल अर्नेस्टा के नेतृत्व में सेशेल्स का संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर रहा।
- रोम में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर,2026 तक खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की वानिकी संबंधी समिति के 28वें सत्र (सीओएफओ 28) का आयोजन हो रहा है।
- शंघाई सहयोग संगठन ने पाकिस्तान के लाहौर को वर्ष 2026-27 के लिए 'पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी' घोषित किया है। इससे पहले भारत के वाराणसी को 2022-23 में यह दर्जा मिला था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस मनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। सिएरा लियोन के प्रस्ताव को भारत समेत करीब 70 देशों ने सह-प्रायोजित किया।
- हाल ही में द हेग स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वेनेजुएला, चाड, बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने बाहर होने की घोषणा की है।
- बर्डलाइफ इंटरनेशनल ने नैरोबी में ग्लोबल फ्लाईवेज समिट में स्टेट ऑफ द वर्ल्डस बर्ड्स रिपोर्ट जारी की। पहली बार रिपोर्ट प्रवासी पक्षियों और उनके फ्लाईवेज पर केंद्रित है। रिपोर्ट के अनुसार हर 9 में से 1 प्रजाति पर विलुप्ति का खतरा है।
- यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने EU KIDS एक्ट का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया की लत और ऑनलाइन खतरों से बचाना है। प्रस्ताव में 13 साल से छोटे बच्चों के सोशल मीडिया पर रोक और 13 से 15 साल के बच्चों के लिए माता-पिता की निगरानी में मिनी अकाउंट की व्यवस्था होगी।
- वॉरन बफे- यह विश्व के महान निवेशक और बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन है जिन्होंने बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन का पद त्यागने की घोषणा की है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूसी तेल खरीद पर भारत समेत 5 देशों पर 100% तक टैरिफ वाले बिल पर साइन कर दिए हैं। अब इस कानून के तहत भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक में अपना सैन्य अभियान समाप्त कर दिया है।

■■■■

राष्ट्रीय परिदृश्य

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026-

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026' के परिणाम जारी किए गए हैं।
- इस सर्वेक्षण में वायु प्रदूषण नियंत्रण, वायु गुणवत्ता में सुधार और स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के आधार पर देश के शहरों का मूल्यांकन किया गया है।
- **श्रेणीवार रैंकिंग-**
  - श्रेणी-I (10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर)
    - 1th- लखनऊ (198 अंक)
    - 2th -इंदौर (197 अंक)
    - 3th -जबलपुर (195 अंक)
  - श्रेणी-II (3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर)
    - 1th -राउरकेला (198.5 अंक)
    - 2th - फिरोजाबाद (195 अंक)
  - श्रेणी-III (3 लाख से कम आबादी वाले शहर)
    - 1th - कलिंगा नगर (198.5 अंक)
    - 2th -अंगुल (196.5)
- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम-**
  - शुभारंभ- वर्ष 2019
  - मंत्रालय- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयद्वारा
  - मुख्य उद्देश्य- शहरों में पीएम-10 और पीएम-2.5 के स्तर को घटाना तथा वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को मजबूत करना।
  - संशोधित लक्ष्य- 2017-18 की तुलना में वर्ष 2025-26 तक पीएम-10 सांद्रता में 40 प्रतिशततक की कमीलाना या NAAQS मानकों को प्राप्त करना।

भारत की पहली एलएनजी-डीजल डीएमयू ट्रेन का शुभारंभ-

- 27 सितंबर, 2026 को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती रेलवे स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आधारित ट्रेन का शुभारंभ किया है।
- मार्ग- साबरमती से महेसाणा जंक्शन के मध्य
- संरचना- यह 8 डिब्बों वाली नॉन-एसी चेयर कार ट्रेन
- टैंक क्षमता- प्रत्येक डीपीसी में लगभग 2,200 लीटर क्षमता का एलएनजी टैंक
- यह ट्रेन केवल एलएनजी पर आधारित न होकर एलएनजी-डीजल ड्यूल-फ्यूल तकनीक का उपयोग करती है। यह प्रणाली एलएनजी का उपयोग करके पारंपरिक डीजल की खपत में लगभग 40 प्रतिशत तक की कमी ला सकती है।
- राष्ट्रीय परिवहन कंपनी द्वारा साबरमती इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो में दो 1,400 एचपी की ड्राइविंग पावर कारों (DPC) को इस तकनीक के अनुकूल परिवर्तित किया गया है।
- **आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ-**
  - एलएनजी के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइडऔर कणिकीय पदार्थों के उत्सर्जन में कमी आएगी।
  - परिचालन लागत में बचत होगी।

इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स-

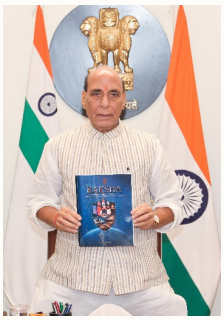
- संस्करण- द्वितीय
- जारीकर्ता- नीति आयोग
- **प्रमुख निष्कर्ष-**
  - वैश्विक एवं घरेलू परिदृश्य- वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में हिस्सेदारी (वर्ष 2025 आंकड़े)-
    - चीन- 50 प्रतिशत से अधिक।
    - यूरोपीय संघ- 25 प्रतिशत से अधिक।
    - अमेरिका-लगभग 10 प्रतिशत।
  - केंद्र सरकार की प्रमुख पहल एवं वित्तीय सहायता- इलेक्ट्रिक वाहनों और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 92,000 करोड़ रुपये से अधिककी सहायता प्रदान की जा रही है-
    - प्रमुख योजनाएं- फेम योजना, पीएम ई-ड्राइव,पीएम ई-बस सेवा
- **राज्यों का प्रदर्शन एवं इंडेक्स के निष्कर्ष-**
  - भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशोंने अपनी ईवी नीतियां अधिसूचित कर दी हैं।
  - आईईएमआई (IEMI) स्कोर में सुधार-
    - शीर्ष राज्य स्कोर-पिछले एक वर्ष में उच्चतम राज्य स्कोर 77 से बढ़कर 84 हो गया है।
    - औसत राज्य स्कोर-राज्यों का औसत स्कोर 36 से बढ़कर 40 हो गया है।

बायो-निवेशपहल का शुभारंभ-

- 3 सितम्बर, 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'बायो-निवेश' का शुभारंभ किया।
- **बायो-निवेश क्या है?-** यह जैव-प्रौद्योगिकी नवोन्मेषकोंऔर निवेशक समुदाय के बीच जुड़ाव को मजबूत करने हेतु डिजाइन किया गया एक रणनीतिक, दो-तरफा प्लेटफॉर्म है।

- **उद्देश्य-**
  - जैव-प्रौद्योगिकी नवाचारों को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाने और उनके व्यवसायीकरण हेतु निजी पूंजी के प्रवाह को गति देना।
  - पारंपरिक निवेशक-बैठक प्रारूप से आगे बढ़कर नवोन्मेषकों को निवेशकों की दृष्टि समझने तथा निवेशकों को जैव-प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक, नियामक और विकास मार्गों की गहन जानकारी प्रदान करना।

रक्षा-



- रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 3 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में रक्षा कूटनीति पर 'रक्षा' नामक दस्तावेज का विमोचन किया।
- रक्षा कूटनीति भारत की विदेश नीति का एक मुख्य स्तंभ है।
- यह व्यापक दस्तावेज आगामी 10 वर्षों में वैश्विक रक्षा साझेदारियों पर देश के रणनीतिक रोडमैप और दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- इस दस्तावेज के रणनीतिक खाके निम्न स्तंभों को उल्लेखित किया गया है-
  1. रणनीतिक साझेदारी- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना।
  2. क्षमता विकास-संयुक्त सैन्य अभ्यासों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा मित्र देशों के साथ रक्षा के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करना।
  3. स्वदेशी निर्यात-भारत में निर्मितरक्षा प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर देश को एक विश्वसनीय वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना।
  4. समुद्री सुरक्षा- हिंद महासागर क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करना।

मांदर वाद्य यंत्र-



- सुर्ख़ियों में- झारखंड के पारंपरिक जनजातीय वाद्ययंत्र 'मांदर' को जीआई टैग प्रदान किया गया है।
- **मांदर वाद्ययंत्र-**
  - यह ढोलक जैसा अवनद्ध वाद्ययंत्र होता है।
  - इसका एक सिरा पूरी तरह से स्थानीय लाल मिट्टी से बनता है।
  - यह झारखंड की जनजातीय संस्कृति, लोक कला प्रस्तुतियों, सामुदायिक सम्मेलनों तथा विभिन्न उत्सवों का एक मुख्य सांस्कृतिक अंग माना जाता है।
- **भौगोलिक संकेतक (जी.आई.) टैग-**
  - यह किसी क्षेत्र के उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा का आधार या गारंटी है जो बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में है।
  - यह टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है।

मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2026 रैंकिंग

- हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स ने मास्टर्स इन मैनेजमेंट-2026 रैंकिंग जारी की है।
- इसमें विश्व के टॉप-100 में भारत के 14 संस्थान शामिल हैं। इनमें सात सरकारी और सात प्राइवेट संस्थान हैं।
- **सम्मिलित संस्थान-**
  - 21वां स्थान - भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु
  - 26वां स्थान - एस. पी. जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
  - 27वां स्थान - भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद
  - 33वां स्थान - XLRI-जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
  - 39वां स्थान - भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता
  - 54वां स्थान - भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड
  - 62वां स्थान - भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर

आयुर्वार्ता-

- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली ने 'आयुर्वार्ता' नामक विशेष डिजिटल संवाद श्रृंखला की शुरुआत की है।
- उद्देश्य- आयुर्वेद के प्रामाणिक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था में इसकी प्रासंगिकता को देश-विदेश के व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचाना है।
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानआयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है।

भारत के 7वें डाक प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला-

- उद्घाटनकर्ता-श्री ज्योतिरादित्यसिंधिया (केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री)
- तिथि- 2 सितंबर 2026
- स्थान-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)
- **मुख्य उद्देश्य-**
  - डाक कर्मियों को आधुनिक कौशलों, उभरती प्रौद्योगिकियों और नागरिक-केंद्रित डाक संचालन से लैस करना।
- **अन्य छह केंद्र-**

1. सहारनपुर
2. वडोदरा
3. मैसूरु
4. गुवाहाटी
5. मदुरै
6. दरभंगा

अहमदाबाद से 'हब एंड स्पोक' इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू-



- 1 सितम्बर, 2026 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहमदाबाद से 'हब एंड स्पोक' इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया है।
- अहमदाबाद, वाराणसी (25 जून,2026) और अमृतसर (28 जुलाई,2026) के बाददेश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो भारत के 'हब एंड स्पोक' फ्रेमवर्क में शामिल हुआ है।
- उद्देश्य- भारत को 2030 तक पसंदीदा एविएशन हब और 2047 तक प्रमुख ग्लोबल एविएशन हब बनाना, जिससे विदेशी ट्रांजिट एयरपोर्ट पर निर्भरता कम हो सके।
- हब एंड स्पोकफ्रेमवर्क को देश के 22 और एयरपोर्ट्सतक बढ़ाया जाएगा।
- **'हब एंड स्पोक' मॉडल की कार्यप्रणाली-**
  - सिंगल चेक-इन व इमिग्रेशन-यात्री अपने शुरुआती 'स्पोक' एयरपोर्ट (जैसे अहमदाबाद) पर ही चेक-इन, इमिग्रेशन और कस्टम्स की प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे।
  - सुगम ट्रांसफर-मुख्य 'हब' (दिल्ली) पहुंचने पर यात्रियों को दोबारा इमिग्रेशन या कस्टम्स से नहीं गुजरना होगाऔर उनका सामान सीधे अगली अंतरराष्ट्रीय उड़ान में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 अधिसूचित-

- हाल ही में भारत सरकार ने विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 अधिसूचित किये है।
- अधिसूचित तिथि- 27 अगस्त,2026 (राजपत्र में प्रकाशन-29 अगस्त,2026)
- नियामक प्राधिकरण-विधिक मापविज्ञान विभाग
- वैज्ञानिक आधार- CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
- संबंधित मंत्रालय-उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)
- मूल विजन- 'एक देश, एक समय' का समर्थन करना।
- **उद्देश्य एवं ढांचा-**
  - कानूनी मान्यता-भारतीय मानक समय को देश के लिए एकमात्र सामान्य, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त और ट्रेस करने योग्य समय संदर्भ के रूप में स्थापित करना।
  - व्यापक ढांचा-यह नियम भारतीय मानक समय की उत्पत्ति, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए एक कानूनी संरचना प्रदान करता है।
- **डिस्ट्रिब्यूटेड नेशनल आर्किटेक्चर (क्षेत्रीय केंद्र)-**

1. अहमदाबाद
2. बेंगलुरु
3. भुवनेश्वर
4. फरीदाबाद
5. गुवाहाटी

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के लिए दिशा-निर्देश-

- 1 सितंबर,2026 कोभारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये।
- **खाद्यान्न खरीद एवं गुणवत्ता मानक-**
  - खरीफ विपणन मौसम (2026-27)-धान खरीद का अनुमान 708.64 लाख मीट्रिक टनऔर मोटे अनाज की खरीद का अनुमान 18.85 लाख मीट्रिक टनरखा गया है।
  - उन्नत चावल के लिए नए मानक-
    - कच्चा चावल-टूटे हुए दानों की सीमा 25 प्रतिशतसे घटाकर 10 प्रतिशतकी गई।
    - पारबॉयल्ड चावल-टूटे हुए दानों की सीमा 16 प्रतिशतसे घटाकर 5 प्रतिशतकी गई।
  - एआई सत्यापन-खरीफ विपणन मौसम 2026-27 से प्रोक्योरमेंट सेंटर स्मार्ट-असेसमेंट पोर्टल के तहतएआई-आधारित इमेज सत्यापनऔर ऑनलाइन भौतिक सत्यापन लागू होगा।
- **राज्यों का प्रदर्शन एवं भंडारण नीति (राज्यों की उत्कृष्ट उपलब्धियां)-**
  - आंध्र प्रदेश-उन्नत चावल योजना में सर्वश्रेष्ठ।
  - पंजाब-संयुक्त भौतिक सत्यापनऔर PCSAP में सर्वश्रेष्ठ।
  - कर्नाटक-श्री अन्ना (मोटे अनाज) की खरीद में उत्कृष्टता।
  - छत्तीसगढ़-धान खरीद में 'एग्रीस्टैक' लागू करने वाला पहला राज्य।
- **नई भंडारण नीति-**
  - कुल 131 लाख मीट्रिक टनअतिरिक्त भंडारण क्षमता (111 लाख मीट्रिक टन राज्यों द्वारा + 20 लाख मीट्रिक टन FCI द्वारा) बनाई जाएगी।

- **तकनीक आधारित आपूर्ति श्रृंखला-**
  - जीपीएस ट्रैकिंग-खाद्यान्न वाहनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग हेतु दिसंबर, 2026 तक शत-प्रतिशत कार्यान्वयन का लक्ष्य।
- **डिजिटल रुपये में डीबीटी पायलट प्रोजेक्ट-** FPS (उचित मूल्य की दुकान) डीलर मार्जिन के लिए डिजिटल रुपये पर आधारित डीबीटी प्रोजेक्ट का विस्तार दिल्ली तथा छह अन्य राज्यों (आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु) के दो-दो जिलों में किया जाएगा।

गोल्लाला गुड़ी मंदिर-

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने तेलंगाना के गोल्लाला गुड़ी मंदिर को 'राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक' घोषित किया है।
- **मंदिर-**
  - अवस्थित- पालमपेट गाँव, मुलुगु जिला,तेलंगाना
  - निर्माण काल- 12वीं–13वीं शताब्दी ईस्वी/काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान
  - यह मंदिर 'त्रिकूटालय' वास्तु शैली में निर्मित है। इसमें तीन स्वतंत्र गर्भगृह हैं। **इसके केंद्रीय गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है।**
- किसी स्मारक या स्थल को राष्ट्रीय महत्त्व घोषित करने के लिए उसका कम-से-कम 100 वर्ष पुरानाहोना आवश्यक है। वर्तमान में देश में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के संरक्षण वाले ऐतिहासिक स्मारकों की संख्या 3,689 हो गई है।

दक्षिण भारत में पाई गईं रतनजोत (जेट्रोफा) की 3 नई प्रजातियां-

- मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के वनस्पति विज्ञानविभाग के शोधकर्ताओं ने प्रायद्वीपीय भारत मेंरतनजोत (जेट्रोफा) की तीन नई प्रजातियों की पहचान की है।
- **प्रजातियाँ-**

1. जेट्रोफा लिविंगस्टोनै 2. जेट्रोफा नरसिम्हानी
3. जेट्रोफा उमाशंकरी

बाल विवाह उन्मूलन के लिए 2030 का लक्ष्य एवं 'अंतर्राष्ट्रीय दिवस' घोषित-

- भारत ने देश में बाल विवाह की प्रथा को वर्ष 2030 तक पूरी तरह समाप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 नवंबर को "बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह उन्मूलन दिवस"के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है।
- **संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐतिहासिक प्रस्ताव-**
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव पश्चिमी अफ्रीकी देशसिएरा लियोन की ओर से लाया गया था।
  - भारत का समर्थन व योगदान-भारत समेत 50 से अधिक देशोंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

गोंधल-

- फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मराठी फिल्म 'गोंधल' को वर्ष 2027 के ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री चुना गया है।
- यह फिल्म संतोष दावखर द्वारा लिखित और निर्देशित है।
- इस फिल्म में ग्रामीण महाराष्ट्र में नवविवाहित जोड़े से जुड़े पारंपरिक अनुष्ठान की एक रात की कहानी है।
- ऑस्कर समारोह 14 मार्च 2027 को लॉस एंजिलिस में होगा।

ओएनजीसी को ओडिशा तट के पास समुद्र के नीचे मिली प्राकृतिक गैस-

- तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने ओडिशा केकोणार्क तट से लगभग 43 किलोमीटर दूरगहरे समुद्र में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज की है। यह सफलता ओएनजीसी के 'समुद्र मंथन' अभियान के तहतमहानदी बेसिनमें प्राप्त हुई है।

पीलीभीत में बीईडीएफ बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला-

- 9 सितम्बर, 2026 को केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के तांडा बिजेशी में बीईडीएफ बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी।
- संयुक्त परियोजना-यह केंद्रकृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) तथाबासमती निर्यात विकास फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है।
- **प्रमुख तथ्य-**
  - देश मेंजैविक उत्पादनमें उत्तर प्रदेश 7वें स्थानपर है।
  - जैविक खेती के क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश में 8वें स्थान पर है।

T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद-

- 21 सितंबर, 2026 कोरक्षा मंत्रालय नेएक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिएसहायक विद्युत इकाइयों की खरीद हेतु ₹586 करोड़के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- **सहायक विद्युत इकाई की प्रमुख विशेषताएं एवं लाभ-**
  - एपीयूटैंक के मुख्य इंजन को बंद रखकर भी उसके विभिन्न महत्वपूर्ण उपकरणों को लगातार विद्युत शक्ति प्रदान करने वाला एक वैकल्पिक स्रोत है।
  - यह इकाई टैंक केफायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टमऔर अन्य सहायक उपकरणों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
  - स्वदेशी रूप से विकसित इस एपीयू को शामिल करने से भारतीय सेना कीमशीनीकृत इकाइयों (Mechanised Units) की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता और स्थायित्व में सुधार होगा।

देश का पहला बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र

हरित ऊर्जा स्वच्छ भविष्य

हाल हीं में गुजरात के गांधीनगर जिले के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में देश के पहले बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी गई।



विशेषताएं

- **वित्तीय परिव्यय-** ₹2,300 करोड़
- **उत्पादन क्षमता-** 150 टन प्रतिदिन
- **संयुक्त उद्यम-** दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (DPA) और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (APCL)
- **पूंजीगत अनुपात-** दोनों साझेदारों के बीच पूंजीगत योगदान का अनुपात **76:24** (DPA : APCL) तय किया गया है।
- **कच्चा माल व तकनीक-** यह संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा, जल और जैविक स्रोतों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ई-मेथनॉल (हरित ईंधन) का उत्पादन करेगा।



स्थापित

यह संयंत्र चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा-

1 प्रथम चरण-

- निवेश : ₹1,200 करोड़
- उत्पादन क्षमता- 50 टन प्रतिदिन
- लक्ष्य- : जनवरी, 2027

2 द्वितीय चरण-

- निवेश : ₹1,100 करोड़
- उत्पादन क्षमता- 100 टन प्रतिदिन
- लक्ष्य- : मार्च, 2027

महत्व

इस हरित ईंधन का उपयोग एशिया-यूरोप अंतरराष्ट्रीय व्यापार गलियारे पर चलने वाले जहाजों में ईंधन की आपूर्ति के लिए किया जाएगा।

यह सिंगापुर-रॉटरडैम समुद्री मार्ग पर हरित ईंधन के एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा।

यह भारत की सबसे बड़ी ई-मेथनॉल उत्पादन सुविधाओं में से एक होगी, जिससे 3,500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

एनएसओ ने पहली बार गैर-कृषि क्षेत्र के लिए जिला स्तरीय अनुमान जारी किए-

- हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारावार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (ASUSE-2025) के आधार पर पहली बार भारत के गैर-निगमित और गैर-कृषि क्षेत्र के लिए विस्तृत जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए गए हैं। **इन अनुमानों के प्रमुख निष्कर्ष-**

- **आर्थिक संकेंद्रण और भौगोलिक वितरण**
  - देश के शीर्ष 10 जिले गैर-निगमित क्षेत्र के कुल प्रतिष्ठानों, श्रमिकोंऔर सकल मूल्य वर्धित का लगभग 10% (दसवां हिस्सा)योगदान करते हैं। ये जिले गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैले हैं।
  - कुल प्रतिष्ठानों, श्रमिकों और सकल मूल्य वर्धित का लगभग एक-तिहाई (33%) हिस्साकेवल शीर्ष 50 जिलों में संकेंद्रित है, जो 12 राज्यों में फैले हैं।

- **प्रतिष्ठानों का दायरा-**
  - लगभग एक-तिहाई जिलों में प्रति जिला 1 लाख से अधिक प्रतिष्ठान हैं।
  - केवल 16 जिलों (पश्चिम बंगाल-8, महाराष्ट्र-3, गुजरात-2, कर्नाटक-1, तेलंगाना-1, उत्तर प्रदेश-1) में प्रति जिला 5 लाख से अधिक प्रतिष्ठान हैं।

- **उत्पादकता प्रदर्शन-**
  - 280 जिलोंमें प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित अखिल भारतीय औसत (₹1,56,539) से अधिक है, जो इन क्षेत्रों में उच्च आर्थिक उत्पादकता को दर्शाता है।
  - लगभग 331 जिलों में प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धितर 1 लाख से ₹1.5 लाखके बीच है।

- **महिला उद्यमिता और भागीदारी-**
  - महिला स्वामित्व वाले गैर-पंजीकृत उद्यमों की उच्चतम हिस्सेदारी वाले शीर्ष 10 जिले तेलंगाना, मणिपुर और मेघालय में स्थित हैं।
  - मिजोरमराज्य केप्रत्येक जिले में कम से कम 50% प्रतिष्ठान महिला-स्वामित्व वालेहैं।

- **कार्यबल में भागीदारी-**
  - 237 जिलोंके गैर-निगमित कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33% (एक-तिहाई)है।
  - 25 जिलों में महिला कामगारों की हिस्सेदारी 50% से अधिक है।

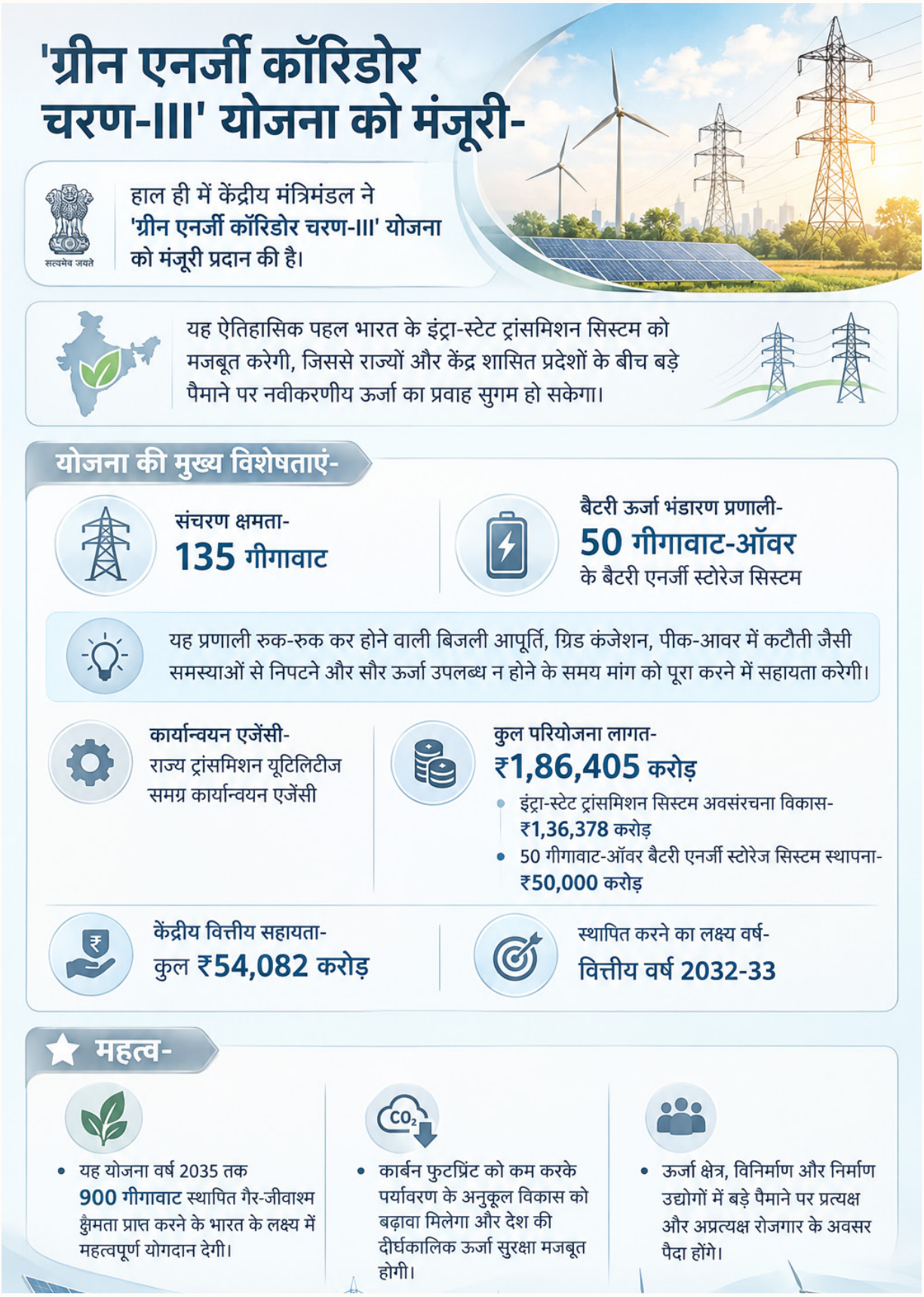
- **विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रतिष्ठानों वाले जिले**

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	सबसे अधिक प्रतिष्ठानों वाला जिला	राज्य के भीतर योगदान (प्रतिशत)
अंडमान और निकोबार	दक्षिण अंडमान	61.04
आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	5.61
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	5.77
कर्नाटक	बेंगलुरु (शहरी)	12.83
गुजरात	सूरत	19.43
तमिलनाडु	चेन्नई	7.13
तेलंगाना	रंगारेड्डी	23.53
पंजाब	लुधियाना	14.74
बिहार	पटना	8.23
महाराष्ट्र	पुणे	9.14
मध्य प्रदेश	जबलपुर	6.03
राजस्थान	जयपुर	11.70
पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	15.99
हरियाणा	गुरुग्राम	9.96

विविध तथ्य

- भारतीय रेलवे ने गुजरात के भावनगर पारा यार्ड के पुनर्निर्माण परियोजना को लगभग 125करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति प्रदान की है।
- भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के 712 रूट किलोमीटर खंडों पर कवच वर्जन 4.0 लागू करने की स्वीकृति दे दी है। इसकी कुल लागत 170 करोड़ रुपये है।
- पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते (NAMASTE) योजना के तहत व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
- राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने5 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
- उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 5 सितंबर,2026 को चेन्नई में आयोजित 'इंडिया वाल्व्स 2026' सम्मेलन के दौरान 'इंडिया वाल्व रजिस्ट्री' का शुभारंभ किया।
- भारतीय रेलवे ने गुजरात के भावनगर पारा यार्ड के पुनर्निर्माण परियोजना को लगभग 125करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति प्रदान की है।

'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III' योजना को मंजूरी-



भारतीय वायु सेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (SAT-SAAW) की खरीद-

- 23 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय नेभारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय वायु सेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन तथा उनके संबंधित उपकरणों की आपूर्ति हेतु ₹810.79 करोड़के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- डिजाइन व विकास- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा
- स्वदेशी सामग्री- 60 प्रतिशतस्वदेशी सामग्री का उपयोग
- **विशेषताएं-**
  - यह हवा से जमीन पर मार करने वाला एक अत्याधुनिक और सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है।
  - लॉन्च प्लेटफॉर्म्स- जगुआर, हॉकऔरसुखोई-30 एमकेआई से
  - महत्व- यह लंबी स्टैंड-ऑफ रेंजसे दुश्मन के एयरफील्ड, रनवे और बंकरों को पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है, जिससे विमान को दुश्मन के हवाई रक्षा तंत्र के सीधे खतरे में आए बिना हमला करने की सुविधा मिलती है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सैन्य खरीद प्रस्तावों स्वीकृति प्रदान की-

- रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 7 सितंबर, 2026 को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में रक्षा बलों के विभिन्न खरीद प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- कुल स्वीकृत राशि-लगभग ₹1,10,000 करोड़।

सेना के तीनों अंगों हेतु स्वीकृत प्रमुख उपकरण एवं प्रणालियाँ-

1. **भारतीय थल सेना-**
   - रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन।
   - उच्च गतिशीलता वाले वाहन।
   - स्वचालित यांत्रिक बारूदी सुरंग बिछाने वाले वाहन।
   - उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर।
   - ट्रॉल टैंक एवं सर्वत्र ब्रिज सिस्टम।
2. **भारतीय नौसेना-**
   - अरुध्रा रडार
   - मरीन गैस टर्बाइनों का डिजाइन एवं विकास-एमजीटी एक स्वदेशी युद्धपोत प्रणोदन प्रणाली है, जिससे रक्षा क्षेत्र में विदेशी विक्रेताओं और आयात पर निर्भरता काफी कम होगी।
3. **भारतीय वायु सेना-**
   - लड़ाकू, परिवहन विमानों एवं हेलीकॉप्टरों की क्षमता वृद्धि की जायेगी।
   - ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पज जैमर।
   - डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड।

एचएएल द्वारा रक्षा उपकरणों की आपूर्ति-

- 18 सितंबर, 2026 को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने भारतीय वायु सेना को दो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस (एफओसी) दो-सीटर ट्रेनर तथा तीन एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर हेलीकॉप्टर सौंपे।
- एचएएल ने पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल) को चार ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन (एनजी) हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराए है।

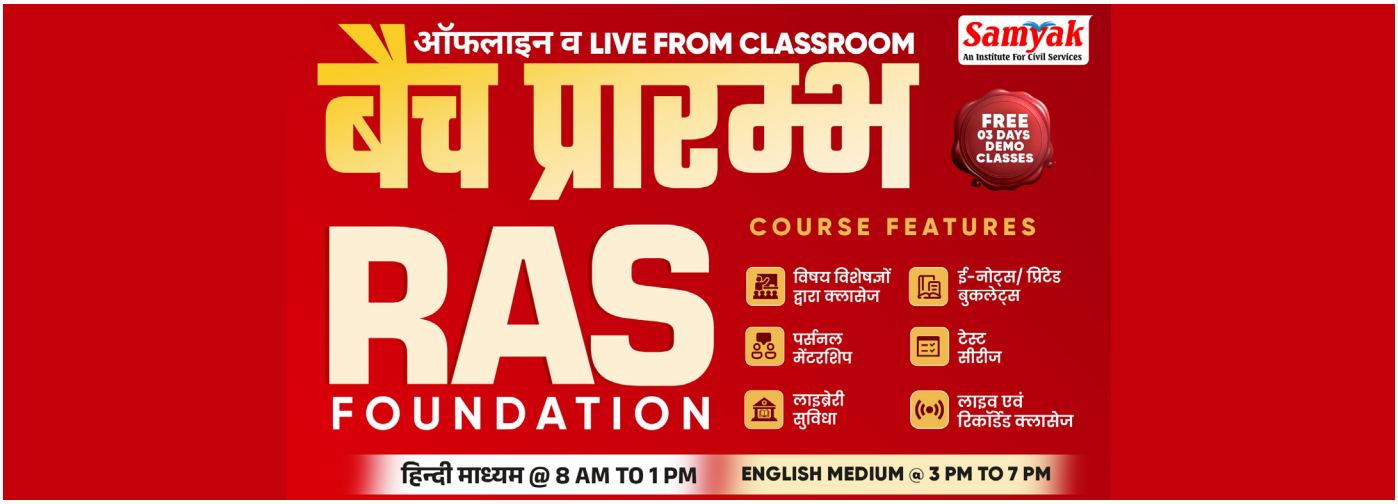
	एलसीए तेजस एफओसी प्रशिक्षक	एचटीटी -40	ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन (एनजी) हेलीकॉप्टर
श्रेणी	सुपरसोनिक लीड-इन फाइटर ट्रेनर (LIFT)	बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट (बीटीए)	बहु-भूमिका वाला नागरिक हेलीकॉप्टर
ऑपरेटर	भारतीय वायु सेना	भारतीय वायु सेना	पवन हंस लिमिटेड / सिविल पीएसयू
भूमिका	परिचालन रूपांतरण और पूर्ण युद्ध संचालन	चरण-1 मूलभूत और प्रारंभिक उड़ान प्रशिक्षण	अपतटीय रसद, आपदा राहत और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं
प्रणोदन प्रणाली	जीई एयरोस्पेस एफ404-आईएन20 टर्बोफैन	हनीवेल TPE331-12B टर्बोप्रॉप	शक्ति टर्बोशाफ्ट (HAL-Safran)

उपकरण विशेषताएं	ग्लास कॉकपिट, उन्नत एवियोनिक्स और पूर्ण हथियार हार्डपॉइंट	आधुनिक डिजिटल एवियोनिक्स, जीरो-जीरो इजेक्शन सीटें और एरोबैटिक हैंडलिंग	डीजीसीए-प्रमाणित केबिन लेआउट, फ्लोटेशन गियर और कार्गो हुक
स्वदेशीकरण-	2010 के अनुबंध बैच की अंतिम डिलीवरी	आधारभूत स्तर पर 56% स्वदेशी सामग्री, जो बढ़कर 60% से अधिक हो जाती है	10 विमानों के ऑर्डर के तहत पहली चार यूनिटें डिलीवर की गईं
फोटो-			

विविध तथ्य

- भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के 712 रूट किलोमीटर खंडों पर कवच वर्जन 4.0 लागू करने की स्वीकृति दे दी है। इसकी कुल लागत 170 करोड़ रुपये है।
- पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते (NAMASTE) योजना के तहत व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
- राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने5 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
- उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 5 सितंबर,2026 को चेन्नई में आयोजित 'इंडिया वाल्व्स 2026' सम्मेलन के दौरान 'इंडिया वाल्व रजिस्ट्री' का शुभारंभ किया।
- 25 सितम्बर, 2026 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग' (डीसीआर) प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे ग्राहकों को विभिन्न संपत्तियों की डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग की जानकारी उपलब्ध कराने और संपत्तियों की डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहें।
- रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 से 10 सितंबर, 2026 तक श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा की।
- सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 16 से 18 सितंबर,2026 तक रूस की तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रक्षा साझेदारी और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना था।
- केंद्रीय पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मुंबई में विश्व ओजोन दिवस-2026 के अवसर पर भारत का नेट जीरो पोर्टल और जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।
- गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
- हाल ही में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई), बेंगलुरु में 'स्किल्स4फ्यूचर' ईवी और ग्रीन स्किल्स लैब का उद्घाटन किया गया है।
- वाणिज्य विभाग के अपर सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मनीला, फिलीपींस में आयोजित 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक (ईएएस-ईएमएम) और 23वें आसियान-भारत आर्थिक मंत्री परामर्श में भाग लिया।
- केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए के गंभीर मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए राजस्थान, बिहार और आंध्रा में तीन विशेष न्यायालय बनाए है। ये जयपुर पटना और विशाखापत्तनम में होंगे।
- महाराष्ट्र सरकार ने 2029 तक राज्य को नशामुक्त बनाने की नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- केरलम राज्य ने कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक 622 किमी लंबे नेशनल हाईवे-66 को देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है।
- कर्नाटक ने एयरोस्पेस पॉलिसी 2026-31 को मंजूरी दी। इससे विमानन और रक्षा तकनीक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

- हाल ही में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में बदलाव किए। ये 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इनका मकसद फर्जी छूट, भ्रामक विज्ञापन और सर्च नतीजों में गड़बड़ी रोकना है। कंपनियों को छूट के साथ पिछले 30 दिनों की सबसे कम कीमत यानी 'प्रायर प्राइस' दिखानी होगी।
- हाल ही में केरल ने बुजुर्गों के लिए सरकारी सेवाओं को आसान बनाने की दिशा में एल्डर-फ्रेंडली ऑफिस पहल शुरू की है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 'जन सूचना सेवा' शुरू की। इसका मकसद आम लोगों और दिव्यांगों तक कोर्ट के फैसलों को आसान भाषा में पहुंचाना है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसलों का सरल हिंदी में सारांश दिया जाएगा।
- लद्दाख के उपराज्यपाल ने जांस्कर घाटी के कुमिक गांव को लद्दाख का पहला आधिकारिक हेरिटेज विलेज घोषित किया। घोषणा 11वें लद्दाख जांस्कर महोत्सव पर हुई।
- कर्नाटक सरकार ने तुलु भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया है।
- हाल ही में 1960 के दशक के नगालैंड पर बनी फिल्म अंग' ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में प्लेटफॉर्म अवॉर्ड जीता। फिल्म के डायरेक्टर थेजा रियो हैं। ये इसमें कोनयाक जनजाति के एक बुजुर्ग मुखिया और उनके बेटे की कहानी दिखाई गई है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के पेशेंट सेफ्टी डेटाबेस में डेटा शेयर करने के मामले में भारत दुनिया में 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
- हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार विभाग के तहत आने वाले डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन को बंद कर दिया। 1989 में यह 'टेलीकॉम कमीशन' के नाम से बना था और 2018 में डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन हुआ। यह स्पेक्ट्रम की कीमत, नई नीतियों और ट्राईकी सिफारिशों पर फैसले लेने वाला मुख्य निकाय था।
- पुणे शहर वर्ष 2032 में 'यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप' की मेजबानी करेगा। यह फैसला कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुई 'यूसीआई कांग्रेस'में लिया गया।
- असम ने 796.88 करोड़ रुपए के स्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसमें एशियाई विकास बैंक 637.50 करोड़ रुपए का लोन देगा और बाकी राशि राज्य सरकार देगी।
- भारत और लाइबेरिया ने संयुक्त राष्ट्र में 'ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफियरर्स' शुरू किया है। इससमूह का उद्देश्य जहाजों और नाविकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स-2026 में भारत 9 पायदान ऊपर चढ़कर 31वें स्थान पर पहुंच गया।
- हाल ही में यूनेस्को आईओसी कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 74 और तटीय गांवों को 'सुनामी रेडी' घोषित किया गया है।
- यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में भारत के पाँच नए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को शामिल किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश की बाघ गुफा चित्रकारी, चंबल घाटी के मंदिर, उदयगिरि गुफाएं, सत्याग्रह के स्थलऔर गिन्नौरगढ़ किला शामिल हैं।
- भारत और श्रीलंका ने तीन रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें श्रीलंकाई एयरफोर्स की एल-70 तोपों का अपग्रेडेशन, दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर का तालमेल और नेशनल डिफेंस कॉलेज के बीच सहयोग शामिल है।
- 7 सितंबर, 2026 को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा की राजधानी पणजी में गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया।



सर्वाधिक विश्वसनीय व परिणामोन्मुखी

TEST SERIES



RAS 2026

OFFLINE & ONLINE EVERY SUNDAY

PRELIMS
21 TEST PAPER

16 TOPICWISE
05 FULL PAPER

TIME: 10:30 AM

PRELIMS GOLD

35 TEST PAPER

MAINS 14 TEST
8 AM - 10 AM

PRE 21 TEST
10:30 AM - 1:30 PM

- RPSC पैटर्न पर आधारित
- डिटेल्ड मॉडल ANSWER KEY
- हिंदी और ENGLISH MEDIUM
- PERSONAL MENTORSHIP

आर्थिक परिदृश्य

विपणन सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी-

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2027-28 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
- सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में विपणन सीजन 2027-28 के लिए वृद्धि की है।
- एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि कुसुम के लिए घोषित की गई है, जो 675 रुपये प्रति क्विंटल है।
- विपणन सीजन 2027-28 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(रुपये प्रति क्विंटल)-

क्र. सं.	फसलें	एमएसपी-2027-28	एमएसपी-2026-27	एमएसपी में वृद्धि (पूर्ण)
1	गेहूं	2610	2585	25
2	जौ	2286	2150	136
3	चना	5958	5875	83
4	मसूर	7390	7000	390
5	रेपसीड और सरसों	6613	6200	413
6	कुसुम	7215	6540	675

न्यूनतम समर्थन मूल्य-

- **परिभाषा**- न्यूनतम दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीद की गारंटी देती है, ताकि बाजार में फसलों के दाम गिरने पर भी किसानों को नुकसान न हो।
- **शुरुआत-वर्ष** 1966-67 में/ सबसे पहले गेहूँ के लिए
- **सिफारिशकर्ता संस्था**-कृषि लागत और मूल्य आयोग
- **अनुमोदन संस्था**-आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
- **नोडल खरीद एजेंसी**-भारतीय खाद्य निगम
- **फसलें**- कुल 22 अनिवार्य फसल के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है-
- **खरीफ फसलें (14)-**
  - अनाज-धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी।
  - दलहन-अरहर (तूर), मूंग, उड़द।
  - तिलहन-मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजरसीड, अरंडी-कपास।
- **रबी फसलें (6)-**
  - अनाज-गेहूँ, जौ।
  - दलहन-चना, मसूर।
  - तिलहन-सरसों/राया, कुसुम
- **अन्य व्यावसायिक फसलें (2)-** कच्चा जूट, खोपरा
- **गन्ना (1)-**
  - गन्ने के लिए एमएसपी के बजायउचित और लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है, जो गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के तहत सांविधिक है।
- उद्देश्य-
  - किसानों को मूल्य जोखिम से सुरक्षा (कृषि आय की स्थिरता)।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न प्राप्त करना।
  - किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।

सुर्खियों में- मेक इन इंडिया- मेक इन इंडियाके 12 साल पूर्ण-



- लॉन्च तिथि- 25 सितंबर,2014
- मंत्रालय/नोडल एजेंसी- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
- मूल उद्देश्य- भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में रूपांतरित करना।
- टैगलाइन- "Build in India, For the World" और "Zero Defect, Zero Effect"
- **लक्ष्य-**
  - विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादमें हिस्सा बढ़ाकर 25% करना।

- विनिर्माण क्षेत्र में प्रति वर्ष 12% से 14% की वृद्धि दर हासिल करना।
- 10 करोड़ अतिरिक्त विनिर्माण नौकरियों का सृजन करना।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और घरेलू निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित करना।

■ **स्तंभ-**

- **'मेक इन इंडिया' के 4 मुख्य स्तंभ-**

1. नई प्रक्रियाएं- 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ाना; नौकरशाही की अड़चनों को खत्म करना और प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण।
2. नया बुनियादी ढांचा-औद्योगिक गलियारों, स्मार्ट शहरों और अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स का विकास।
3. नए क्षेत्र- रक्षा, रेलवे, बीमा और मेडिकल डिवाइसेज जैसे क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमाओं को उदार बनाना।
4. नई सोच- सरकार की भूमिका को 'नियंत्रक' से बदलकर 'सुविधाप्रदाता' के रूप में स्थापित करना।

■ **मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र (27 क्षेत्र)-**

विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
एयरोस्पेस और रक्षा	सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट्स	पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
दवाइयां और चिकित्सा उपकरण	चिकित्सा मूल्य यात्रा
जैव-प्रौद्योगिकी	परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
पूंजीगत माल	लेखा एवं वित्त सेवाएँ
वस्त्र और परिधान	ऑडियो विजुअल सेवाएं
रसायन और पेट्रो रसायन	कानूनी सेवाओं
इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण	संचार सेवाएँ
चमड़ा और जूते	निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
खाद्य प्रसंस्करण	पर्यावरण सेवा
रत्न और आभूषण	वित्तीय सेवाएं
शिपिंग	शिक्षा सेवाएँ
रेलवे	
निर्माण	
नई और नवीकरणीय ऊर्जा	

■ **प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज की गई उपलब्धियाँ**

- **इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण-**
  - इलेक्ट्रॉनिक्स का कुल उत्पादन वर्ष 2014-15 के ₹1.9 लाख करोड़ से लगभग सात गुना बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹13.11 लाख करोड़ तक पहुँच गया।
  - 'मोबाइल फोन विनिर्माण योजना' के बल पर भारत दुनिया कादूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माताबन चुका है।
  - वर्तमान में देश में उपयोग होने वाले 99.2% मोबाइल फोनस्वदेशी रूप से निर्मित हैं। वर्ष 2025 में स्मार्टफोन देश की सबसे बड़ी निर्यातित उत्पाद श्रेणी बनकर उभरे हैं।
- **ऑटोमोबाइल उद्योग-** वर्ष 2024-25 में कुल वाहन उत्पादन 31.03 मिलियन यूनिट रहा, जो 2014-15 की तुलना में 33% अधिक है।
- **रक्षा एवं एयरोस्पेस स्वदेशीकरण -** वर्ष 2014-26 के दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादन का कुल मूल्य लगभग 283% बढ़ा।
- **भारी उद्योग (कच्चा इस्पात)-** राष्ट्रीय कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2014-15 के 81.7 मिलियन टन से दोगुने से अधिक बढ़कर वर्ष 2025-26 में 170.0 मिलियन टनपहुँच गया।
- **औषधि एवं चिकित्सा उपकरण-** भारत औषधि उत्पादन कीमात्रा में तीसरेऔरमूल्य में 11वेंस्थान पर है।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना-** 14 प्रमुख क्षेत्रों में लागू उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने जून 2026 तक ₹2.6 लाख करोड़ का निवेशआकर्षित किया तथा ₹23.8 लाख करोड़के उत्पादन एवं बिक्री को गति दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी-

■ 9 सितम्बर, 2026को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति ने रेल मंत्रालय की लगभग 10,021 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

■ यह परियोजनाएँ को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों के 17 जिलों में फैली हैं, इससे भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। यह स्वीकृत योजनाएं 'प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' के अंतर्गत बनाई गई हैं।

■ **स्वीकृत परियोजना-**

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मार्ग प्रकार	कुल लंबाई
1.	अरक्कोनम – रेनिगुंटा	तीसरी और चौथी लाइन	77 किमी
2.	व्हाइटफील्ड – बांगरपेट	तीसरी और चौथी लाइन	47 किमी
3.	होसुर – ओमालूर	दोहरीकरण	147 किमी
4.	सलेम – करूर – डिंडीगुल	दोहरीकरण	159 किमी
5.	सिकंदराबाद (घाटकेसर) से काजीपेट	मल्टीट्रैकिंग	110 किमी

ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म पर मूल प्रमाण पत्र के लिए ओपन एपीआई सुविधा प्रारम्भ-

- 7 सितम्बर, 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)ने ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करने और सत्यापन के लिए एक ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) सुविधा शुरू की है।
- यह ओपन एपीआई सुविधा निर्यातकों को अपने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अकाउंटिंग या अन्य व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर को सीधे डीजीएफटी के सीओओ सिस्टम के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाती है।
- वर्तमान में निर्यातकों को अपने व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर में मौजूद सीओओ विवरणों को डीजीएफटी प्लेटफॉर्म पर अलग से पुनः दर्ज करना पड़ता था। नई प्रणाली से निर्यातक के सिस्टम से डाटा सीधे डीजीएफटी प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो जाएगा।
- यह ओपन एपीआई प्रणाली मुख्य रूप से दो प्रकार के मूल प्रमाण पत्रों का समर्थन करती है-
  1. **वरीयता प्राप्त मूल प्रमाण पत्र-** उद्देश्य- यह मुक्त व्यापार समझौतों, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों और वरीयता प्राप्त व्यापार समझौतों के तहत जारी किए जाते हैं, ताकि निर्यातक आयातक देश में लागू शुल्क रियायतों का लाभ प्राप्त कर सकें।
  2. **गैर-वरीयता प्राप्त मूल प्रमाण पत्र-** उद्देश्य- यह सीमा शुल्क निकासी, अनुपालन, व्यापार उपचार और अन्य व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। इनमें कोई शुल्क लाभ/रियायत प्रदान नहीं की जाती है।

सुर्खियों में- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई)

- 1 सितम्बर, 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) की प्रगति की समीक्षा की।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-**
  - स्वीकृति तिथि- 16 जुलाई, 2025,
  - बजट-₹24,000 करोड़, समयावधि- 6 वर्ष
  - लक्ष्य-देश के कृषि क्षेत्र में कम प्रदर्शन करने वाले 100 जिलोंको लक्षित करना।
  - मुख्य ध्येय-फसल उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण, सिंचाई व भंडारण सुविधाओं में सुधार और आसान कृषि ऋण सुनिश्चित करना।

पीएम-सेतु- पांचवीं राष्ट्रीय संचालन समिति ने 735.70 करोड़ रुपये के एसआईपी को मंजूरी-

- 7 सितम्बर, 2026 को प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन कार्यक्रम (पीएम-सेतु) की पांचवीं राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की बैठक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
- स्वीकृत रणनीतिक निवेश योजनाएं- 3 राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना) में आईटीआई क्लस्टरों के लिए₹735.70 करोड़ के कुल परियोजना परिव्यय को मंजूरी दी गई।

स्वीकृत आईटीआई क्लस्टरों का विवरण-

राज्य	स्वीकृत राशि	मुख्य हब आईटीआई	संबद्ध आईटीआई	एंकर/उद्योग भागीदार
राजस्थान	₹241.00 करोड़	सरकारी आईटीआई भिवाड़ी	अलवर, नीमराना, तिजारा, किशनगढ़ बास	मेसर्स एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
तेलंगाना	₹254.30 करोड़	सरकारी आईटीआई मेडचल	अलवाल, शमीरपेट, कुकुनूरपल्ली, सिद्दीपेट	मेसर्स ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
उत्तर प्रदेश	₹240.40 करोड़	सरकारी आईटीआई (साकेत), मेरठ	गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

- **राजस्थान की विशेष उपलब्धि-**
  - राजस्थान, पीएम-सेतु योजना के तहत शेयर धारक समझौते को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे भिवाड़ी आईटीआई क्लस्टर में कायाकल्प की औपचारिक शुरुआत हो गई है।
- **पीएम-सेतु (PM-SETU)-**
  - पूरा नाम- प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन उन्नत आईटीआई , नोडल मंत्रालय- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
  - उद्देश्य- उद्योग साझेदारी, आधुनिक बुनियादी ढांचा, उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम और बेहतर रोजगार परिणामों के माध्यम से देश की आईटीआई प्रणाली का रूपांतरण करना।
  - एक 'हब आईटीआई' को कई 'स्पोक आईटीआई' के नेटवर्क से जोड़कर उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।



ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट



तिथि-
16 सितंबर 2026, नई दिल्ली

जारीकर्ता-
नीति आयोग

संदर्भित अवधि-
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल - जून 2026)

प्रमुख निष्कर्ष

1 वैश्विक एवं भारतीय व्यापार परिदृश्य (वैश्विक व घरेलू रुझान)

वैश्विक वस्तु व्यापार

- वर्ष 2026 की पहली छमाही में वैश्विक वस्तु व्यापार **13.7 ट्रिलियन डॉलर** तक पहुँच गया, जिसमें साल-दर-साल **12.5 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई।

वैश्विक सेवा व्यापार

- सेवाओं के वैश्विक व्यापार में **10.5 प्रतिशत** की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

भारत का कुल व्यापार

- भारत में वस्तु एवं सेवा का कुल व्यापार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में **506.9 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया, जिसमें वार्षिक आधार पर **15.5 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज हुई।

2 भारत का वस्तु व्यापार और प्रमुख रुझान

प्रमुख निर्यात क्षेत्र

- मिनरल फ्यूल (खनिज ईंधन), इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूलिल्यर रिएक्टर, लोहा एवं इस्पात तथा गाड़ियों का विशेष योगदान रहा।

आयात रुझान

- औद्योगिक और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक घटकों तथा तांबे के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

व्यापारिक गंतव्य

- तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका भारत के शीर्ष दस बाजारों के रूप में उभरे हैं।

आयात स्रोत

- कच्चे तेल की खरीद में विविधता के लिए लैटिन अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका से आयात बढ़ा। उत्तर-पूर्व एशिया, एक्सिम एशिया-जीसीसी और आसियान क्षेत्र भारत के कुल आयात का लगभग आधा हिस्सा रहे।

एफटीए साझेदारों के साथ प्रदर्शन

- एफटीए साझेदारे देशों को होने वाले निर्यात में **36.3 प्रतिशत** और आयात में **10.0 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई।

3 डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाएं

- भारत से डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज का निर्यात वर्ष 2024 के **277 बिलियन डॉलर** से बढ़कर वर्ष 2025 में **317 बिलियन डॉलर** हो गया।

वैश्विक रैंकिंग

- वैश्विक स्तर पर भारत अब **चौथे स्थान** (अमेरिका, ब्रिटेन एवं आयरलैंड) पर आ गया है।

4 धातु एवं अयस्क व्यापार

निर्यात स्थिति

- वर्ष 2025 में धातुओं का कुल निर्यात **34.8 बिलियन डॉलर** रहा। इसमें लोहा और इस्पात, लोहा-इस्पात की वस्तुएं और एल्यूमिनियम की हिस्सेदारी लगभग **78 प्रतिशत** रही।

आयात स्थिति

- धातुओं एवं अयस्कों का आयात वर्ष 2015 के **32.2 बिलियन डॉलर** से बढ़कर वर्ष 2025 में **60.5 बिलियन डॉलर** हो गया।

सुर्ख़ियों में

पीएम विश्वकर्मा योजना के तीन वर्ष पूर्ण-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार

पीएम विश्वकर्मा योजना
कौशल · सम्मान · समृद्धि



भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की तीसरी वर्षगांठ **17 सितंबर, 2026** को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित धोलो धान्यो सभागार में मनाई गयी।

पीएम विश्वकर्मा योजना-

शुभारंभ तिथि-
17 सितंबर 2023

संबंधित मंत्रालय-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

कार्यान्वयन अवधि:
वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 (5 वर्ष)।

कुल बजट आवंटन-
₹13,000 करोड़।

लक्ष्य-
30 लाख पारंपरिक दस्तकारों एवं कामगारों को वित्तीय व कौशलात्मक सहायता प्रदान करना।

उद्देश्य- असंगठित क्षेत्र के पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को संस्थागत सहायता, कौशल उन्नयन, आधुनिक टूलकिट, रियायती ऋण, डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना।

इस योजना के तहत **18 चिन्हित पारंपरिक व्यवसायों** (जैसे- बधाई, लोहार, सुनार, दर्जी आदि) में लगे कारीगरों एवं शिल्पकारों (विश्वकर्माओं) को **संपूर्ण** सहायता प्रदान की जाती है।

कौशल विकास व स्टाइपेंड-

- **बेसिक स्किल ट्रेनिंग-** 5 से 7 दिवसीय प्रशिक्षण, जिसमें ₹500 प्रतिदिन का स्टाइपेंड दिया जाएगा।
- **एडवांस स्किल ट्रेनिंग-** 15 दिवसीय प्रशिक्षण, जिसमें ₹500 प्रतिदिन का स्टाइपेंड दिया जाएगा।

टूलकिट सहायता-

आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु ₹15,000 की वित्तीय सहायता।



रियायती ऋण सहायता (MSME मंत्रालय- बैंकों के माध्यम से)-

- **प्रथम अंशा-** **₹1 लाख** तक का कोलेट्रल फ्री (गारंटी मुक्त) ऋण (अवधि- 18 माह)।
- **द्वितीय अंश-** **₹2 लाख** तक का अतिरिक्त ऋण (अवधि- 30 माह)।
- **ब्याज दर-** लाभार्थी से केवल 5% वार्षिक ब्याज लिया जाएगा। शेष 8% तक की सब्सिडी भारत सरकार वहन करेगी।



ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम समझौता-

- 11 सितम्बर, 2026 को ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य कोचीन में इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी (आईएसआरएफ) के संचालन और विस्तार के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर हुए है।
- यह समझौता 'इंडिया मैरीटाइम वीक 2025' के दौरान दोनों संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर आधारित है।
- हिस्सेदारी- 50:50 (डीपी वर्ल्ड की कंपनीड्राईडॉक्स वर्ल्ड औरकोचीन शिपयार्ड लिमिटेड)
- यह समझौता कोचीन को एक प्रमुख वैश्विक समुद्री सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करेगा और केरल में पोत मरम्मत, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

विविध तथ्य

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांच राज्यों (उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और त्रिपुरा) के लिए 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' तथा 'कृषोन्नति योजना' के तहत कुल 1,183.11 करोड़ रुपए की द्वितीय मदर सैंक्शन जारी करने की मंजूरी दीहै।
- ई-मार्केटप्लेस (जेम) और कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत टेक्सटाइल कमेटी (टीसी) ने सार्वजनिक खरीद के माध्यम से प्री-और पोस्ट-कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट, कतरन और पुराने कपड़ों से बने रीसाइक्ल्ड और अपसाइक्ल्ड उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाथसमझौता ज्ञापनपर हस्ताक्षरित किया है।
- बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026 के प्रावधान 1 अक्टूबर,2026 से लागू होंगे। इसे 13 अगस्त,2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी जो बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 1891 की जगह लेगा। यह समकालीन बैंकिंग तरीकों के अनुरूप बैंकिंग रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक आधुनिक व्यवस्था प्रदान करता है।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 20 अक्टूबर,2026 से लागू होगा। इस एफटीए पर 27 अप्रैल 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री माननीय टॉड मैक्ले द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 28 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 'लाइवस्टॉक इंश्योरेंस पोर्टल' (पशुधन बीमा पोर्टल) का शुभारंभ किया गया।
- जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड' ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB+से बढ़ाकर A-कर दिया है।
- सेबी ने 'डिमैट 2.0' पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड को डिजिटल टोकन में बदला जाएगा, जिससे एटॉमिक सेटलमेंट के जरिए लेनदेन तुरंत पूरा होगा। इसके लिए RBI की डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा। भारत डिजिटल लेजर पर बॉन्ड जारी कर डिजिटल करेंसी से सेटलमेंट करने वाला पहला देश बन गया है।
- सरकार ने ओडिशा के पारादीप पोर्ट को मेगा पोर्ट का दर्जा दिया है। यह फैसला भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 की धारा-73 के तहत लिया गया। इसके साथ देश में मेगा पोर्ट की सूची में पारादीप के अलावा दीनदयाल पोर्ट (कांडला), जवाहर लाल नेहरू पोर्ट (न्हावा शेवा) और मुंद्रा पोर्ट शामिल हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

रक्षा प्रौद्योगिकी

आईएनएस निपुण-

- भारतीय नौसेना ने 31 अगस्त, 2026 को मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत आईएनएस निपुण को नौसेना में शामिल किया है।यह अपने सहयोगी पोतआईएनएस निस्तार के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- निर्माता- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम
- लम्बाई- 119.4 मीटर, वजन- 10,500 टन वजनी
- यह पोत सैचुरेशन डाइविंग, एयर डाइविंगऔर हेलिओक्स डाइविंगमें सहायता प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम है।
- रिमोट ऑपरेशन्स-पानी के नीचे जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए दूर से संचालित प्रणालियों से लैस।

इलेक्ट्रिक इंटरसेप्टर ड्रोन 'आहुति Mk-II'-



- हाल ही में हैदराबाद स्थित रक्षा-प्रौद्योगिकी स्टार्टअपअपोलियन डायनेमिक्स द्वारा विकसित इलेक्ट्रिक इंटरसेप्टर ड्रोन 'आहुति Mk-II' ने 498 किमी प्रति घंटेकी प्रमाणित अधिकतम गति हासिल की।
- इस उपलब्धि कोइंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारत में किसी भी मल्टी-रोटर मानव रहित हवाई वाहन द्वारा प्राप्त अब तक कीसर्वाधिक गतिके रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है।
- यह एक उच्च-गति मल्टी-रोटर इंटरसेप्टर ड्रोन है, जिसे आने वाले हवाई खतरों तथा दुश्मन के ड्रोनों को हवा में ही तेजी से नष्ट (इंटरसेप्ट) करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

खगांतक-243

- 2 सितंबर, 2026 को भारतीय वायु सेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी के ग्लाइड बम खगांतक-243 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- परीक्षण स्थल- पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान
- लॉन्च प्लेटफॉर्म-सुखोई Su-30MKI लड़ाकू विमान
- मारक क्षमता- लगभग 12 किमी की ऊंचाई से छोड़े जाने पर यह बम 144 किलोमीटर से 180 किलोमीटरकी दूरी पर स्थित लक्ष्य को सटीक रूप से भेदने में सक्षम है।
- **वजन एवं वॉरहेड-**
  - कुल वजन- लगभग 300 किलोग्राम।
  - वॉरहेड- इसमें 125 किलोग्रामक्षमता का शक्तिशाली Mk-81 जनरल-पर्पस वॉरहेडलगा हुआ है।
- निर्माण- इसे नागपुर स्थित स्टार्टअप कंपनीजेएसआर डायनेमिक्स ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है।

एके-203 असॉल्ट राइफल-

- हाल ही में अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने एके-203 असॉल्ट राइफलों के लिए पाँच साल तक गोला-बारूद सप्लाई करने के लिए इंडो-रशियन राइफल्स प्रा. लि. (आईआरआरपीएल) से समझौता किया है। इसके तहत आईआरआरपीएल को भारत में निर्मित 7.62x39 मिमी गोला-बारूद मिलेगा।
- एके-203 राइफल अमेठी के कोरवा प्लांट में बनती है।
- **एके-203 असॉल्ट राइफल-**

मूल राइफल मॉडल	AK-47 का नवीनतम संस्करण
कारतूस	7.62 × 39 मिमी.
प्रतिस्थापित होने वाली प्रणाली	INSAS (भारतीय लघु हथियार प्रणाली- 5.56×45 मिमी.)
लाभार्थी	भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना एवं अन्य सुरक्षा बल
उद्देश्य	गन जैमिंग दूर करना व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में परिचालन दक्षता बढ़ाना

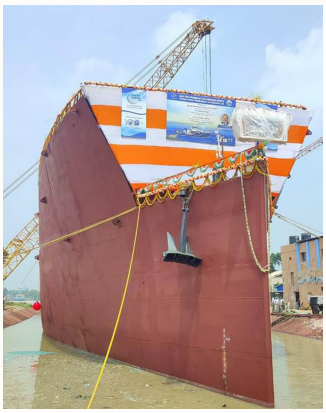
हनुमंता एक्सो 1.2-



- हाल ही में राजस्थान के कोटा निवासी इंजीनियरगौरव राय की टीम ने भारतीय सैन्य बलों के जवानों के लिए एक अत्याधुनिक एडवांस ह्यूमन एक्सोसूट का नया मॉडल 'हनुमंता एक्सो 1.2' तैयार किया है।

- यह नवोन्मेष रक्षा मंत्रालय की आईडीईएक्स परियोजना और अदिति प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है।
- एक्सोसूट का उद्देश्य- कठिन और विषम परिस्थितियों में भारी सैन्य सामान उठाते समय सैनिकों पर पड़ने वाले शारीरिक दबाव, मांसपेशियों के तनाव और थकान को अत्यधिक कम करना।
- भार वहन क्षमता- 100 किलो से लेकर 200 किलो तक
- कार्यप्रणाली- यह 'डेल्टा स्प्रिंग सिस्टम' की कार्यप्रणाली पर आधारित है। यह प्रणाली सैनिक के शरीर पर आने वाले अत्यधिक भार को उसके जूतों के माध्यम से सीधे जमीन की ओर स्थानांतरित कर देती है, जिससे शरीर पर भार का अहसास न्यूनतम हो जाता है।

ओआरवी सागर मंथन- भारत का पहला उन्नत स्वदेशी महासागर अनुसंधान पोत लॉन्च-



- लॉन्च तिथि- 9 सितंबर, 2026
- लॉन्च स्थल-ऋषि बंकिम शिपयार्ड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
- पोत का आधिकारिक नाम-ओआरवी सागर मंथन-यार्ड 3041
- सेवा अवधि-30 वर्ष
- लागत-लगभग₹840 करोड़।
- पोत निर्माता संस्था-गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम)
- संबंधित नोडल संस्था-राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र, गोवा
- मंत्रालय-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- ओआरवी सागर मंथन का निर्माण भारत सरकार के प्रमुख डीप महासागर मिशन केवर्टिकल-4 (गहन महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण) के तहत किया गया है।
- यह सर्व-मौसम अनुकूल, बहुविषयक अनुसंधान पोत है।
- यह आधुनिक पोत वर्ष 1983 में जर्मनी से खरीदे गए अनुसंधान पोत 'ओआरवी सागर कन्या' का स्थान लेगा।
- यह पोत डायनामिक पोजिशनिंग, मल्टीबीम बाथिमेट्री, मल्टीचैनल भूकंपीय प्रणाली, सब-बॉटम प्रोफाइलिंग, मौसम रडार, ड्रॉप कील्स, और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्सव ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्सकी तैनाती की सुविधाओं से पूरी तरह लैस है।

अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी

अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट-05



- प्रक्षेपण तिथि- 4 सितंबर 2026
- एजेंसी- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
- स्थल- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा
- यान- GSLV-F17 (भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान)
- **उपग्रह की प्रमुख विशेषताएँ-**
  - उपनाम- आई इन द स्काई
  - भार- 2,367 किलोग्रामहै।
  - यह उपग्रह उन्नत ऑप्टिकल और इंफ्रारेड इमेजिंग पेलोड से लैस है, जो निरंतर और वास्तविक समय में तस्वीरें और डेटा उपलब्ध कराने में सक्षम है।
  - यह भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह है, जिसे भू-समकालिक कक्षा से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह GSLV-F17 भारत के भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यानकी 19वीं परिचालन उड़ानहै।

जीआइसैट-1ए (EOS-05) का पहला कक्षा परिवर्तन व सेमीक्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट-

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइटजीआइसैट-1ए (GISAT-1A / EOS-05) के प्रक्षेपण के पश्चात उसकी कक्षा में पहला सफल बदलाव पूरा किया है।
- इसके साथ ही, इसरो ने महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्समें अपनेसेमीक्रायोजेनिक इंजनका 100% थ्रस्ट स्तर पर पहला सफल हॉट टेस्ट भी आयोजित किया।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन 2026-



- आयोजन तिथि- 9-10 सितंबर, 2026

- आयोजन स्थल-पेरिस, फ्रांस
- भागीदारी-लगभग 120 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया
- यह पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन था
- उद्देश्य- राजनीतिक नेताओं, अंतरिक्ष एजेंसियों, वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष यात्रियों, कंपनियों, निवेशकों और अन्य हितधारकों को तेजी से बदलते अंतरिक्ष क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन 2026 में अंतरिक्ष स्थिरता, अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और अंतरिक्ष वाणिज्यीकरण के पहलूओं पर विचार किया गया।

भीममॉडल-

- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु के वैज्ञानिकों और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने मिलकर 'भीम' (BHIM) नाम से एक स्वदेशी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हैबिटेट मॉडल तैयार किया है।
- यह मॉडल चांद और मंगल ग्रह पर भावी इंसानी बस्तियां बसाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- **भीम-**
  - BHIM- Bharatiya Extraterrestrial Expandable Modular Habitat
  - यह परियोजना फिलहाल डिजाइन-कॉन्सेप्ट चरण में है।

जैव-प्रौद्योगिकी, सूचना-प्रौद्योगिकी व अन्य प्रौद्योगिकी

स्टैनफोर्ड का 'OceanOneK'-

- स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रोबोटिक्स लैब ने एक अत्याधुनिक ह्यूमनॉइड अंडरवॉटर रोबोट 'OceanOneK' विकसित किया है।
- यह रोबोट समुद्र के भीतर लगभग 1,000 मीटर (1 किलोमीटर)की अत्यधिक गहराई तक जाकर उन दुर्गम स्थलों की खोज करने में सक्षम है, जहाँ इंसानों का पहुँचना बेहद कठिन और जोखिम भरा होता है।
- उच्च दबाव सहन करने की क्षमता-सतह की तुलना में 100 गुना तक
- यह रोबोट 3D कैमरों और हैप्टिक फीडबैक सिस्टम से लैस है।

धाव-हाइरोबोट डॉग-

- बेंगलूरु स्थित डीप-टेक कंपनी 'एक्सटेरा रोबोटिक्स' ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी , कानपुर के शोध एवं तकनीकी सहयोग से एक विशेष रोबोट डॉग विकसित किया है। इस स्वदेशी रोबोट का नाम 'धाव-हाइ' रखा गया है।
- पहिए और पैर का कॉम्बिनेशन-यह हाइब्रिड रोबोट है, जिसमें इसकेचार पैरों के साथ पहियोंका प्रयोग किया गया है।
- यह रोबोट समतल सड़कों पर पहियों की मदद से तेजी से दौड़ सकता है। वहीं, सामने सीढ़ियां, ढलान या ऊबड़-खाबड़ जमीन आने पर यह तुरंत अपने पैरों की मदद से रास्ता बदल लेता है।
- अधिकतम रफ्तार- 5 मीटर प्रति सेकंड
- भार वहन क्षमता- 10 किलोग्राम

विविध तथ्य

- भारतीय नौसेना के नौवहन प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शिनी ने 'लोकायन-26' अभियान के तहत 6 सितंबर 2026 को स्पेन के बार्सिलोना में अपनी यात्रा पूरी की।
- हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI-DST का स्वायत्त संस्थान), कैलगरी विश्वविद्यालय और लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ने क्वांटम एंटैंगलमेंट के क्षय को रोकने हेतु नई तकनीक की खोज की है।
- सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक अमीनो एसिड (एस्पार्टिक एसिड) को प्रकाश-अवशोषित करने वाले कार्बनिक अणु 'पेरीलीन डायइमाइड' के साथ सुप्रामॉलिक्यूलर स्व-संयोजन द्वारा जोड़कर पूर्णतः धातु-मुक्त प्रकाश-उत्प्रेरक का विकास किया है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टेम सेल थेरेपी के नियमन पर परामर्श जारी किया है। अब स्टेम सेल थेरेपी को नियमित नैदानिक अभ्यास के रूप में केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सूची में शामिल बीमारियों/स्थितियों के लिए ही इस्तेमाल की अनुमति है।
- भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी की मिसाइल पोत (एनजीएमवी) परियोजना के पहले पोत का कील-लेइंग समारोह 18 सितंबर, 2026 को कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में आयोजित किया गया।
- अभयरैब- यह एंटी-रेबीज वैक्सीन है। हाल ही में डीसीजीआई ने इस वैक्सीन की बिक्री, सप्लाई और उपलब्धता पर निगरानी के निर्देश दिए हैं।
- एडमिरल नखिमोव-यह रूस का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला और दुनिया के सबसे खतरनाक व सबसे बड़े मिसाइल युद्धक्रूज़र में से एक है।

- भारत 6जी नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों की अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ। इसका लक्ष्य ऐसी 6-जी तकनीक बनाना है, जो सुरक्षित हो और समान सुरक्षा हितों वाले देशों के बीच काम करे। 6जी में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड डिवाइस, एआई और कम लेटेंसी वाली कम्युनिकेशन तकनीक होगी।
- इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि में CE20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया।
- नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने चांद पर नया विशाल क्रेटर खोजा। वैज्ञानिक थॉमस मैकगेचिन के नाम पर इसका नाम रखा है। यह 728 फीट चौड़ा और 141 फीट गहरा है। यह करीब दो साल पहले एस्टेरॉयड या धूमकेतु के टकराने से बना।
- लद्दाख के लेह में 10,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा 'द्विन फ्लावर फील्ड' शुरू हुआ। चोगलमसार और स्टाकना में 40 एकड़ में फैले इस फील्ड में लिलियम और ग्लेडियोलस के 25 लाख से ज्यादा फूल हैं। इसका उद्देश्य ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में वैज्ञानिक खेती का मॉडल बनाना है।
- ओडिशा सरकार ने नारज में 870 एकड़ में 'ओडिशा सिलिकॉन वैली' बनाने की घोषणा की है।
- हाल ही में ब्रिटेन ने अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए एक नई मिलिट्री स्पेस यूनिट बनाई है। इस नई यूनिट का नाम 'नंबर-III स्पेस इफेक्ट्स स्क्वाड्रन' रखा गया है। यह ब्रिटेन की पहली ऐसी स्पेशल विंग है जो दुश्मन के हमलों से अपने उपग्रहों की रक्षा करेगी।
- एंथ्रोपिक के एआई मॉडल क्लॉड ने डीएनए डेटा से 'एआरटी' नाम का एंजाइम सिस्टम खोजा है। एआरटी जीन एडिटिंग में इस्तेमाल होने वाली क्रिस्पर तकनीक के पैटर्न जैसा है।
- 28 सितंबर, 2026 को स्पेसएक्स के शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप ने अपनी 14वीं परीक्षण उड़ान के दौरान पहली बार पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचकर इतिहास रचा है।



खेल परिदृश्य

क्रिकेट

महिला टी-20 एशिया कप, 2026-



- संस्करण- 10वाँ संस्करण
- आयोजन तिथि- 28 अगस्त से 13 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
- आयोजक- एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC)
- परिणाम
  - विजेता- भारत
  - उपविजेता- श्रीलंका
  - भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता।
- भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही।
- प्लेयर ऑफ द मैच-शेफाली वर्मा
- भारत की दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 14 विकेट हासिल किए। वे महिला एशिया कप इतिहास की सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज (कुल 40 विकेट) बनीं।

अभिषेक शर्मा सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने-

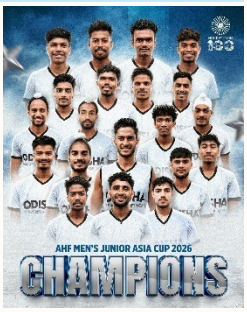
- भरत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में सिर्फ 30 गेंद में शतक जड़ दिया।
- वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे व भारत के पहले बल्लेबाज बने।

महिला टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027-

- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी परिवर्तन करके भारत को सौंप दी है।
- आयोजन- 14 से 28 फरवरी, 2027
- पूर्व में इस प्रतियोगिता का आयोजन श्रीलंका में होना प्रस्तावित था।
- मेजबानी परिवर्तन का कारण- श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में सरकारी दखल और प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण आईसीसी ने वहां से मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए।
- आयोजन स्थल-
  1. मुंबई-क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) ग्राउंड
  2. वडोदरा-इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

हॉकी

पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2026-



- आयोजन तिथि- 4 से 13 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल-मोकी, चीन
- परिणाम-
  - विजेता- भारत
  - उपविजेता- दक्षिण कोरिया
  - भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से पराजित कर खिताबी जीत हासिल की।
  - भारतीय पुरुष टीम ने रिकॉर्ड छठी बार (2004, 2008, 2015, 2023, 2024, 2026) यह खिताब अपने नाम किया।
- **प्रमुख व्यक्तिगत प्रदर्शन:**
  - अनमोल एक्का-
    - भारतीय टीम के कप्तान।
    - कुल 17 गोल करके टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे।
  - विवेक लाकड़ा- भारत के विवेक लाकड़ा को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर चुना गया।

महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2026-



- आयोजन तिथि- 4 से 13 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- मोकी, चीन
- **परिणाम-**
  - विजेता- भारत
  - उपविजेता- चीन
  - भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने खिताबी मुकाबले में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर खिताबी जीत हासिल की।
  - भारतीय महिला टीम ने लगातार तीसरी बार महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता।

- **प्रमुख व्यक्तिगत प्रदर्शन-**
  - निधि- भारत कीनिधिको प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर घोषित किया गया।
  - सानिका चंद्रकांत माने- भारतीय खिलाड़ी सानिका चंद्रकांत माने (7 गोल) प्रतियोगिता की प्रमुख गोल स्कोरर में शामिल रहीं।

FIH यूथ हॉकी 5s वर्ल्ड कप-

- इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पहला यूथ हॉकी 5s वर्ल्ड कप आयोजित करने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का पहला संस्करण 7 से 12 दिसंबर, 2026तक मिस्र के इस्माइलिया शहर में खेला जाएगा।

पोलिग्रास मैजिक स्किल अवॉर्ड-

- भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपरबिचु देवी और पाकिस्तान के स्ट्राइकर अब्दुल रहमान ने हाल में हुए वर्ल्ड कप के पोलिग्रास मैजिक स्किल अवॉर्ड जीते।
- बिचु देवी को इंग्लैंड के खिलाफ पूल मैच के आखिरी मिनट में किए गए शानदार रिफ्लेक्स सेव के लिए अवॉर्ड मिला।

टेनिस

यूएस ओपन 2026-

- संस्करण- 146वां
- आयोजन तिथि- 23अगस्त से 13 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- न्यूयॉर्क शहर, यूएसए (हार्डकोर्ट पर)
- यूएस ओपन 2026 विजेता सूची

वर्ग	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	अलेक्जेंडर ज़्वेरेव (जर्मनी)	बेन शेल्टन (अमेरिका)
महिला एकल	एलेना राइबाकिना (कजाकिस्तान)	आर्यना सबालेंका (बेलारूस)
पुरुष युगल	क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कूप्सकी	टिम पुट्ज़ और केविन क्राविट्ज
महिला युगल	केटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड	रॉबिन मोंटगोमेरी और एशलीन क्रूगर

बैडमिन्टन

चाइना मास्टर्स सुपर 750-

- भारत की पुरुष युगल जोड़ीसात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टीनेचाइना मास्टर्स सुपर 750बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। वर्ष 2005 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह भारत कीपहली ट्रॉफीहै।
- परिणाम-
  - विजेता- सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी (भारत)
  - उपविजेता- टिंग और रेन जियांग यू (चीन)

एथलेटिक्स

राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026-



- संस्करण- 21वीं
- आयोजन तिथि- 1 सितंबर से 3 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल-लुधियाना (पंजाब)
- आयु वर्ग- अंडर-18 आयु वर्ग
- पदक तालिक-

	राज्य	🥇	🥈	🥉	कुल
1	हरियाणा	4	7	3	14
2	महाराष्ट्र	3	3	2	8
3	कर्नाटक	3	2	0	5
4	तमिलनाडु	2	4	3	9
5	उत्तर प्रदेश	2	3	3	8
6	पंजाब	2	2	1	5
7	मध्य प्रदेश	2	1	2	5
8	तेलंगाना	2	0	2	4
9	पश्चिम बंगाल	1	3	1	5
10	राजस्थान	1	0	3	4

Note- राजस्थान के साहिल ने बालक वर्ग में (दौड़) में पहला स्थान हासिल करके स्वर्ण पदक जीता है।

शतरंज

निहारिका बनीं 'वुमन इंटरनेशनल मास्टर'-

- आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले की 26 वर्षीय निहारिका चल्लाने शतरंज में 'वुमन इंटरनेशनल मास्टर' का प्रतिष्ठित टाइटल हासिल किया है।
- महिला शतरंज में वुमन इंटरनेशनल मास्टरकी पदवी ग्रैंडमास्टर के बाद दूसरी सबसे बड़ी पदवीमानी जाती है।
- निहारिका भारत की 44वीं महिलाहैं जिन्हें यह टाइटल मिला है। इससे पहले वर्ष 2023 मेंनिमी ए जॉर्जने यह मुकाम हासिल किया था।

एलीना मिश्रा-



- यह ओडिशा की चार साल की सबसे कम उम्र की शतरंज महिला खिलाड़ी है। वह इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की ऑफिशियल रेटिंग लिस्ट में जगह बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
- एलेना ने यह उपलब्धि 4 साल, 6 महीने और 16 दिन की उम्र में हासिल की।

तीरंदाजी

वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026-



- आयोजन तिथि- 4 से 9 सितंबर, 2026
- **आयोजन स्थल-** अहमदाबाद
- अहमदाबाद: भारतीय पदक विजेता
- भारत ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते।
- **श्रेणी और पदक विजेता-**
- **गोल्ड**
  - वूमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड- शीतल देवी
  - मेंस कंपाउंड डबल्स - टोमन कुमार, श्याम सुंदर स्वामी
  - मेंस रिकर्व डबल्स - हरविंदर सिंह, विजय सुंडी
  - रिकर्व मिक्स्ड टीम - भावना, हरविंदर सिंह
- **सिल्वर**
  - वूमेंस रिकर्व डबल्स - भावना, पूजा
  - W1 मिक्स्ड टीम - स्वाति चौधरी, आदिल मोहम्मद नज़ीर अंसारी
  - दृष्टिबाधित - तन्वी प्रवीण इंगले
- **ब्रॉन्ज**
  - वूमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड- सरिता
  - मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड- टोमन कुमार
  - कंपाउंड मिक्स्ड टीम - शीतल देवी, टोमन कुमार
  - वूमेंस इंडिविजुअल रिकर्व- भावना
  - W1 वूमेंस इंडिविजुअल- स्वाति चौधरी
  - W1 मेंस डबल्स- आदिल मोहम्मद नज़ीर अंसारी, नवीन दलाल
  - W1 वूमेंस डबल्स- स्वाति चौधरी, वसुंधरा तेवतिया
  - दृष्टिबाधित- युगल गर्ग

धीरज बोम्मदेवरा-

- भारत के 25 वर्षीय तीरंदाजधीरज बोम्मदेवराने आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में पुरुष रिकर्व स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है।
- धीरज ने फाइनल मुकाबले के बेहद कड़े 'शूट-ऑफ' में जापान केजुन्या नाकानिशी को पराजित कर यह खिताब अपने नाम
- धीरज वर्ल्ड कप फाइनल में पुरुष रिकर्व स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाजबन गए हैं।

फुटबाल

लियोनेल मेसी-

- यह अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है।
- इनकी कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 फीफा विश्व कप जीता। उन्होंने 207 मैचों में 125 गोल किए व अंतरराष्ट्रीय गोल में रोनाल्डो के बाद दूसरे नंबर पर हैं।

मार्कोस लोरेंटे-

- यह स्पेनिश फ़ुटबाल खिलाड़ी है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है।
- यह एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेलना जारी रखेंगे।

तैराकी

नेशनल मास्टर्स तैराकी-2026

- संस्करण- 22वां
- आयोजन तिथि- 11 से 13 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- एचएल सिटी स्थित चैंपियन एक्वेटिक्स अकादमी, हरियाणा
- आयोजक- स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन

अन्य

अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड-2026

- संस्करण- 19वां
- आयोजन तिथि 20 से 27 अगस्त,2026
- आयोजन स्थल-तुरिन (इटली)
- आयोजक संस्था-अंतरराष्ट्रीय भूविज्ञान संगठन
- प्रतिभागी देश- 39 देशों के छात्रों ने इस वैश्विक स्पर्धा में भाग लिया।
- भारत का प्रदर्शन-भारतीय छात्र प्रतिनिधियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुल 9 पदक (4 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य) जीते है।
- **पदक विजेता-**

❑ सौमिकमंडल (डीएवी मॉडल स्कूल, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल)	2 स्वर्ण, 1 रजत
❑ एरन मैती (डीएवी मॉडल स्कूल, आईआईटी-खड़गपुर, पश्चिम बंगाल)	1 स्वर्ण, 1 कांस्य
❑ ऋद्धि रंजन (ज्ञान अस्थली इंटरनेशनल स्कूल, पटना, बिहार)	1 स्वर्ण, 1 रजत
❑ मोहम्मद एहतेषाम रिज़वी (जवाहर नवोदय विद्यालय, बिहार)	1 रजत, 1 कांस्य

वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता-

- संस्करण- 48वां
- आयोजन तिथि- 22 से 27 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- शंघाई, चीन
- **भारतीय दल-**
  - ❑ टीम स्किल इंडिया ने 64में से 63 कौशलों में लगभग 70 प्रतियोगियों के दल के साथ भाग लिया।
  - ❑ यह वर्ल्डस्किल्स में भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विविध प्रतिनिधित्व है।
  - ❑ नेतृत्वकर्ता निकाय- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।
- भारत ने ग्यारह नए कौशलों में पहली बार प्रतिस्पर्धा की है।
- इस प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और 20 उत्कृष्टता पदक जीतकर 10वां स्थान हासिल किया।
- **रजत पदक विजेता-**

क्रमांक	कौशल श्रेणी	प्रतियोगी
1	बेकरी	स्मृति नाम्बियार
2	डेंटल प्रोस्थेटिक्स	मोहम्मद सलाम
3	डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया डिज़ाइन	कोविड अजय गंगराडे
4	औद्योगिक डिजाइन प्रौद्योगिकी	पार्थ वोहरा
5	लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग	मेहरूनिसा बेगम
6	खुदरा बिक्री	सानिया जोशी

- **उत्कृष्टता पदक-**

	कौशल श्रेणी	प्रतियोगी
1	इंटेलिजेंट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी	रागुल कंथम्मा बलराज
2	मेकाट्रोनिक्स	दीपू मुदिगेरेपाल्या श्रीनिवास; जयन्त करियप्पा
3	मोबाइल एप्लिकेशन विकास	अर्जुन सुमति विजयबाशकर
4	इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन	धनुष मधुगिरी गोविंदराजू
5	प्लास्टरिंग और ड्राईवॉल सिस्टम	सुरेंथिरन मणि
6	पेंटिंग और सजावट	मुस्कान
7	ऑटोनोमस मोबाइल रोबोटिक्स	आदित्य प्रकाश; देबाशीष पांडा
8	कैबिनेट मेकिंग	यशवंथ चारी केशोजू
9	आभूषण	जॉय दास
10	सौन्दर्य उपचार	ताहेसिन साबिर सुतार
11	फैशन प्रौद्योगिकी	विधि निरवकुमार सुथार
12	ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी	एमडी सेराज
13	कार पेंटिंग	कैफ खान
14	आईटी नेटवर्क सिस्टम प्रशासन (आईटीएनएसए)	खुशराज निमेश राठौड़
15	ग्राफिक डिजाइन प्रौद्योगिकी	राजीब लोचन चंद
16	स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल	विष्णुप्रिया सुनील

17	उद्योग 4.0	मल्लिनाथ; सुहान मस्करेन्हा
18	रासायनिक प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	संपदा देसाई
19	एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग	पवन भद्रावती सुरेश
20	रोबोट सिस्टम एकीकरण	अभिषेक सोमन्ना शिगनल्ली; विनय मुत्तय्या हिरेमठ

- **अतिरिक्त तथ्य-**
  - वर्ष 2015 में वर्ल्डस्किल्स में 29वें स्थान से भारत वर्ष 2024 में 13वें स्थान पर पहुंच गया।
  - देश ने वर्ल्डस्किल्स एशिया-2025 में एशिया में 8वां स्थान हासिल किये और ताइपे कैपिटल कप-2026 में पांच पदक जीते है।

एशियाई खेल 2026-



- संस्करण- 20वां
- आयोजन स्थल- आइची-नागोया, जापान
- आयोजन तिथि- 19 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2026
- आधिकारिक स्लोगन- IMAGINE ONE ASIA
- आधिकारिक शुभंकर- होनोहोन
- प्रतिभागी देश- 46देशों और क्षेत्रों के 11,000 से अधिक एथलीट
- खेल विधा- 43
- भारतीय दल के शेफ डी मिशन- सहदेव यादव
- आयोजक संस्था- Aichi-Nagoya Asian Games Organizing Committee
- **एशियाई खेल-**
  - एशियाई खेल एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बहु-खेल (Multi-sport) प्रतियोगिता हैं, जिनका आयोजन प्रत्येकचार वर्षमें एक बार किया जाता है।
  - आयोजक संस्था- एशियाई ओलंपिक परिषद
  - **एशियाई खेलों का इतिहास-**
    - प्रथम आयोजन- एशियाई खेलों की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्वर्ष 1951 में
    - भारत की भूमिका- भारत के प्रथम प्रधानमंत्रीपंडित जवाहरलाल नेहरूने एशियाई खेलों के आयोजन की वकालत की थी।
- **उद्देश्य-**
  - द्वितीय विश्व युद्ध के कारण टूटे हुए एशियाई देशों के आपसी संबंधों को पुनर्जीवित व सुदृढ़ करना।
  - संपूर्ण एशिया महाद्वीप में स्थायी शांति स्थापित करने में योगदान देना।
  - प्रथम एशियाई खेलनई दिल्ली (भारत)में आयोजित किए गए थे।
  - जापान द्वारा मेजबानी-जापान में तीसरी बार आयोजन।
    - तीसरे खेल (वर्ष 1958)- टोक्यो
    - 12वें खेल (वर्ष 1994)- हिरोशिमा
    - 20वें खेल (वर्ष 2026)- आइची-नागोया
- नोट- एशियाई खेल 2026 की समापन तिथि 4 अक्टूबर, 2026 है, अत: पदक तालिका और अतिरिक्त जानकारी अगले माह की मैग्जिन में प्रकाशित की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय लेक्रोज प्रतियोगिता-

- आयोजन तिथि- 28 से 30 अगस्त 2026
- आयोजन स्थल- कुआलालंपुर (मलेशिया)
- भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया।भारतीय टीम ने सिंगापुर को 10-9 से पराजित कर पदक अपने नाम किया।
- **राजस्थान के खिलाड़ियों का योगदान-**
  - भारतीय लेक्रोज टीम में राजस्थान से कुल 15 खिलाड़ियों (महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में) का चयन हुआ था।
  - भारतीय महिला टीम में मुख्य रूप से उदयपुर संभाग और जनजातीय (ट्राइबल) क्षेत्र की 9 खिलाड़ियों- सुनीता मीणा, डाली गमेती, यशिष्ठा बत्रा, यशोदा गमेती, जुला कुमारी गुर्जर, मीरा दौजा, विशाखा मेघवाल, रोशनी बोस एवं जानवी राठौड़ने प्रतिनिधित्व किया।
  - पुरुष वर्ग में उदयपुर के ट्राइबल क्षेत्र के खिलाड़ी मोहनलाल गमेती, खुमाराम गमेती, दयाशंकर गमेती, नारायण लाल गमेती, निशांत नागदाऔर नागौर के शाहिद खान शामिल थे।

विश्व स्ट्रेंथलिफ्टिंग और इन्क्लाइन बेंच प्रेस (आईबीपी) चैंपियनशिप 2026-

- संस्करण- 13वां
- आयोजन स्थल- 8 से 12 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- किर्गिस्तान
- Note- जयपुर के लालचंदपुरा निवासी पवन कुमावत ने 85 किलो पुरुष भारवर्ग में रजत पदक जीता है।

कैटी टेलर-

- यह आयरलैंड की पूर्व पेशेवर मुक्केबाज और फुटबॉलर हैं।
- इन्होंने मुक्केबाजीसे संन्यास की घोषणा की है।

अरुंधति चौधरी-

- अंतरराष्ट्रीयमुक्केबाज अरुंधति चौधरी को हाल ही में एशिया बॉक्सिग कमेटी का निर्विरोध वाइस चेयरमैन चुना गया है।
- उनका कार्यकाल चार वर्ष का रहेगा। उन्होंने 28 सितंबर, 2026 को जापान के आइची-नागोया पहुंचकर पद की शपथ ली।

डायमंड लीग फाइनल 2026 (जैवलिन थ्रो)-

- डायमंड लीग 2026 के फाइनल में श्रीलंका के 23 वर्षीय एथलीटरुमेश थरंगाने भाला फेंक (जैवलिन थ्रो) स्पर्धा में 89.04 मीटर के शानदार प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता।
- वे यह प्रतिष्ठित डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए हैं।

जॉर्ज क्लूनी-

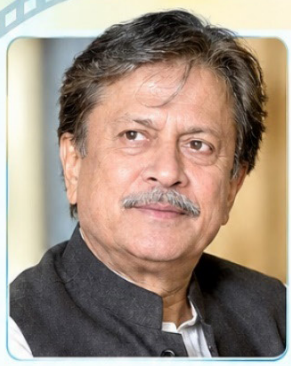
- ऑस्कर विजेता अभिनेता जॉर्ज क्लूनी को वेनिस फिल्म महोत्सव में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन से सम्मानित किया गया।

विविध तथ्य

- स्मृति मंधाना ने महिला एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ शतक बनाकर वह महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 शतक लगाने वाली बल्लेबाज बनीं और मेग लैनिंग का 17 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। वह सभी फॉर्मेट में 10,880 रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज भी बन गईं।
- भारतीय फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर भारत ने 20 साल के लंबे इंतजार के बाद एएफसी अंडर-20 एशियन कप के लिए क्वालीफाई किया है।
- भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने और सबसे ज्यादा शतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
- गुजरात ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए 301 करोड़ रुपए का बजट तय किया। इसमें 200 करोड़ रुपए होस्ट फीस के रूप में दिए जाएंगे।
- वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के इतिहास में पहली बार यह टूर्नामेंट अफ्रीका में आयोजित होने जा रहा है। केन्या की राजधानी नैरोबी 2029 संस्करण की मेजबानी करेगा। इसके बाद 2031 की चैम्पियनशिप जर्मनी के म्यूनिख शहर में होगी।
- मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनि लेखरा ने दक्षिण कोरिया में चांगवोन 2026 पैरा डब्ल्यूएसपीएस निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल आर 2 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
- चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने आईपीएल 2027 के लिए भारत के पूर्व पेसर जहीर खान को नया हेड कोच नियुक्त किया है। वह स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे।
- विराट कोहली वनडे क्रिकेट के इतिहास में 15,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। इस सूची में शीर्ष पर सचिन तेंदुलकर हैं।

पुरस्कार एवं सम्मान

दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024



- हाल ही में कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता **अनंत नाग** को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले अनंत नाग दूसरे कन्नड़ अभिनेता (अभिनेता राजकुमार के बाद) बन गए हैं।
- उनकों यह सम्मान 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह (22 सितंबर, 2026) जो गुजरात में आयोजित हुआ था, में प्रदान किया गया।

अनंत नाग

- **जन्म वर्ष-** वर्ष 1948
- **जन्म स्थान-** कर्नाटक
- इन्होंने 300 से अधिक फिल्मों (250 से अधिक कन्नड़) में अभिनय किया है।
- **सम्मान-**
  - फिल्मफेयर पुरस्कार
  - कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार
  - कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार
  - कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार
  - पद्म भूषण- 2025 में
- **कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य-** वर्ष 1988 से 1994 तक
- **कर्नाटक विधान सभा के सदस्य-** वर्ष 1994 से 1999 तक

दादा साहब फाल्के पुरस्कार

- **स्थापना-** वर्ष 1969 में
- यह भारतीय फिल्म जगत/सिनेमा का सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है।
- दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में दादासाहेब फाल्के के योगदान के सम्मान में स्थापित किया गया था।
- दादासाहेब फाल्के ने वर्ष 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म, राजा हरिचंद्र का निर्देशन किया था।
- **प्रदाता-** भारत सरकार (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)
- यह सम्मान किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा के विकास और प्रगति में उसके अतुलनीय एवं आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
- **प्रथम प्राप्तकर्ता-** वर्ष 1969 में अभिनेत्री देविका रानी



दादासाहेब फाल्के
(भारतीय सिनेमा के जनक)

भारतीय सिनेमा को अमूल्य योगदान के लिए एक अनमोल सम्मान...

सरला सम्मान

- साहित्यकार डॉ. रामचंद्र बेहरा को उड़िया साहित्य में योगदान के लिए 'सरला सम्मान' मिला।

महादेवी वर्मा सम्मान-

- जयपुर के कवि कन्हैयालाल भ्रमर कोलखनऊ में 'महादेवी वर्मा विश्व भूषण सम्मान-2026' से सम्मानित किया गया है।
- यह साहित्य महोत्सव निहारिका साहित्य मंच, कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आयोजित हुआ।

पद्मजा को स्वयं प्रकाश स्मृति सम्मान-

- जयपुर की लेखिका पद्मजा की डायरी 'मैं कोई और' को वर्ष 2026 के स्वयं प्रकाश स्मृति सम्मान के लिए चुना है।
- इस पुस्तक में लेखिका ने बीमारी, उपचार के दौरान स्मृति और भाषा खोने तथा उन्हें दोबारा हासिल करने के अनुभव दर्ज किए है।

डॉ. विवेक शर्मा-

- जयपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विवेक शर्मा को जीवरानफाउंडेशन, प्रयागराज की ओर से महात्मा गांधी गौरव सम्मान दिया गया।
- उनकों यह पुरस्कार डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों को बेहतर शिक्षा व पढ़ने-लिखने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों को महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा द्वारा बेहतर और सहयोगपूर्ण शिक्षा दिलाने के क्षेत्र में किए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण-

- भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने 22 सितंबर, 2026 को एकता नगर, गुजरात में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किये।
- 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को तीनों जूरी के अध्यक्षों द्वारा की गई थी।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-

- **स्थापना-** वर्ष 1954, यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान हैं।
- **प्रदाता-** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- **पुरस्कार श्रेणी-**
  - फीचर फिल्में
  - नॉन-फीचर फिल्में
  - सिनेमा पर लेखन

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेता-

पुरस्कार	फिल्म (भाषा)	पुरस्कार विजेता
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म	आर्टिकल 370 (हिंदी)	निर्माता: जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज; निर्देशक: आदित्य सुहास जंभाले
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन	अमरन (तमिल)	राजकुमार पेरियासामी
मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	ब्रमायुगम (मलयालम); चंदू चैंपियन (हिंदी)	ममूटी और कार्तिक आर्यन (संयुक्त रूप से)
मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	आर्टिकल 370 (हिंदी)	यामी गौतम
सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	भक्षक (हिंदी)	संजय मिश्रा
सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	महाराजा (तमिल); मिथ्या (कन्नड़)	सच्चाना नामीदास और रोपाश्री वर्काडी (साझा)
निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म	स्वातंत्र्य वीर सावरकर (हिंदी)	रणदीप हुड्डा
संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म	कल्कि 2898 एडी (तेलुगु)	निर्माता:वैजयंती मूवीज; निर्देशक:नाग अश्विन सिंगीरेड्डी
राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म	कैप्टन मिलर (तमिल)	निर्माता: सत्य ज्योति फिल्म्स; निर्देशक: अरुण मथेश्वरन
सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म	35 - चिन्ना कथा कादू (तेलुगु)	निर्माता: एस ओरिजिनल्स और वाल्टेयर प्रोडक्शंस; निर्देशक: नंदा किशोर इमानी
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन	आर्टिकल 370 (हिंदी); अमरन (तमिल)	शाश्वत सचदेव (गीत); जी. वी. प्रकाश कुमार (पार्श्व संगीत)
सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म	भंगार (मराठी और अंग्रेजी)	निर्माता एवं निर्देशक: सुमिरा रॉय
निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म (गैर-फीचर)	आंगेन (संथाली)	निर्देशक: रवि राज मुर्मू
सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री)	राम-नामी (हिंदी)	निर्माता: बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड; निर्देशक: भारतबाला गणपति
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन (गैर-फीचर)	स्टैच्यू ऑफ यूनिटी - एकता का प्रतीक (हिंदी)	आनंद एल. राय
सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक	नानिरुवुदे निमगागी नादिरुवुदे ननगागी (कन्नड़)	लेखक: कंचनूरु प्रदीप कुमार शेट्टी; प्रकाशक: मिरर पुस्तका
सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक	हिंदी	संजीव श्रीवास्तव

- 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए फीचर फिल्म जूरी की अध्यक्षता श्री जयराज ने की थी। इसी संस्करण के लिए गैर-फीचर फिल्म जूरी की अध्यक्षता श्री असीम सिन्हा ने तो सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन जूरी की अध्यक्षताश्री ए. चंद्रशेखर ने की थी।

68वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार-2026

- रमन मैग्सेसे अवॉर्ड फाउंडेशनने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं के रूप में समाज में उत्कृष्ट और परिवर्तनकारी योगदान देने के लिए तीन प्रमुख एशियाई व्यक्तित्वों को इस सम्मान हेतु चुना गया है।



- **वर्ष 2026 के पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता-**
  - टॉमी कोह (सिंगापुर)-अंतर्राष्ट्रीय संवाद और कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित।
  - रुना खान (बांग्लादेश)- वंचित समुदायों के बीच किए गए कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।
  - बो की (म्याँमार)- सैन्य दमन और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ जीवनभर के प्रतिरोध के लिए सम्मानित।
- **रमन मैग्सेसे पुरस्कार-**
  - स्थापना- वर्ष 1958 में
  - उद्देश्य-जाति, लिंग या धर्म के भेदभाव से परे निःस्वार्थ सेवा, साहस, मानवीय भावना और परिवर्तनकारी नेतृत्व को मान्यता देना तथा उसे सम्मानित करना।
  - इसे एशिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है और व्यापक रूप से "एशिया का नोबेल पुरस्कार"कहा जाता है।
  - चयनित विजेताओं को रमन मैग्सेसे अवॉर्ड फाउंडेशन द्वारा एकपदक, प्रमाण-पत्रऔरनकद राशिप्रदान की जाती है।

ललित कला अकादमी पुरस्कार-

- 27 सितम्बर, 2026 को ललित कला अकादमी ने 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए 20 विजेताओं के नामों की घोषणा की है।
- **65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार विजेता-**

क्र.सं.	कलाकार	पुरस्कृत कलाकृति	माध्यम	श्रेणी
1	चंद्र शेखर सैन	माई एंटायर वर्ल्ड - I	टेराकोटा	प्रतिमा
2	गोपाल चंद्र नस्कर	द ट्यून ऑफ़ द श्रीमद भगवद गीता	कैनवस पर ऐक्रेलिक	पेंटिंग
3	किशोर कुमार नरखादीवाला	पर्यावरण	तैल चित्र	पेंटिंग
4	मृणाल डे	होपलेस सेटलमेंट	कैनवस पर ऐक्रेलिक	पेंटिंग
5	निधि चोपड़ा	टैंजिबल ड्रीम्स	सिरेमिक	प्रतिमा
6	निमाई सिंह सरुंगबम	मुद्रा - I	सागौन की लकड़ी	प्रतिमा
7	पंकज कुमार शर्मा	हेलोएड ट्रैवलर - III	पैनल वर्क्स	चित्र
8	पूजा राजपूत	प्रकृति शोषण	सफ़ेद संगमरमर	प्रतिमा
9	प्रवीण कुमार	वेयर द वॉल्स रिमेंबर	मिक्स्ड मीडियम	पेंटिंग
10	प्रीतम मधुकर देउसकर	ऑफ़ टाइम एंड द सिटी	नक्काशी	प्रिंटमेकिंग
11	राजेंद्र प्रसाद	सुजाता विद बुद्ध	वॉटर कलर (वॉश)	पेंटिंग
12	रमेश विट्ठल थोराट	शीर्षकहीन - II	तैल चित्र	पेंटिंग
13	रविराम रामकृष्णन	फिशरवुमन	कॉपर, ऑक्सीकृत, वेल्डेड	प्रतिमा

14	संजय कुमार	व्हेन मेमोरीज कम बैक - 7	मिक्स्ड मीडियम	पेंटिंग
15	संजय कुमार साहनी	यूथ	तैल चित्र	पेंटिंग
16	संजीब कुमार गोगोई	आकार निरंकार- II	ऐक्रेलिक & तैल चित्र	पेंटिंग
17	सांता देब	अट्रेक्शन ऑफ़ सिम्पलिसिटी	सिरेमिक	प्रतिमा
18	सिद्धार्थ शाहजीराव शिंगाडे	ट्रीज	मिक्स्ड मीडियम	पेंटिंग
19	उषारंजन मंडल	व्हील ऑफ़ ए क्राउडेड सिटी	मिक्स्ड मीडियम	कोई अन्य माध्यम
20	विजेंद्र शर्मा	लाइफ 2025	तैल चित्र	पेंटिंग

- **ललित कला अकादमी-**
  - स्थापना- 5 अगस्त, 1954
  - वैधानिक पंजीकरण- 11 मार्च, 1957 (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860)
  - मुख्यालय- नई दिल्ली
  - क्षेत्रीय केंद्र- पाँच (चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर, गढ़ी)
  - उप-केंद्र- चार (शिमला, अहमदाबाद, अगरतला, पटना)
  - उद्देश्य- दृश्य कला (समकालीन, आधुनिक, लोक एवं जनजातीय कला) का संरक्षण व प्रोत्साहन देना।

तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार (टीएनएनएए)-

- हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार (टीएनएनएए) की घोषणा की है।
- ये पुरस्कार चार श्रेणियों भू- जल तथा वायु साहसिक अभियानों तथा आजीवन उपलब्धि के लिए प्रदान किये जायेंगे। पुरस्कार प्रदान किये जाने का उद्देश्य- युवाओं में साहस, सहनशीलता, अनुशासन, जोखिम लेने की क्षमता और सहयोगात्मक टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देना।
- तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के विजेता को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

- **पुरस्कृत-**

क्रम	नाम	संवर्ग
1.	सुश्री बलजीत कौर	भू साहसिक अभियान
2.	श्री स्कालज़ैंग रिगज़िन	भू साहसिक अभियान
3.	श्री रिमो साहा	जल साहसिक अभियान
4.	श्री शिव प्रसाद चमोली	आजीवन उपलब्धि

- **तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार-**

स्थापना	वर्ष 1994
मंत्रालय	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्रेणियाँ	भूमि, जल, वायु, जीवनपर्यंत उपलब्धि
पुरस्कार राशि	₹15 लाख
पुरस्कार	कांस्य प्रतिमा, प्रमाण-पत्र, ब्लेज़र/रेशमी टाई या साड़ी

ग्रीन हाईवेज एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026-

- प्रद्दता- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)
- उद्देश्य- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में सतत हरित प्रथाओं को अपनाने में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इन पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा तीन श्रेणियों में की गई है।

- **श्रेणी- I (सड़क के किनारे पौधा रोपण)-**

पहला पुरस्कार	परियोजना- आंध्र प्रदेश में एनएच 16 पर चिलकलूरिपेट बाईपास का छह लेन में विस्तार, आरओ-विजयवाड़ा के अंतर्गत

- **श्रेणी- II (सड़क के बीच पौधारोपण)-**

पहला पुरस्कार	परियोजना- हैदराबाद-यादगिरी खंड के एनएच 163 किमी का चार लेन में विस्तार, आरओ-हैदराबाद के अंतर्गत

- **श्रेणी- III (भूखंड में पौधारोपण)-**

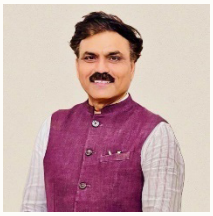
पहला पुरस्कार	परियोजना- एनएच-44 पर जामठा क्लोवर लीफ, ऑक्सीजन बर्ड पार्क, आरओ – नागपुर के अंतर्गत

- **ग्रीन हाईवेज़ एक्सीलेंस अवार्ड्स-**
  - स्थापना वर्ष- 2025 में
  - संस्थापक- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा
  - ये पुरस्कार पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास के साथ-साथ पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखने के प्रति एनएचएआई की प्रतिबद्धता को मज़बूत करते हैं।

डॉ. रेशमा वी.आर. नायर-

- बायो 360 लाइफ साइंसेज पार्क की प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉ. रेशमा वी.आर. नायर को डॉ. हिशाम एंडोमेंट अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है।
- उन्हें हम्बोल्टिया यूनिजुगा पर फाइटोकेमिकल रिसर्च के लिए सम्मान मिलेगा। उन्हें तिरुवनंतपुरम में स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र व नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जन सेवा पुरस्कार 2026-



- प्राप्तकर्ता- श्री किशोर मकवाना (अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग)
- नामांकनकर्ता संस्थाएं- प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन एवं संसद रत्न पुरस्कार समिति
- आयोजन का अवसर- 16वां संसद रत्न पुरस्कार समारोह 2026 (नई दिल्ली)
- पुरस्कार का उद्देश्य- सामाजिक न्याय और अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा में उत्कृष्ट योगदान

राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता-2025-26पुरस्कार वितरण-

- पुरस्कार वितरण संस्करण- 27वां
- आयोजन तिथि- 10 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल-संसद भवन परिसर, नई दिल्ली।
- आयोजक-संसदीय कार्य मंत्रालय।
- अध्यक्षता व पुरस्कार वितरण-श्री किरेन रिजिजू (केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री)।
- प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए संसदीय शील्ड और ट्रॉफी "पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, उखरुल-1, मणिपुर (शिलांग क्षेत्र)" को प्रदान की गयी।
- इसके अतिरिक्तनिम्नलिखित विद्यालयों को उनके संबंधित क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए योग्यता ट्रॉफी प्रदान की गयी-

	विद्यालयों के नाम	क्षेत्र
1.	पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, कोल्लम, केरल	हैदराबाद
2.	पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, ठियोग, शिमला, हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़
3.	पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर-द्वितीय, राजस्थान	जयपुर
4.	पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, मल्हार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	भोपाल
5.	पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, वलसाड, गुजरात	पुणे
6.	पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	पटना
7.	पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड	लखनऊ

- Note- राजस्थान के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर-द्वितीय, राजस्थान को भी पुरस्कृत किया गया है।

चतुर्थ 'इको वॉरियर' पुरस्कार समारोह-

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रीश्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चौथे 'इको वॉरियर' पुरस्कार समारोह और 'इको वॉरियर' सम्मेलनका आयोजन किया गया।
- इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजनभारतीय वन सेवा संघ तथा 'इंडियन मास्टरमाइंड्स'के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ।
- **लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (आजीवन उपलब्धि पुरस्कार)-**
  - पुरस्कार विजेता-श्री बृज किशोर सिंह (कर्नाटक कैडर, 1976 बैच के आईएफएस अधिकारी)।
- **इको वॉरियर पुरस्कार विजेता (केवल राजस्थान के विजेता व्यक्तित्व)-**

स्पेशल जूरी अवॉर्ड-

- सुश्री सविता दहिया (डीसीएफ, बाड़मेर, राजस्थान)
- योगदान- 'ताल छापर' घास के मैदानों के पुनरुद्धारहेतु।

विशेष परियोजना सम्मान-

- स्थान-राजस्थान।
- पुरस्कृत परियोजनाएं- 'प्रोजेक्ट एलिफ़ेंट' एवं 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) संरक्षण प्रोजेक्ट'।
- योगदान-संकटग्रस्त प्रजातियों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण में अतुलनीय योगदान हेतु।

राज कपूर स्पेशल अवॉर्ड-

- एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को 62वें महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स समारोह में प्रतिष्ठित राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- यह अवॉर्ड भारतीय सिनेमा में रानी के योगदान और मुंबई व महाराष्ट्र से उनके लंबे जुड़ाव के लिए दिया गया है।

कलिंग रत्न पुरस्कार-

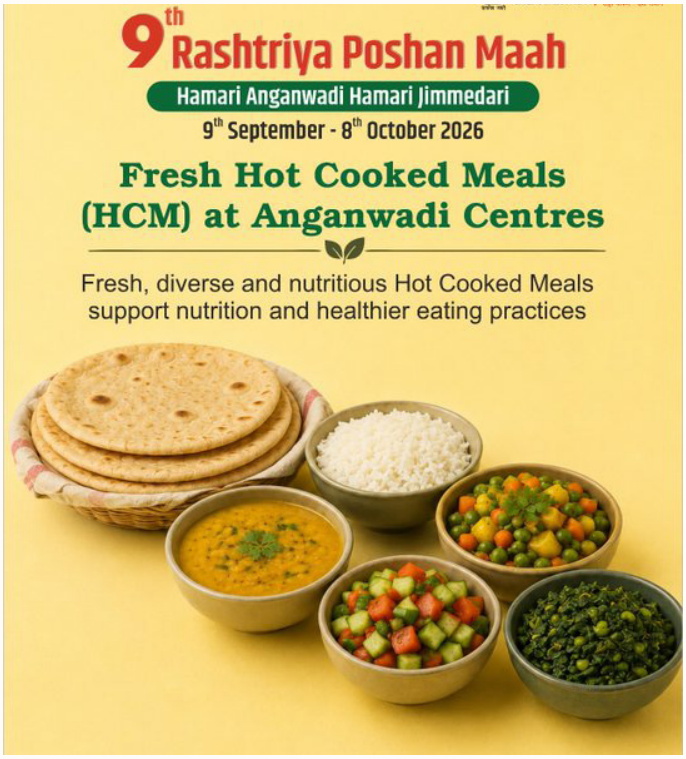
- भारत केपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा को कटक में सरला साहित्य संसद ने 'कलिंग रत्न पुरस्कार' दिया गया।

■■■■■

सम्मेलन/बैठक /मेला/महोत्सव/प्रदर्शनी

राष्ट्रीय

9वां राष्ट्रीय पोषण माह 2026-



- लाँच तिथि- 9 सितंबर,2026
- समापन तिथि- 8 अक्टूबर, 2026
- लाँच स्थल-रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
- आयोजक- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- मुख्य अतिथि-श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री) एवं योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश)
- अभियान का विषय- "हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी"
- पोषण माह 2026 के सहायक विषय-पोषण माह 2026 के 5 परस्पर सहायक विषय है-
  1. आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन।
  2. आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन।
  3. सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही।
  4. पोषण, प्रारंभिक प्रोत्साहन और बाल विकास के लिए शिक्षा।
  5. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष।
- मुख्य तथ्य-
  - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में पोषण को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के केंद्र में लाने और 2047 तक 'सुपोषित भारत' के निर्माण हेतु यह अभियान शुरू किया गया था।
  - प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित होने वाला 'राष्ट्रीय पोषण माह' एक जन आंदोलन बन चुका है, जो महिलाओं, बच्चों और किशोरों के पोषण व स्वास्थ्य व्यवहार को सुदृढ़ करता है।

एयरो इंडिया-



- संस्करण- 16वां
- आयोजन तिथि- 8 से 12 फरवरी, 2027
- आयोजन स्थल-येलाहांका वायु सेना स्टेशन, बेंगलुरु
- आयोजक-रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय
- उद्देश्य-
  - देश की एयरोस्पेस, रक्षा विनिर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचार में बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना।
  - व्यापारिक संबंधों, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक संवाद के अवसर प्रदान करना।
- प्रमुख तथ्य-
  - यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और दुनिया की प्रमुख विमानन व रक्षा प्रदर्शनियों में से एक है।
  - इसमें वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा कंपनियों, नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, नवोन्मेषकों, उद्योग हितधारकों और रक्षा बलों के अधिकारी शामिल होंगे।
  - पांच दिनों के इस आयोजन में भारतीय वायु सेना और अंतर्राष्ट्रीय विमानन टीमों द्वारा हवाई प्रदर्शन (एयर शो) किया जाएगा।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक-



- संस्करण/बैठक/सत्र क्रम- 28वीं बैठक
- आयोजन तिथि-7 सितम्बर, 2026
- आयोजन स्थल- पणजी, गोवा
- आयोजक- अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार (गोवा सरकार की मेज़बानी में)
- अध्यक्ष- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह
- उपाध्यक्ष- गोवा के मुख्यमंत्री
- **उद्देश्य-**
  - सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के आधार पर आपसी सहयोग बढ़ाना।
  - दो या अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों, विवादों और क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा व समाधान करना।
- **प्रमुख तथ्य- क्षेत्रीय परिषद**
  - स्थापना- राज्यों और उनसे संबंधित मामलों के पुनर्गठन की योजना के एक भाग के रूप में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी।
  - उद्देश्य- केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यों-राज्यों के मध्य सहयोग, समन्वय और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना।
  - **वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद् और सदस्य-**
    - उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् - हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र।
    - मध्य क्षेत्रीय परिषद्- छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
    - पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् - बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल।
    - पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्- गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र।
    - दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश।

ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026-



- आयोजन तिथि- 10 से 12 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, नई दिल्ली
- विषय- 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग से ड्राईलैंड खेती में बदलाव लाना'
- **आयोजक-**
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
  - अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईसैट)
- **उद्देश्य-**
  - दक्षिण-दक्षिण सहयोग से ड्राईलैंड (शुष्क भूमि) खेती में बदलाव लाना।
  - जलवायु परिवर्तनशीलता, भूमि क्षरण, जल संकट और बदलते बाजारों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे छोटे किसानों और शुष्क भूमि की कृषि प्रणालियों में सुधार पर विचार-विमर्श करना।
- प्रमुख तथ्य- सम्मेलन का समापन 'शुष्क भूमि पर दिल्ली घोषणापत्र (3डी)' को अपनाने के साथ हुआ।

वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम (डब्ल्यूसीईएफ) 2026-



- आयोजन तिथि- 15 से 18 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- गांधीनगर (गुजरात)
- अध्यक्षता- भूपेंद्र यादव (केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री) और भूपेंद्रभाई पटेल (गुजरात के मुख्यमंत्री)
- विषय- 'सर्कुलर इकोनॉमी: लोगों और समृद्धि के लिए बदलाव'
- उद्देश्य-
  - सर्कुलैरिटी को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बेहतर बनाने के लिए भारत की पहलों को दिखाना।
  - वैश्विक सहयोग और 'ग्लोबल साउथ' के साथ बेहतर जुड़ाव को मुमकिन बनाना।
  - सर्कुलर फाइनेंस और निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाना।
  - पॉलिसी बातचीत व भागीदारी को बढ़ावा देना।
  - नवाचार, डिजिटलीकरण व तकनीक को आगे बढ़ाना।
- यह फोरम दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहा है।
- डब्ल्यूसीईएफ 2027 के आयोजन की जिम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को सौंपी।

सेमीकॉन इंडिया 2026-

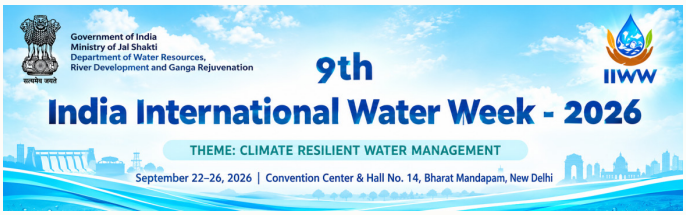


- संस्करण- 5वां संस्करण
- आयोजन तिथि- 17 से 19 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल- यशोभूमि, नई दिल्ली
- विषय- 'सिलिकॉन से सिस्टम तक: परितंत्र का निर्माण'
- उद्घाटनकर्ता- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
- इसमें 6 देशों (जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन) के मंडप, 12 भारतीय राज्यों के मंडप, एक स्टार्टअप पवेलियन और एक कार्यबल विकास क्षेत्र शामिल रहा।
- **प्रमुख रणनीतिक घोषणाएँ एवं उद्योग जगत की प्रतिबद्धताएँ-**
  - भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का बजट- सेमीकंडक्टर 1.0 के तहत ₹8 अरब अमेरिकी डॉलर के बजट को बढ़ाकर सेमीकंडक्टर 2.0 के लिए 13.5 अरब अमेरिकी डॉलरकर दिया गया है।
  - वैश्विक बाजार अनुमान- वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2035 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरतक पहुंचने का अनुमान है।
  - टोक्यो इलेक्ट्रॉन (TEL) द्वारा गुजरात में अगले वर्ष एक सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई।
- **नए उद्घाटन व नवाचार शोकेस**
  - प्रधानमंत्री द्वारा मोहाली स्थित CDIL सेमीकंडक्टर में डिस्क्रीट डिवाइसों के लिए और सूरत स्थित सुची सेमीकॉन में पैकेजिंग के लिए वर्चुअल उद्घाटन किया गया।
  - सुची सेमीकॉन और ईइन्फोचिप्स द्वारा भारत की पहली वाणिज्यिक QFN चिप, भारत में डिजाइन की गई 'सेंससोक-200'चिप का स्मार्ट मीटर में एकीकरण, और 6 ChipIn क्षेत्रीय केंद्रों का शुभारंभ।
- **सेमीकॉन 2.0- यह 'मूलभूत विश्वसनीयता से व्यापक घरेलू क्षमता' की ओर बदलाव है। इसके छह प्रमुख स्तंभ हैं-**
  1. डिजाइन
  2. उपकरण और सामग्री
  3. फैब्स (Fabs)
  4. उन्नत पैकेजिंग
  5. अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास
  6. प्रतिभा विकास

स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर-2026

- संस्करण- 5 वां
- आयोजन तिथि- 12 से 19 सितंबर, 2026 तक
- यह भारत के 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबे विशाल तटीय क्षेत्र की सुरक्षा और सफाई पर केंद्रित।
- उद्देश्य- महासागरों के संरक्षण और तटीय सफाई के लिए नागरिकों, छात्रों, तटीय समुदायों और स्वयंसेवी संगठनों की व्यापक जन-भागीदारी सुनिश्चित करना।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026-



- संस्करण- 9वां
- आयोजन तिथि- 22-26 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- भारत मंडपम, नई दिल्ली
- विषय- ''जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन''
- मंत्रालय- जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
- **उद्देश्य-**
  - उभरती जल चुनौतियों का समाधान करना।
  - जल-सुरक्षित और जलवायु अनुकूल भविष्य को आगे बढ़ाना।
  - ज्ञान एवं संवाद को व्यावहारिक सिफारिशों, साझेदारियों और व्यापक समाधानों में बदलना।
- भागीदार देश- नीदरलैंड और जर्मनी।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) की वार्षिक समीक्षा बैठक-

- बैठक- 1 सितंबर, 2026, अध्यक्षता- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
- इस बैठक में सोलह रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की उपस्थिति थी।
- **प्रमुख तथ्य-**
  - **रक्षा उत्पादन (2025-26) -** भारत का कुल रक्षा उत्पादन-लगभग ₹1.8 लाख करोड़। (डीपीएसयू का योगदान-लगभग ₹1.29 लाख करोड़)
- **सरकार को लाभांश का भुगतान -** कुल लाभांश-₹3,951 करोड़
- **बैठक में विमोचित पुस्तकें**
  1. आत्मनिर्भर डीपीएसयू- आत्मनिर्भरता की ओर डीपीएसयू की यात्रा
  2. दिशा
  3. एचएएल का आधुनिकीकरण रोडमैप
  4. एचएएल का स्वदेशीकरण रोडमैप

वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान माला-

- संस्करण/बैठक/सत्र- द्वितीय
- आयोजन तिथि- 1 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र, दिल्ली
- यह भारत के सैन्य और रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्यक्रम है।
- यह केंद्र भारतीय रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तहत तीनों सेनाओं (थलसेना, नौसेना और वायुसेना) का एक त्रि-सैन्य थिंक टैंक (विचार समूह) है।

भाषिनी संगम- अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता कार्यशाला-

- आयोजन तिथि- 1 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल-काठमांडू, नेपाल
- आयोजक-डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) का 'डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग', भारतीय दूतावास (काठमांडू) और काठमांडू विश्वविद्यालय के सहयोग से
- **उद्देश्य-**
  - भाषा एआई के क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग को सुदृढ़ बनाना।
  - बहुभाषी व ध्वनि-प्रधान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से डिजिटल सेवाओं और अवसरों को लोगों की पसंदीदा भाषाओं तक पहुँचाना।
  - स्थानीय भाषाओं/संस्कृतियों का संरक्षण करना।
- **प्रमुख तथ्य-**
  - कार्यशाला डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर आधारित है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रवर्तन कार्य बल की बैठक-

- बैठक क्रम- 138वीं बैठक, आयोजन तिथि- 31 अगस्त, 2026
- आयोजक-वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का प्रवर्तन कार्य बल
- उद्देश्य- 08 अगस्त, 2026 से 23 अगस्त, 2026 की रिपोर्टिंग अवधि के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रवर्तन कार्रवाइयों, निरीक्षणों और अनुपालन स्थिति की समीक्षा करना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक-

- संस्करण/बैठक- दूसरी बैठक
- आयोजन तिथि- 1 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- अध्यक्षता- जगत प्रकाश नड्डा (केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री)
- उद्देश्य- मंत्रालय तथा इसके विभिन्न संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करना और राजभाषा के प्रयोग को और बढ़ाना।

जल पर आयोजित राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन-

- यह पानी पर आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन था।
- आयोजन तिथि-1-2 सितंबर,2026
- आयोजक-केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय
- अध्यक्षता-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (समापन सत्र की अध्यक्षता)
- **उद्देश्य-**
  - टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना।
  - सहकारी संघवाद को गहरा करना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर सहयोग के जरिए भारत की जल सुरक्षाके प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना।

भारत के डेटा सेंटर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुगमता विषय पर सीईओ गोलमेज सम्मेलन-

- आयोजन तिथि- 2 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल-वाणिज्य भवन, नई दिल्ली
- अध्यक्षता- पीयूष गोयल (केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री)
- **उद्देश्य-**
  - भारत के डेटा सेंटर सेक्टर के त्वरित और सतत विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण को और सुदृढ़ करना।
  - डेटा सेंटर उद्योग के हितधारकों के साथ इस सेक्टर को बढ़ावा देने और व्यापार सुगमता बढ़ाने पर चर्चा करना।
- **प्रमुख तथ्य-**
  - भारत में डेटा सेंटर उद्योग में लगभग 200 बिलियन डॉलर का निवेश होने की संभावना है।
  - 2026 की पहली छमाही में डेटा सेंटर के उपयोग में हाइपरस्केलर्स की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक रही।
  - राष्ट्रीय भवन संहिता-2026 में डेटा केंद्रों को अब समूह-ई के अंतर्गत विशेष रूप से मान्यता दी गई है।
  - यह सेक्टर भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा।

राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) की राष्ट्रीय बैठक-

- बैठक क्रम- 16वीं
- आयोजन तिथि- 6-7 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल-चंडीगढ़
- आयोजक-राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए)
- **अध्यक्षता-**
  - श्री गुलाब चंद कटारिया (पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ यूटी के प्रशासक)
  - श्री भूपेंद्र यादव (केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री)
  - श्री राव नरबीर सिंह (पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री, हरियाणा सरकार)

- **उद्देश्य-**
  - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अनुभव, नवाचार और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को साझा करना।
  - संस्थागत तंत्रों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कामकाज, जन जैव विविधता रजिस्टरों की गुणवत्ता/उपयोगिता और राज्य व स्थानीय स्तर पर जैव विविधता शासन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए व्यावहारिक उपायों पर विचार-विमर्श करना।

डीडीयू-जीकेवाई-1.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के समापन पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला-

- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 1.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के समापन पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- आयोजन तिथि- 7-8 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल-राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी), पूसा, नई दिल्ली
- आयोजक-ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- उद्देश्य-डीडीयू-जीकेवाई 1.0 की परियोजनाओं की समीक्षा करना और दस्तावेज़ीकरण पूरा होने के बाद औपचारिक समापन की घोषणा के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना।

5वां ई-फास्ट इंडिया शिखर सम्मेलन-

- संस्करण- 5वां
- आयोजन तिथि- 07 सितंबर,2026
- आयोजक- नीति आयोग (ई-फास्ट इंडिया प्लेटफॉर्म)
- अध्यक्षता/शुभारंभकर्ता- राजीव गौबा (सदस्य, नीति आयोग)
- उद्देश्य- बड़े पैमाने पर शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के लिए व्यावसायिक आधार को मजबूत करना, माल ढुलाई इकोसिस्टम के हितधारकों के बीच संपर्क स्थापित करना, मांग को एकजुट करना, और व्यापार, वित्तपोषण व चार्जिंग साझेदारी को बढ़ावा देना।
- मुख्य घोषणाएँ- पीएसीटी (PACT) का शुभारंभ और ज़ेडईटी (ZET) मार्केटप्लेस की शुरुआतकी गयी।

एसटीपीआई इलेक्ट्रोप्रेन्योर समिट 2026

- आयोजन तिथि- 8 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- आईआईआईटी-दिल्ली (IIIT-Delhi)
- आयोजक- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) [इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत]
- **उद्देश्य-**
  - भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) के दायरे को बढ़ाना।
  - ईएसडीएम क्षेत्र में नए तकनीकी समाधानों और स्टार्टअप्स की पहचान करना व उन्हें समर्थन देना।
  - भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स व डीप-टेक इनोवेशन के भविष्य को आकार देना।

इन्नोप्रोम इंडिया 2026-

- **संस्करण-**प्रथम, **आयोजन तिथि-** 9 से 11 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल-भारत मंडपम, नई दिल्ली
- आयोजक-वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा रूसी संघ के उद्योग और व्यापार मंत्रालय के सहयोग से
- **उद्देश्य-**
  - भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना।
  - विनिर्माण, औद्योगिक प्रौद्योगिकी, स्थानीयकरण, निवेश और व्यावसायिक साझेदारी में सहयोग को मजबूत करना।
  - भारत के औद्योगिक गलियारों को दीर्घकालिक विनिर्माण निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना।
- **प्रमुख तथ्य-**
  - इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड ने भाग लिया।
  - भारत और रूस ने 2030 तक लगभग 9.45 लाख करोड़ रुपये (100 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है।

शिल्पकार समागम-

- आयोजन तिथि- 2-3 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल-नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (एनजीएमए), नई दिल्ली
- आयोजक-संस्कृति मंत्रालय
- उद्देश्य-
  - भारत की समृद्ध और विविध शिल्प परंपराओं को संग्रहालय के आर्किटेक्चर, इंटीरियर, गैलरी और सार्वजनिक जगहों में सार्थक ढंग से शामिल करने पर चर्चा करना।
  - कारीगरों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक लैंडमार्क बनाने में सीधे योगदान का अवसर प्रदान करना।

वेंडर विकास कार्यक्रम

- आयोजन तिथि- 7-8 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल-नई दिल्ली
- आयोजक-संस्कृति मंत्रालय
- उद्देश्य-
  - 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' (वाईवाईबीएम) के विकास के लिए भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, विनिर्माताओं, तकनीक प्रदाताओं और विशेषज्ञ एजेंसियों को एक साथ लाना।
  - संग्रहालय के दायरे, तकनीकी जरूरतों और गुणवत्ता मानकों की जानकारी देना तथा वैश्विक भागीदारी बनाना।

राष्ट्रीय फार्मा कोविजिलेंस सप्ताह-

- संस्करण- छठा, आयोजन तिथि- 17 से 23 सितंबर, 2026 (शुभारंभ: 17 सितंबर, 2026)
- आयोजन स्थल- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
- आयोजक- भारतीय फार्माकोपिया आयोग
- विषय- 'फार्माकोविजिलेंस के माध्यम से दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना–सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक कदम'।
- उद्देश्य- स्वास्थ्य पेशेवरों, शोधकर्ताओं और आम लोगों को प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाकी रिपोर्टिंग के प्रति जागरूक करना तथा दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देकर सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में कदम बढ़ाना।
- **प्रमुख तथ्य-** भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC), फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया (PvPI) के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCC) के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) सम्मेलन-

- आयोजन तिथि- 11-12 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल-मुंबई
- आयोजक-केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से)
- अध्यक्षता-डॉ. मनसुख मांडविया (केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री)
- **उद्देश्य-**
  - राष्ट्रीय भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक ढांचे के विकास का जायजा लेना।
  - श्रमिक कल्याण बोर्डों के कामकाज को मजबूत करना।
  - श्रमिकों के लिए वैधानिक जिम्मेदारियों, श्रमिक पंजीकरण, कल्याणकारी सेवाओं की उपलब्धता, कल्याण निधि की निगरानी व उपयोग और प्रौद्योगिकी-आधारित सेवा वितरण पर विचार-विमर्श करना।

उभरता विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कॉन्क्लेव-2026-

- संस्करण- दूसरा
- आयोजन तिथि- 27 से 29 अक्टूबर,2026
- आयोजन स्थल- भारत मंडपम, नई दिल्ली
- विषय-"सृजनात्मक मन, उत्प्रेरित होता विज्ञान, सशक्त बनती प्रौद्योगिकियां"
- आयोजक- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
- **उद्देश्य-**
  - शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, उद्योग और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक अधिक एकीकृत तंत्र बनाना।
  - संस्थागत गतिरोधों को तोड़कर भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव में बदलना।
  - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम के बीच समन्वय को मजबूत करना और 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देना।
  - वैज्ञानिक नवाचार में रचनात्मकता और कल्पना के महत्व को बढ़ावा देना तथा विचारों को सार्थक परिणामों में बदलना।

"माइक्रोबायोम अनुसंधान के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याणको समझना" कार्यशाला-

- आयोजन तिथि- 9 से 11 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- जामनगर
- आयोजक- आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), आयुष मंत्रालय
- उद्देश्य- प्रतिभागियों को माइक्रोबायोम अनुसंधान में हो रहे नए विकास से परिचित कराना और आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य से स्वास्थ्य, वेलनेस और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इसकी संभावित प्रासंगिकता का पता लगाना।

'डिजाइनर एटेलियर' प्रदर्शनी-सह-बिक्री-

- आयोजन तिथि- 12 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक- सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन
- उद्देश्य- भारत की समृद्ध वस्त्र विरासत, पारंपरिक शिल्प कौशल और समकालीन डिजाइन को एक साथ लाने वाली डिजाइनर कृतियों को प्रदर्शित करना।

'संयुक्त परिचालन समीक्षा एवं मूल्यांकन' (कोर) कार्यक्रम-

- आयोजन तिथि- 14 से 18 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल- मानेकशा केंद्र, नई दिल्ली
- आयोजक- एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय (आईडीएस)
- **उद्देश्य-**
  - वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रख्यात वक्ताओं के साथ संवाद के माध्यम से मौजूदा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों से अवगत कराना।
  - प्रतिभागियों में उभरती सुरक्षा चुनौतियों की गहन समझ विकसित करना।
  - भविष्य में नेतृत्व की भूमिकाओं में संतुलित व सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना।

इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड्स समारोह-

- संस्करण- 52वें
- आयोजन तिथि- 13 सितंबर, 2026

- आयोजन स्थल- मुंबई , आयोजक-भारत डायमंड बोर्ड (BDB)
- अध्यक्षता/मुख्य अतिथि- श्री अमित शाह (केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री)
- उद्देश्य-भारत के अर्थतंत्र, वैभव और चमक को निरंतर बढ़ाने वाले जेम्स एंड ज्वैलरी क्षेत्र के योगदान को सम्मानित करना तथा भारत के कौशल, आत्मविश्वास और वैश्विक महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करना।
- **इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड्स-**
  - इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी।
  - इन पुरस्कारों से निर्यातक, निर्माता, बैंकर और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाता है।

हिंदी दिवस 2026 एवं छठा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन-

- संस्करण-छठा
- आयोजन तिथि- 14-15 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल-नवी मुंबई, महाराष्ट्र
- आयोजक-गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग
- **उद्देश्य-**
  - संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी के प्रसार, विकास और समृद्धि के दायित्व का निर्वहन करना।
  - हिंदी के साथ-साथ सभी भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय, संवाद और साझेदारी को और सुदृढ़ करना।
  - हिंदी के राजभाषा, जनभाषा और संपर्कभाषा के रूप में विकास, भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय, तकनीक, अनुवाद और साहित्य जैसे विषयों पर विचार-मंथन करना।
- वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 के 'राजभाषा कीर्ति' का प्रथम पुरस्कारप्रदान किया गया है।
- अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की शुरुआत 2021 में वाराणसी से हुई थी।

राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन-

- संस्करण- 69वां, आयोजन तिथि- 12 से 19 सितंबर 2026 तक
- आयोजन स्थल-केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका
- आयोजक-राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए)
- **उद्देश्य-**
  - राष्ट्रमंडल की विधायिकाओं से संबंधित समकालीन मुद्दों पर चर्चा करना।
  - राष्ट्रमंडल के भीतर संसदीय लोकतंत्र, विधायी सहयोग और अंतर-संसदीय सहभागिता को मजबूत करना।
  - भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ और लंबे समय से चले आ रहे संसदीय संबंधों को और मजबूत करना।
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व-राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

हानले डार्क स्काई रिजर्व स्टार पार्टी-

- संस्करण- 4वां, आयोजन तिथि- 7 से 12 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- भारतीय खगोलीय वेधशाला, हानले (लद्दाख)
- आयोजक- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए), लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण विभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर) द्वारा संयुक्त रूप से
- **उद्देश्य-**
  - वेधशाला में निरंतर अनुसंधान के लिए हानले के निर्मल अंधकारमय आकाश और प्रकाश संबंधी प्रदूषण को कम करने के महत्व को रेखांकित/संरक्षित करना।
  - स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए खगोल-पर्यटन (खगोल विज्ञान आधारित नवीन सामाजिक-आर्थिक विकास) को बढ़ावा देना।
  - शौकिया खगोलविदों, खगोलीय छायाकारों और स्थानीय दूतों को व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं अवलोकन का अवसर प्रदान करना।

पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान, आनुवंशिक संसाधनों और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर बिम्सटेक सम्मेलन-

- सम्मेलन- तीसरा , आयोजन तिथि- 16 से 17 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- गोवा
- आयोजक-भारत सरकार का आयुष मंत्रालय
- अध्यक्षता-श्रीमती मोनालिसा दास (संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय)
- **उद्देश्य-**
  - एक ऐसा सहयोगी ढांचा विकसित करना जो पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के साथ वैध अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दे।
  - पूर्व सूचित सहमति, पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और न्यायसंगत लाभ-साझेदारी के माध्यम से समुदायों के हितों की रक्षा करना।
- **बिम्सटेक सदस्य देश-** बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) का कमांडर्स सम्मेलन-

- संस्करण- 43वां संस्करण, आयोजन तिथि- 17 से 19 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली
- आयोजक- भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी)
- **उद्देश्य-**
  - भारतीय तटरक्षक बल को मजबूत करना।
  - रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करना।
  - देश के समुद्री हितों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में उसकी भूमिका को सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दोहराना।
- यह वार्षिक बैठक भारतीय तटरक्षक बल का सबसे बड़ा पेशेवर मंच है, जिसमें देशभर के वरिष्ठ कमांडर एकत्र होते हैं।

क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन- दक्षिण क्षेत्र-

- आयोजन तिथि- 18 सितंबर
- आयोजन स्थल- हैदराबाद (तेलंगाना)
- आयोजक- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार
- उद्देश्य- केंद्र-राज्य के बीच तालमेल को मजबूत करते हुए कृषि में आत्मनिर्भरता, उच्च-मूल्य वाली बागवानी, डिजिटल और जलवायु-अनुकूल कृषि, और भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन तथा विपणन के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे के वास्ते लक्षित रणनीतियाँ विकसित करने का प्रयास करना।

राज्य वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवो का सम्मेलन-

- आयोजन तिथि- 18 और 19 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल-नई दिल्ली
- आयोजक-वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग), भारत सरकार
- विषय- "विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा का वित्तपोषण"
- यहसम्मेलन मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत पूरकताओं पर केंद्रित था।
- **इस सम्मेलन में तीन विषयगत सत्र आयोजित हुए-**
  1. वृहद आर्थिक अवलोकन
  2. कृषि रूपांतरण के लिए वित्तपोषण
  3. ऊर्जा परिवर्तन का वित्तपोषण

राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह-2026

- संस्करण- छठा, अवधि- 17 से 23 सितंबर 2026
- शुभारंभ स्थल-भारतीय फार्माकोपिया आयोग, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
- नोडल/राष्ट्रीय समन्वय केंद्र- भारतीय फार्माकोपिया आयोग
- विषय-"फार्माकोविजिलेंस के माध्यम से दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना- सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक कदम"
- **उद्देश्य एवं अभियान का महत्व-**
  - स्वास्थ्य पेशेवरों, शोधकर्ताओं और सामान्य जनता को प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया की रिपोर्टिंग के महत्व के प्रति जागरूक करना।
  - फार्माकोविजिलेंस और रोगी सुरक्षा में हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
  - फार्माकोविजिलेंस आंकड़ों का प्रभावी उपयोग करके दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत इस्तेमाल को बढ़ावा देना।

सेवा संकल्प, खादी महोत्सव-2026-

- अवधि- 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, 2026
- आयोजन स्थल-राजघाट, नई दिल्ली
- आयोजक संस्थान-सूक्ष्म खादी और ग्रामोद्योग आयोग

कथकली महोत्सव-

- संस्करण- 17वां, आयोजन तिथि- 18 से 20 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- चेन्नई, तमिलनाडु
- विषय-"कथा रस संगम- कहानियों के सार का संगम"
- आयोजक- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में कलाक्षेत्र फाउंडेशन द्वारा
- **कथकली-**
  - शैली- नृत्य
  - राज्य- केरल
  - प्रकृति- नृत्य-नाट्य
  - मुख्य भाषा/साहित्यिक आधार- मलयालम तथा संस्कृत परंपरा
  - प्रमुख कथानक- रामायण, महाभारत, पुराण आदि
  - विशेष पहचान- भव्य वेशभूषा, रंगीन मेकअप और चेहरे का अभिनय
  - प्रमुख प्रदर्शन तत्व- नृत्य, अभिनय, मुद्राएँ, संगीत और ताल

संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन (कोर) कार्यक्रम 2026-

- आयोजन तिथि- 14 से 18 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली
- आयोजक- एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय (एचक्यू आईडीएस) द्वारा आयोजित और सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज (सीईएनजेडेडब्ल्यूएस) द्वारा संचालित
- **उद्देश्य-**
  - वरिष्ठ सैन्य और असैन्य अधिकारियों को संयुक्तता, एकीकरण, चल रहे संघर्षों, युद्ध लड़ने के आधुनिक तरीकों, राष्ट्रीय सुरक्षा के गैर-गतिक पहलुओं, रक्षा उत्पादन एवं क्षमता विकास पर विचार साझा करने हेतु मंच प्रदान करना।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी मौजूदा एवं उभरती चुनौतियों पर चर्चा करना।

अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026

- संस्करण- 2वां, आयोजन तिथि- 22-24 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- भारत मंडपम,नई दिल्ली
- विषय- पेयजल तक पहुंच, स्वच्छता अवसंरचना, स्वच्छता व्यवहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य
- मंत्रालय- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राष्ट्रीय औषध निगरानी सप्ताह कार्यक्रम-

- संस्करण- छठा संस्करण (राष्ट्रीय औषध निगरानी सप्ताह का) / 7वां संस्करण (राष्ट्रीय फ़ार्मुलेरी 2026 का)
- आयोजन तिथि- 17 से 23 सितंबर 2026

- आयोजन स्थल- डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली
- विषय- "फार्माकोविजिलेंस द्वारा दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा: सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक कदम"
- आयोजक- भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी)
- **उद्देश्य-**
  - दवाओं के तर्कसंगत और सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना।
  - चिकित्सा उपकरण संबंधी प्रतिकूल घटनाओं की सुरक्षा निगरानी व सूचना देना।
  - रोगी देखभाल और दवा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस में भारत का योगदान 2009-2014 के दौरान 123वें स्थान से बढ़कर वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर पहुंच गया है।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन-

- संस्करण- तीसरा
- आयोजन तिथि- 22 सितंबर,2026 (दो दिवसीय)
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
- विषय- "सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व"
- उद्घाटन/अध्यक्षता- श्री अमित शाह (केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री)
- उद्देश्य– देश की आने वाली पीढ़ियों को नशे के खतरे से बचाने, विज़न डॉक्यूमेंट (2026-29) के लक्ष्यों की प्रगति पर चर्चा करने, तथा देशभर में मादक पदार्थों की तस्करी व नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सप्लाई, डिमांड और हार्म रिडक्शन से संबंधित प्रभावी रणनीतियों की पहचान व क्रियान्वयन करना।

रबी अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-

- आयोजन तिथि-28–29 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल- भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम सभागार, एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली
- आयोजक- भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्घाटन/अध्यक्षता- श्री शिवराज सिंह चौहान (केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री)
- उद्देश्य- केन्द्र-राज्य तालमेल को मजबूत करना तथा कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक समन्वित एवं परिणाम उन्मुख रणनीति बनाना।

नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2026/02-

- संस्करण- दूसरा (साल में दो बार होने वाले आयोजन)
- आयोजन तिथि-29 सितंबर से 1 अक्टूबर,2026
- आयोजन स्थल- नौसेना भवन, नई दिल्ली
- आयोजक- भारतीय नौसेना
- उद्देश्य- सैन्य-रणनीतिक स्तर पर परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा करना, पश्चिमी एशिया के संघर्षों के बीच भारत के समुद्री व ऊर्जा हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करना, तथा 'जय' (संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार) के स्तंभों के अनुरूप तैयारियों का आकलन कर 'आत्मनिर्भरता' व 'विकसित भारत-2047' के दृष्टिकोण को साकार करना।

प्रहार-CT (आतंकवाद-रोधी) नीति और रणनीति पर सम्मेलन-

- आयोजन तिथि-28 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- उद्घाटन- अमित शाह (केन्द्रीय गृह मंत्री)
- उद्देश्य- आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति को मजबूत करना।

इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) 2027-

- संस्करण- पांचवां
- आयोजन तिथि-28-31 जनवरी 2027
- आयोजन स्थल- कोलकाता
- विषय- "नवाचार को बढ़ावा। ऊर्जा सुरक्षा। भविष्य को आकार देना"
- उद्देश्य- वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्थायित्व को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना।
- यह साल का पहला बड़ा वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन होगा।
- यह सम्मेलन दुनिया भर के नीति-निर्माताओं, ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गजों, तकनीकी अन्वेषकों, निवेशकों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों को एक साथ लाएगा।
- यह आयोजन भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग के बीच ऊर्जा के भविष्य को आकार देने वाली तकनीक, साझेदारी और रणनीतिक फैसलों का मुख्य केंद्र होगा।

अंतर्राष्ट्रीय

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट-2026-

GLOBAL FINTECH FEST 2026

- संस्करण- 7वें
- आयोजनतिथि- 8 से 11 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई
- उद्घाटनकर्ता- नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)
- विषय- "प्रभाव की क्षमता: एजेंटिक AI।टोकनीकरण।क्वांटम- समावेशी वित्त के लिये विश्वसनीय, परस्पर संबद्ध और वैश्विक प्रणालियाँ"।
- आयोजक-पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल
- यह वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल वित्त क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन है।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरणने 'आधार फेस ऑथेंटिकेशन' और 'आधार फेस ऑथेंटिकेशन सैंडबॉक्स' लॉन्च किया है।

फिनटेक (Fintech)

- **परिभाषा-** फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) से तात्पर्य वित्तीय प्रणालियों और सेवाओं के वितरण को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से है। यह प्रौद्योगिकी-आधारित वित्तीय नवाचार नए व्यावसायिक मॉडल, अनुप्रयोग, प्रक्रियाएं या उत्पाद तैयार करता है।
- **फिनटेक के लिए सहायक प्रौद्योगिकियाँ-**
  - एपीआई- नियमों और विशिष्टताओं का समूह, जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपस में संवाद करते हैं और नए अनुप्रयोग बनाने की अनुमति देते हैं।
  - क्लाउड कंप्यूटिंग- ऑनलाइन नेटवर्क ('क्लाउड') का उपयोग करके कंप्यूटिंग क्षमता, लचीलापन और लागत बचत बढ़ाना।
  - बायोमेट्रिक्स- मानवीय विशेषताओं के आधार पर पहचान और वर्गीकरण का अध्ययन।
  - डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी- परिसंपत्ति लेन-देन को एक साथ कई स्थानों पर दर्ज करने की डिजिटल प्रणाली।
  - बिग डेटा- डिजिटल प्रणालियों द्वारा निर्मित संरचित व असंरचित डेटा का विशाल भंडार।
  - आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसव मशीन लर्निंग- मानवीय क्षमताओं वाले कार्य करने वाले आईटी सिस्टम, जिनमें मशीनें बिना मानवीय हस्तक्षेप के डेटा से सीखती हैं।
- **फिनटेक का महत्व और प्रभाव-**
  - प्रतिस्पर्धा व दक्षता- यह उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर व्यापक विकल्प प्रदान करता है तथा वित्तीय संस्थानों की कार्यकुशलता में सुधार लाता है।
  - वित्तीय समावेशन- भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2017 के 43.4 से बढ़कर मार्च 2026 में 70.0 हो गया है।
  - क्रेडिट स्रोतों में विविधता- पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से इतर विकल्प मिलने से बैंकों पर निर्भरता और प्रणालीगत जोखिम कम होते हैं।
- **भारत की फिनटेक सफलता के मुख्य स्तंभ-**
  - जेएएम ट्रिनिटी
  - एकीकृत भुगतान इंटरफेस
  - डिजिटल पहचान, दस्तावेज एवं कल्याण वितरण
  - ओपन डिजिटल कॉमर्स

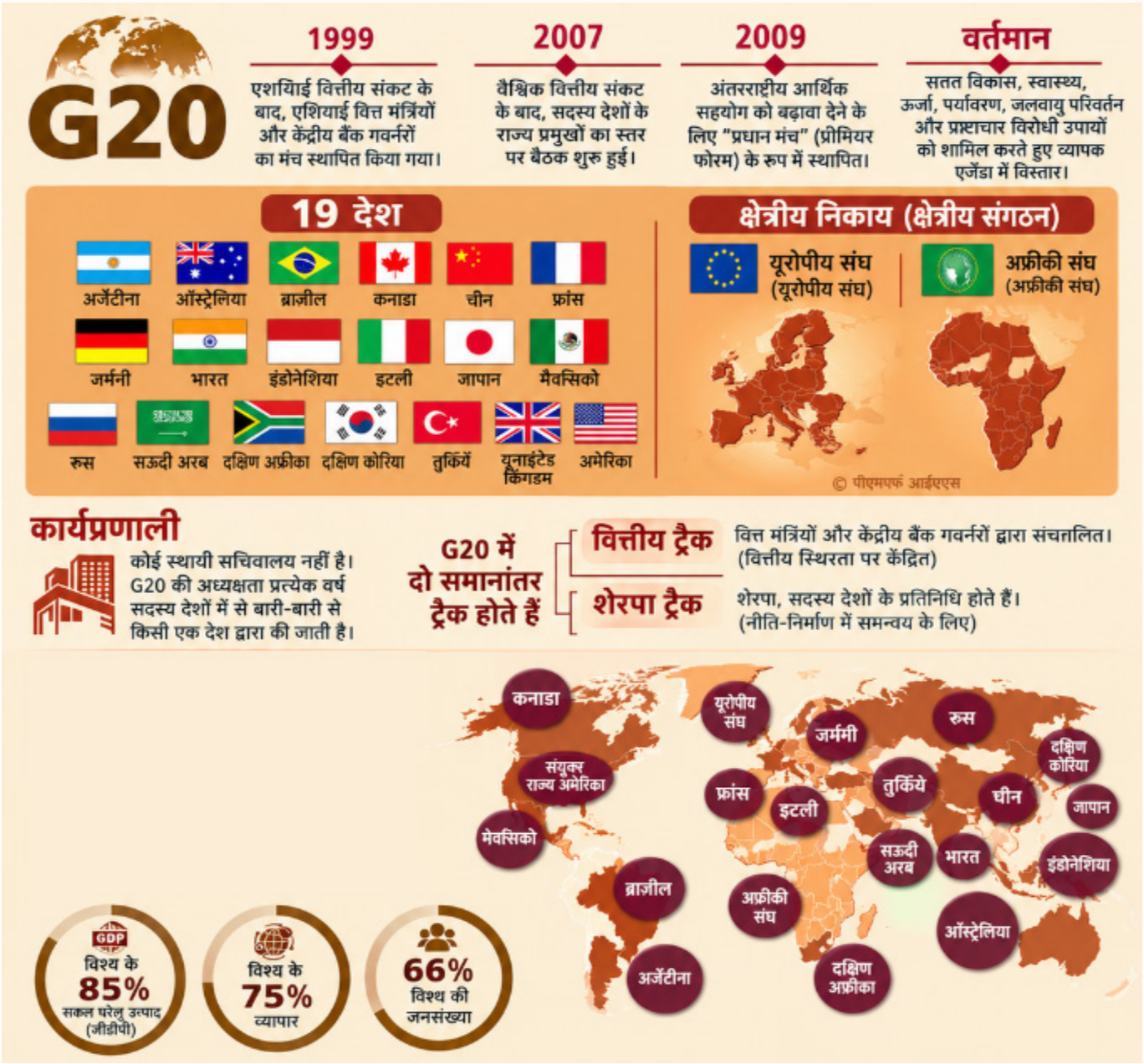
भारत-जर्मन पर्यावरण मंच-

- संस्करण- चौथा
- आयोजन स्थल-नई दिल्ली
- आयोजन तिथि- 31 अगस्त, 2026
- विषय-"अधिक सुदृढ़ता के लिए एकजुट"
- आयोजक-केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जर्मनी का पर्यावरण, जलवायु संरक्षण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय,
- सहयोग- जर्मन व्यापार की एशिया-प्रशांत समिति और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ।
- अध्यक्षता-
  - भूपेंद्र यादव (केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री)
  - कार्स्टेन श्नाइडर (पर्यावरण, जलवायु संरक्षण, प्रकृति संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा मंत्री, जर्मनी)
- उद्देश्य-जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण, प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए एकीकृत व सहयोगात्मक समाधान खोजना तथा जलवायु-लचीले, संसाधन-कुशल और सतत विकास के मार्ग प्रशस्त करना।

जी-20 नवाचार मंत्री बैठक-

- आयोजन तिथि- 1-2 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल-चैपल हिल, उत्तरी कैरोलिना, अमेरिका
- आयोजक-अमेरिकी वाणिज्य विभाग और व्हाइट हाउस के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय (ओएसटीपी)
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व- श्री जितिन प्रसाद (इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री)
- उद्देश्य-उभरती प्रौद्योगिकियों में समृद्धि को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाना और सभी लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करना।
- प्रमुख तथ्य- जी-20 मंत्रियों ने 'नवाचार मंत्रिस्तरीय वक्तव्य' जारी किया और छह प्रमुख स्तंभों पर सहमति व्यक्त की। यह स्तंभ निम्न है-
  1. नवाचार-समर्थक नीतिगत ढांचा।
  2. अवसर और समृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी।
  3. कुशल तकनीकी कार्यबल विकास।
  4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए बौद्धिक संपदा नीतियां।
  5. मानकों के लिए एआई और एआई के लिए मानक।
  6. औद्योगिक नवाचार एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश।

- **जी-20-**



ब्रिक्स देशों के बौद्धिक संपदा कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक-

- बैठक- 18वीं बैठक
- आयोजन तिथि- 1 से 3 सितंबर 2026 (दूसरा दिन: 2 सितंबर 2026)
- आयोजन स्थल-नई दिल्ली
- आयोजक- पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न के महानियंत्रक का कार्यालय
- अध्यक्षता-भारत की अध्यक्षता में
- उद्देश्य-वैश्विक नवाचार, रचनात्मकता और आर्थिक विकास के एक प्रमुख प्रेरक के रूप में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाना तथा सीमा-पार नवाचार और वैश्विक आईपी मानकों को आकार देने के संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना।

व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर भारत-अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक-

- आयोजन तिथि- 1 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल-वर्चुअल माध्यम से आयोजित
- आयोजक-भारत और अफगानिस्तान
- उद्देश्य-
  - द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग की समीक्षा करना।
  - व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाना।
  - दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करना।

बाघ बहुल क्षेत्र- आजीविका और आय सृजन के स्तंभ के रूप में संरक्षण, जैव अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक पर्यटन

- आयोजन तिथि- 2-3 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक-
  - अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए)
  - एशियाई विकास बैंक (एडीबी)
  - राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
- अध्यक्षता- भूपेंद्र यादव (केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री)
- उद्देश्य- बाघ परिदृश्यों को प्राकृतिक पूंजी के रूप में मान्यता देना।

नैनोमेडिसिन पर विश्व कांग्रेस 2026-

- आयोजन तिथि- 27 से 29 सितम्बर, 2026
- आयोजन स्थल- विज्ञान भवन, नई दिल्ली
- उद्घाटन- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह
- आयोजक- इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंसेज (आईएनएमएस), चिकित्सा विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय
- अध्यक्षता- प्रो. रोजर डी. कॉर्नबर्ग (अध्यक्ष)
- उद्देश्य- नैनोमेडिसिन के क्षेत्र में उभरती प्रगति और इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा करना, ज्ञान का आदान-प्रदान करना, सहयोग विकसित करना और भविष्य की स्वास्थ्य सेवा हेतु नैनोमेडिसिन के अवसरों को तलाशना।

भारत-मोरक्को संयुक्त रक्षा समिति की बैठक

- संस्करण/बैठक-पहली बैठक
- आयोजन तिथि- 8 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल-नई दिल्ली
- आयोजक-भारत और मोरक्को (रक्षा मंत्रालय)
- अध्यक्षता-रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और मोरक्को की रॉयल आर्म्ड फोर्सेज के द्वितीय ब्यूरो के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अब्देल्लाह अथमानी
- उद्देश्य-
  - प्रशिक्षण एवं सैन्य शिक्षा, शांति स्थापना अभियानों, सैन्य अभ्यासों, चिकित्सा सहयोग, साइबर सुरक्षा और रक्षा उद्योग जैसे क्षेत्रों में आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करना।
  - दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत एवं व्यापक बनाना।
- यह बैठक 2027 में भारत और मोरक्को के बीच द्विपक्षीय सहयोग की 70वीं वर्षगांठ से ठीक पहले आयोजित की गई है।

वन क्षेत्र में सहयोग पर भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक

- संस्करण/बैठक- 7वीं बैठक
- आयोजन तिथि- 8 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- बेंगलुरु
- **अध्यक्षता-**
  - भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व- रमेश कुमार पांडे
  - जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व- शिमिजु कोटारो
- **उद्देश्य-**
  - वनों के बाहर वृक्ष (टीओएफ), वन आनुवंशिकी तथा वन भंडार के क्षेत्रों में अनुभवों का आदान-प्रदान करना।
  - 2027-2031 के रोडमैप का समर्थन करना, और वन, जैव विविधता संरक्षण, अनुसंधान तथा क्षमता विकास के क्षेत्रों में सहयोग व संबंधों को गहरा करना।
- **सहयोग के प्रमुख क्षेत्र-**
  1. वनों के बाहर वृक्ष (टीओएफ) कार्यक्रम
  2. वन आनुवंशिकी
  3. वन भंडार

79वें डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय समिति सत्र में मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक-

- स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन- विशेषज्ञ देखभाल में समानता (डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान आयोजित मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक)
- सत्र- 79वां सत्र
- आयोजन तिथि- 8 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- तिमोर-लेस्ते
- आयोजक- विश्व स्वास्थ्य संगठन
- **उद्देश्य-**
  - स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाना।
  - विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।
  - सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) को हासिल करना।

आसियान-भारत कृषि कार्य समूह की बैठक-

- संस्करण/बैठक- 10वीं
- आयोजन तिथि- 8 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- अध्यक्षता/सह-अध्यक्षता- भारत और फिलीपींस द्वारा
- उद्देश्य- कृषि और वानिकी में आसियान-भारत सहयोग को मजबूत करने पर विचार-विमर्श करना।
- इस बैठक में 11 आसियान सदस्य देशों के 45 प्रतिनिधि शामिल हुए।

कृषि और वानिकी पर आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक-

- संस्करण/बैठक- 9वीं , आयोजन तिथि- 9 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- **अध्यक्षता/सह-अध्यक्षता-**
  - फ्रांसिस्को पी. टियू लॉरेल (फिलीपींस के कृषि विभाग के सचिव)
  - शिवराज सिंह चौहान (भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री)
- **उद्देश्य-**
  - खाद्य सुरक्षा, सतत और लचीलेपन से भरपूर कृषि भविष्य के निर्माण के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता पर जोर देना।
  - व्यावहारिक, किसान-केंद्रित सहयोग और कृषि एवं वानिकी में आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना।

भारत-मलेशिया द्विपक्षीय बैठक-

- आयोजन तिथि- 9 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल-नई दिल्ली
- आयोजक-कृषि अनुसंधान विभाग (डीएआरई) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
- **प्रतिनिधित्व-**
  - भारत- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
  - मलेशिया- कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री मोहम्मद बिन साबू
- **उद्देश्य-**
  - दोनों देशों के मध्य ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना।
  - संयुक्त कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को सुदृढ़ करना।
  - रोगाणु प्लाज्मा के आदान-प्रदान, व्यापार और बाजार पहुंच से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करना।

भारत-फिजी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी द्विपक्षीय बैठक

- संस्करण/बैठक/सत्र- दूसरी बैठक
- आयोजन तिथि-28 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक- दिए गए कंटेंट में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
- उद्देश्य- सैन्य प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग में सहयोग व भारत तथा फिजी की सशस्त्र सेनाओं के बीच संस्थागत सहयोग को और गहरा करना, तथा द्विपक्षीय रक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करना।

भारत-तिमोर-लेस्ते द्विपक्षीय बैठक-

- आयोजन तिथि- 9 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल-नई दिल्ली
- आयोजक-कृषि अनुसंधान विभाग (डीएआरई)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
- **प्रतिनिधित्व-**
  - भारत- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
  - तिमोर लेस्ते- कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन एवं वानिकी मंत्री श्री मार्कोस दा क्रूज़
- उद्देश्य-कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र का निर्माण करना।

भारत-म्यांमार द्विपक्षीय बैठक-

- आयोजन तिथि- 9 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल-नई दिल्ली
- आयोजक-कृषि अनुसंधान विभाग (डीएआरई)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
- **प्रतिनिधित्व-**
  - भारत- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
  - म्यांमार- कृषि, पशुधन एवं सिंचाई मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री मिन नौंग द्वारा किया गया)
- उद्देश्य-दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की संभावनाओं पर चर्चा करना, दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसी कृषि वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना तथा आर्थिक और कृषि संबंधों को मजबूत करना।

जी20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक-

- आयोजन तिथि- 14-16 सितम्बर 2026
- आयोजन स्थल-ह्यूस्टन, अमेरिका
- आयोजक-अमेरिका
- **उद्देश्य-**
  - वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा की वहनीयता, अवसंरचना विकास और सुदृढ़ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करना;
  - ऊर्जा सुरक्षा और वहनीयता को मजबूत करना,
  - कुशल नियामक ढांचे के माध्यम से ऊर्जा अवसंरचना के समयबद्ध विकास को सुगम बनाना
  - सुरक्षित, सुदृढ़ और विविधीकृत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।
- इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने किया।

ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद की बैठक-

- बैठक- सातवीं उच्च स्तरीय बैठक
- आयोजन तिथि-22 सितंबर,2026
- आयोजक- ओपेक और भारत (ओपेक सचिवालय/भारत सरकार)
- अध्यक्षता- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पूरी और ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस
- **उद्देश्य-**
  - तेल बाजार की स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और तेल उद्योग में पर्याप्त एवं समय पर निवेश के महत्व पर चर्चा करना।
  - एक संतुलित, स्थिर और पूर्वानुमानित वैश्विक ऊर्जा बाजार को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा सहयोग को और गहरा करना।

ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल 2026-

- आयोजन तिथि- 12 से 14 अक्टूबर, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- आयोजक- संस्कृति मंत्रालय (नोडल एजेंसी- राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय)
- विषय- "शेयर्ड स्टोरीज़, शेयर्ड फ़्यूचर्स"
- उद्देश्य- साझा कलात्मक मंच के माध्यम से कलाकारों, रंगमंच कर्मियों और दर्शकों को एक साथ लाकर ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग और जन-से-जन संबंधों को सुदृढ़ करना।

भारत-यूएई निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल (एचएलजेटीएफआई) की बैठक

- बैठक- 14वीं
- आयोजन तिथि-28 सितम्बर, 2026
- आयोजन स्थल- मुंबई
- आयोजक- भारत और यूएई
- **सह-अध्यक्षता-**
  - श्री पीयूष गोयल (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री)
  - शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान (अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) के प्रबंध निदेशक)
- उद्देश्य- द्विपक्षीय निवेश प्रवाह बढ़ाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की संभावनाओं का पता लगाने, व्यापार और निवेश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने तथा दोनों देशों के निवेशकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना।
- **प्रमुख तथ्य-**
  - वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 101.25 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि वर्ष 2025 में गैर-तेल व्यापार 76.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
  - दोनों देशों ने वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का साझा लक्ष्य रखा है।

भारत और इथियोपिया के बीच दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग (जेडीसी) बैठक

- बैठक- दूसरी बैठक
- आयोजन तिथि-28 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल- अदीस अबाबा
- उद्देश्य- सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, चिकित्सा सहयोग, शांति स्थापना और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में आपसी हित के विषयों पर चर्चा करना तथा रक्षा सहयोग गतिविधियों का विस्तार एवं उन्हें और प्रगाढ़ करना।
- **अन्य तथ्य-**
  - यह बैठक फरवरी 2025 में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से स्थापित संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा है।
  - पहली जेडीसी बैठक अक्टूबर,2025 में नई दिल्ली में हुई थी।
  - इथियोपिया और भारत की रक्षा साझेदारी 1958 में शुरू हुई थी।

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा उद्योग तथा लॉजिस्टिक्स सहयोग पर संयुक्त समिति की 10वीं बैठक (जेसीएम)

- बैठक-10वीं बैठक
- आयोजन तिथि-29 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली
- उद्देश्य- वर्तमान द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करना, रक्षा संबंधों को और मजबूत एवं व्यापक बनाना, रक्षा उद्योग जगत के बीच सहयोग को विस्तृत करना तथा रक्षा उत्पादन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अधिकतम भागीदारी को बढ़ावा देना।

पर्यटन संबंधी भारत-इटली संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक-

- बैठक- दूसरी बैठक
- आयोजन तिथि-29 सितंबर,2026
- आयोजक- भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और इटली का पर्यटन मंत्रालय
- **सह-अध्यक्षता-**
  - भुवनेश कुमार (भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव)
  - इमानुएला ट्रिपी (इटली के पर्यटन मंत्रालय की महासचिव)
- उद्देश्य– दोनों देशों के बीच पर्यटन संबंधी सहयोग को सुदृढ़ करना तथा संस्थागत और उद्योगगत संपर्क स्थापित करना।

विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कांग्रेस-2026-

- आयोजन तिथि- 30 सितंबर से 3 अक्टूबर,2026 तक
- आयोजन स्थल- नई दिल्ली

- आयोजक- इंडियन सोसाइटी ऑफ़ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गनाइज़ेशन
- विषय- "गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्वास्थ्य में बदलाव, प्रकृति का संरक्षण"।
  उद्देश्य- गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्वास्थ्य में हो रही प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना, ज्ञान साझा करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना तथा पाचन एवं लिवर की बीमारियों से निपटने के लिए नए तरीके व समाधान खोजना।
- भारत में पहली बार 'विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कांग्रेस' का आयोजन किया जा रहा है।

विविध तथ्य

- 25 सितंबर, 2026 को नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड (एनटीडब्ल्यूबी) की 11वीं बैठक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई।
- 9 सितम्बर, 2026 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीबीएसईएल) के सचिव, श्री टी. के. अनिल कुमार ने नई दिल्ली में उल्लास मेला का उद्घाटन किया।
- भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषध संहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) के अंतर्गत गठित सोवा-रिग्पा कार्य समूह की पहली बैठक 18 सितंबर,2026 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित पीसीआईएम एंड एच में आयोजित की गई।
- 22 सितंबर,2026को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी ने नई दिल्ली में 'मानित सदस्यों' के प्रतिनिधियों के साथ वैधानिक पूर्ण आयोग बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए आयोगों के बीच तालमेल और सहयोग को बेहतर बनाना था।
- राज्य सभा सचिवालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2026 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

Samyak
An Institute For Civil Services
Join our Social Media Platforms
YouTube
Samyak Civil Services
Instagram
Samyak Civil Services
Telegram
Samyak Civil Services
Whatsapp
Samyak Civil Services

निर्वाचन और नियुक्ति

राष्ट्रीय

विवेक हांडे-



- पदभार- महानिदेशक, चिकित्सा सेवा (भारतीय वायु सेना)
- पदभार ग्रहण तिथि- 01 सितंबर, 2026।
- यह पद भारतीय वायु सेना में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर ग्रहण किया है।
- वे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं।

एयर मार्शलकेएए संजीब-

- पदभार- एयर ऑफिसर-इन-चार्ज मेंटेनेंस।
- पदभार ग्रहण तिथि- 01 सितंबर, 2026।
- उन्होंने एयर मार्शलसंजीव घुरटियाका स्थान लिया है, जो 31 अगस्त 2026 को सेवानिवृत्त हुए।
- **पुरस्कार एवं सम्मान-**
  - विशिष्ट सेवा मेडल- वर्ष 2015
  - अति विशिष्ट सेवा मेडल-वर्ष 2026

शक्ति शर्मा-



- एयर वाइस मार्शलशक्ति शर्माभारतीय रक्षा बलों में एयर वाइस मार्शल या इसके समकक्ष 2 स्टार रैंक हासिल करने वालीपहली महिला (गैर-चिकित्सा) अधिकारी बन गई हैं।
- पदभार- असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ (शिक्षा)
- पदभार ग्रहण तिथि- 01 सितंबर, 2026।

एयर मार्शल संदीप थरेजा-

- पदभार-47वेंमहानिदेशक,सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय
- पदभार ग्रहण तिथि- 01 सितंबर, 2026।
- वे अब डीजीएएफएमएस के रूप में रक्षा सेनाओं को व्यापक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की देखरेख करेंगे।

वाइस एडमिरल मनीष होनवाड-

- पदभार-निदेशक और कमांडेंट,सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय-पुणे
- पदभार ग्रहण तिथि- 01 सितंबर, 2026।

वाइस एडमिरल दिलीप राघवन-

- पदभार-महानिदेशक,चिकित्सालय सेवा (सशस्त्र बल)
- पदभार ग्रहण तिथि- 01 सितंबर, 2026
- इनकों 26 जनवरी, 2026 को विशिष्ट सेवा पदक (वीएसएम) से सम्मानित किया गया था।

सुमन राय-

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 सितंबर 2026 से सुमन राय को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
- कार्यभार- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विभाग और परिसर विभाग के प्रमुख। इससे पहले राय महाराष्ट्र की क्षेत्रीय निदेशक थे।

दिनेश शर्मा

- इनको हाल ही में अंडमान-निकोबार का उपराज्यपाल बनाया गया है।
- यह यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा से राज्यसभा सांसद थे।

संदीप खिरवार-

- इनको सीआरपीएफ कामहानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह हरियाणा कैडर के 1995बैच के आइपीएस अधिकारी है।

पुनीत रस्तोगी-

- इनको बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह त्रिपुरा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी थे।

संजुक्ता पाराशर-

- इनकों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की विशेष जंगल वॉरफेयर कमांडो यूनिट 'कोबरा' की पहली महिला आईजी बनाया गया है। कमांडो यूनिट कोबरा साल 2008-09 में नक्सलवाद, उग्रवाद से निपटने के लिए गठित हुई थी।

प्रकाश राजपुरोहित-

- प्रकाश राजपुरोहित को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बोर्ड में पार्ट-टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर (सरकारी निदेशक) नियुक्त किया गया है। यह 2010 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है।

सुधा सिंह-

- हाल ही में केंद्र सरकार ने आइपीएस अधिकारी सुधा सिंह को प्रतिनियुक्ति के आधार पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में महानिरीक्षक पद पर तैनात किया है।
- वह ओडिशा कैडर की 2006 बैच की आइपीएस अधिकारी हैं।

हंसराज सिंह-

- इनकों क्यूबा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में साओ पाउलो में भारत के महावाणिज्य दूत हैं। यह 2008 बैच के आइएफएस अधिकारी है।

मनदीप भंडारी-

- हाल ही में भारत सरकार ने मनदीप भंडारी को सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे 2001 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले सीबीएसई अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार लोखंडे प्रशांत सीताराम के पास था।

जग मोहन-

- केंद्र सरकार ने 1995 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठआईपीएस अधिकारी जग मोहन को इंटेलिजेंस ब्यूरो कास्पेशल डायरेक्टरनियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति-

- राष्ट्रपति ने 8 सितंबर,2026 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।
- **नियुक्त-**

क्र.	नियुक्त व्यक्ति	विवरण
1.	संतोष शर्मा	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
2.	श्रीमती सुषमा सावंत	
3.	सुधीर कुमार	
4.	नचुम्बेमो मोझुई	गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
5.	श्रीमती हेलेन डाउंग्लिआनी	

- राष्ट्रपति ने 8 सितंबर,2026 को निम्न उच्च न्यायालयों में नए न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की-
- **नियुक्त-**

क्र.	नियुक्त व्यक्ति	विवरण
1.	श्रीमती निवेदिता अनिल शर्मा	दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
2.	श्रीमती निशा सहाय सक्सेना	
3.	संजय शर्मा	दिल्ली उच्च न्यायालय केअपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
4.	भरत पराशर	
5.	डॉ. (श्रीमती) अदिति चौधरी	
6.	दिनेश भट्ट	
7.	अरुण भारद्वाज	
8.	यश पॉल बॉर्नी	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
9.	मनोज प्रसाद	झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
10.	अखिल कुमार	
11.	राम शर्मा	
12.	श्रीमती उषारानी	कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
13.	के. एस. भरत कुमार	
14.	श्रीमती नेराले वी. भवानी	

अंतर्राष्ट्रीय

डॉ. विनय प्रकाश सिंह-

- भारतीय डाक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी डॉ. विनय प्रकाश सिंह को एशियाई-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) के महासचिव के रूप में लगातार दूसरी बार चार वर्षीय कार्यकाल के लिए पुनः चुने गएहै।
- 4 सितंबर, 2026 को बैंकॉक में आयोजित 14वें एपीपीयू सम्मेलन में उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उनका दूसरा कार्यकाल जनवरी, 2027 से शुरू होकर दिसंबर, 2030 तक रहेगा।
- **एशियाई-प्रशांत डाक संघ-**
  - मुख्यालय- बैंकॉक (थाईलैंड) में
  - वर्ष 2002 में इसका मुख्यालय मनीला (फिलिपिंस) से बैंकॉक स्थानांतरित किया गया था।
  - शुरुआत- 1 अप्रैल, 1962 को एशियन-ओशियनिक पोस्टल यूनियन के रूप में।
  - वर्तमान स्वरूप-27 मार्च,1981 को योग्याकार्ता में एशियन-पैसिफिक पोस्टल कन्वेंशनपर हस्ताक्षर किए गए, जो 1 जुलाई, 1982 को लागू हुआ।
  - इस समझौते के माध्यम से संगठन का नाम बदलकर एशियाई-प्रशांत डाक संघ किया गया।
  - सदस्य संख्या 32 देश

फातिमा जहरा मंसूरी-

- मोरक्को के किंग मोहम्मद हसन ने फातिमा जहरा मंसूरी को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 50 वर्षीय वकील मंसूरी मोरक्को में इस पद पर पहुंचने वाली पहली और किसी अरब देश की दूसरी महिला है।
- इससे पहले नजला बौदेन ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बनी थी।

अनिल चक्रवर्ती-

- यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। इनको सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी का प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह इस पद शांतनु नारायण की जगह लेंगे।

विविध तथ्य

- शोर्ट- श्री भगवत प्रसाद मकवाना ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग(एनसीएसके) के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारत सरकार ने इनकों 6 सितंबर, 2026 को इस पद पर नियुक्त किया था।
- शोर्ट- जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है।
- शोर्ट- टेवोल्डे गेब्रेमरियम- इनकों एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का नियुक्त किया गया है।
- शोर्ट- मुनपुई साईवी को वानुआटू गणराज्य में भारत की उच्चायुक्त बनाया गया है तथा चिन्मय नायक को गुयाना गणराज्य में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।
- शोर्ट- हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का पुनर्गठन किया। नए बोर्ड में 18 सदस्य हैं और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति अध्यक्ष हैं।

निधन

राष्ट्रीय

गौरंग व्यास-



- गुजराती संगीत जगत के दिग्गज संगीतकार, अरेंजर और गायक गौरंग व्यास का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'जेसल तोरल' फिल्म में अपने पिता के असिस्टेंट के रूप में की थी।
- अपने करियर के दौरान उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया।
- **प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार-**
  - गुजराती सिनेमा और संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें लगभग 11 'बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन' अवॉर्डप्राप्त हुए।
  - लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (2022)- गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा सम्मानित किया गया।
  - विशेष सम्मान (2024)- गुजरात राज्य संगीत अकादमी और गुजरात टूरिज्म द्वारा संयुक्त रूप से विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

मुश्ताक खान-



- हाल ही में मशहूर अभिनेता मुश्ताक खान का निधन हो गया।
- इनका जन्म बैहर बालाघाट जिला (मध्यप्रदेश) में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। मुश्ताक ने 'वेलकम', 'आशिकी', 'हम हैं राही प्यार के' व 'मुझसे शादी करोगी' जैसी फिल्मों में किरदार निभाए है।

नागरमल बाजोरिया-

- यह बिहार के भागलपुर निवासी और 'धरतीपकड़' के नाम से मशहूर व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने नगर निकाय से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक 280 से अधिक बार चुनावी पर्चा भरा।
- यह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे नेताओं के खिलाफ भी मैदान में उतरे। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक के खिलाफ पर्चा दाखिल किया था। हालांकि, किसी चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली।

कृष्णा अच्युतराव-

- यह आइआइटी दिल्ली के प्रख्यात जलवायु वैज्ञानिकऔर प्रोफेसर थे जिनका निधन हो गया।

सुदिव्य कुमार-

- यह झारखंड सरकारके कैबिनेट मंत्री थे जिनका निधन हो गया।
- वे नगर विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की जिम्मेदार संभाल रहे थे।

आर. सारथ-

- यह मलयालम फिल्म निर्माता थे जिनका 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने सात केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते थे।

सोलोमन पप्पैया-

- यह तमिल विद्वान, पूर्व प्रोफेसर और टीवी डिबेट संचालक है जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे तमिल भाषा के पारंपरिक बहस मंच 'पत्तिमन्त्रम' के संचालक थे। उन्होंने तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति को आसान भाषा और हास्य के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया।

फराज हामिदी-

- यह उर्दू के मशहूर शायर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया।

विश्वंभर मोदी-

- यह जयपुर के प्रसिद्ध समाजसेवी, वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है।

राजीव शर्मा-

- यह इंटरनेशनल एथलीट व भारतीय महिला टीम के पूर्व कोच थे जिनका हाल ही में निधन हो गया।
- यह महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित

सावित्री श्रीधरन-

- यह मलयालम सिनेमा और थिएटर की मशहूर एक्ट्रेस थी जिनका हाल ही में निधन हो गया।
- फिल्म 'सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया' में 'जमीला' के रोल से उन्हें पूरे देश में पहचान मिली।
- इस रोल के लिए उन्हें 66वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में स्पेशल मेंशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

पायलमेहता-

- यह देश की जानी-मानी वरिष्ठपत्रकार थी जिनका 46 साल की उम्र में निधन हो गया। यह राष्ट्रीय राजनीति की वरिष्ठ पत्रकार थीं और संसद, केंद्र सरकार तथा राष्ट्रीय राजनीतिक मामलों की रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थीं।

अंतर्राष्ट्रीय

कैसेंड्रा विल्सन-

- यह अमरीकी गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है।
- यह दो बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता थ। विल्सन को 2001 में टाइम पत्रिका ने 'अमरीका की सर्वश्रेष्ठ गायिका' बताया था।

शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम-

- यह संयुक्त अरब अमीरात के शेख थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। यह वर्तमान में यूएई के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक के भाई थे।

अभियान/ओपरेशन /युद्धअभ्यास

अभ्यास तरंग शक्ति-2026



- संस्करण- दूसरा संस्करण
- आयोजन तिथि- 26 सितंबर से 12 अक्टूबर, 2026
- आयोजन स्थल- जोधपुर वायु सेना स्टेशन
- विषय- 'साझेदारी में शक्ति'
- आयोजक- भारतीय वायु सेना
- उद्देश्य-आपस में मिलकर काम करने, जानकारी और अनुभव साझा करने तथा भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच आपसी सहभागिता और साथ मिलकर काम करने की क्षमता को सशक्त करने से प्राप्त सामूहिक शक्ति को उजागर करना तथा दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करना।
- **प्रमुख तथ्य-**
  - इस अभ्यास में सात मित्र देश (ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश) भाग ले रहे हैं तथा कई अन्य देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे।
  - इसमें एफ-35 लाइटनिंग-2, राफेल, एफ-16, ए400एम, एमM-RTटी, सी-130, सी-130जे और केसी-30ए जैसे विदेशी विमान भाग ले रहे हैं, जो लड़ाकू अभियानों, हवाई परिवहन और हवा में ईंधन भरने जैसी विभिन्न परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे।
  - इसका पहला संस्करण साल 2024 में आयोजित किया गया था।
  - यह अभ्यास भारत की बढ़ती स्वदेशी एयरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है।

एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2026-

- संस्करण-18वां
- आयोजन तिथि-21 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2026
- आयोजन स्थल- विदेशी प्रशिक्षण केंद्र, पिथौरागढ़, उत्तराखंड
- आयोजक- भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बल
- उद्देश्य- संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध-शहरी और पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना।
- संयुक्त प्रशिक्षण में सामरिक स्तर के अभियानों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान, संचालन अभ्यासों को अत्याधुनिक बनाने और अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित जा रहा है।

- यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा तथा दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और आपसी विश्वास को मजबूत करेगा।
- प्रमुख तथ्य-
  - यह भारत और मंगोलिया में बारी-बारी से आयोजित होने वाला वार्षिक प्लाटून स्तरीय अभ्यास है।
  - इसका पिछला अभ्यास मई-जून,2025 में मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित किया गया था।

संयुक्त सैन्य अभ्यास कज़िंद-2026-

- संस्करण - नौवां संस्करण
- आयोजन तिथि-28 सितंबर से 11 अक्टूबर,2026
- आयोजन स्थल- ओस्केमेन, कजाकिस्तान
- आयोजक- भारतीय सशस्त्र बल और कजाकिस्तान सशस्त्र बल
- उद्देश्य- अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत एक उप-पारंपरिक वातावरण में संयुक्त आतंकवाद-विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों बलों की संयुक्त क्षमता को मजबूत करना।
- भारतीय सशस्त्र बलों का 60 सदस्यीय दल इस अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन के जवान, अन्य सैन्य बलों के जवान और भारतीय वायु सेना के जवान शामिल हैं।
- यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग को और गहरा करेगा तथा क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा।

आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (एआईएमई-2026)-

- संस्करण- दूसरा
- आयोजन तिथि-28 सितंबर, 2026 से शुरू
- आयोजन स्थल- सुबिक बे, फिलीपींस
- विषय-"विश्वास में अटूट, समुद्र में एकजुट"
- आयोजक- भारतीय नौसेना और आसियान सदस्य देशों की नौसेनाएं
- उद्देश्य– भारत और आसियान देशों की समुद्री सेनाओं को पेशेवर, परिचालन एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए एक मंच पर लाना तथा आपसी समझ, सहयोग एवं सहभागिता को बढ़ाना।
- इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज सह्याद्रि और कुलिश के साथ आसियान सदस्य देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया।

नौसेना अभ्यास 'समुद्र लक्ष्मण'-

- संस्करण- 4वां संस्करण
- आयोजन तिथि- 9-12 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल-लुमुट, मलेशिया
- आयोजक-भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना
- **उद्देश्य-**
  - भारत और मलेशिया के बीच नौसैनिक सहयोग, अंतर-संचालन क्षमता और परिचालन समन्वय को बढ़ाना।
  - पेशेवर सहयोग को मजबूत करना
  - दोनों नौसेनाओं की समन्वित समुद्री अभियान संचालित करने की क्षमता को बढ़ाना।
- **प्रमुख तथ्य-**
  - समुद्र लक्ष्मण भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
  - इस अभ्यास में आईएनएसमैसूर शामिल हुआ।

कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव टेबल टॉप एक्सरसाइज-2026

- आयोजन तिथि- 9 से 12 सितंबर, 2026
- आयोजन स्थल- पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम
- संबद्ध मंच- कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव
- उद्देश्य- हिंद महासागर क्षेत्रमें गैर-कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए एक समन्वित प्रतिक्रियाविकसित करना।
- यह अभ्यास क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सदस्य देशों के सामूहिक संकल्प को दोहराता है।
- यह आयोजन भारत के 'महासागर' (MAHASAGAR) विजन के पूर्णतः अनुरूप है।
  - MAHASAGAR- Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions

स्लिनेक्स-26-

- यह भारत-श्रीलंका वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
- संस्करण- 13वां संस्करण, आयोजन तिथि- 17 से 21 सितंबर 2026
- आयोजन स्थल- विशाखापत्तनम
- आयोजक- पूर्वी नौसेना कमान
- उद्देश्य- भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग, आपसी सहभागिता एवं दोनों देशों के बीच समझ को बढ़ावा देना।
- **प्रमुख तथ्य-**
  - इस अभ्यास की शुरुआत बंदरगाह चरण से हुई है, जिसके बाद समुद्री चरण का आयोजन किया गया।
  - इसमें भारतीय नौसेना की ओर से पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत आईएनएस कवरत्ती और बेड़े का टैंकर जहाज आईएनएस ज्योति तथा श्रीलंका नौसेना की ओर से एसएलएनएस सिंदुराला ने हिस्सा लिया।
  - यह अभ्यास भारत के 'महासागर दृष्टिकोण' के अनुरूप सुरक्षित, स्थिर व समावेशी समुद्री वातावरण के प्रति भारत की वचनबद्धता और द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी को मजबूत करता है।
  - 'स्लिनेक्स' अभ्यास की शुरुआत साल 2005 में हुई थी।

अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयरशो-



- संस्करण- द्वितीय
- आयोजन तिथि-8 से 10 सितंबर,2026
- आयोजन स्थल- अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मिस्र
- आयोजक- मिस्र का रक्षा मंत्रालय, वायु सेना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मिस्र की अंतरिक्ष एजेंसी
- वैश्विक भागीदारी- 80 से अधिक देश
- भारतीय वायु सेना का प्रदर्शन-भारत की तरफ से इसमें 'सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम' ने भाग लिया और स्वदेशीएडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर 'ध्रुव' के साथ प्रदर्शन किया।

वीर गार्जियन-2026-

- आयोजन तिथि- 9 से 22 सितंबर,2026 तक (चौदह दिवसीय)
- आयोजन स्थल- जोधपुर वायुसेना छावनी
- आयोजक- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और जापान वायु आत्मरक्षा बल (जेएएसडीएफ)
- उद्देश्य-
  - सामरिक दक्षता और एयरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर भारत और जापान के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी, लंबे समय से चले आ रहे सहयोग व मित्रता को मजबूत करना।
  - उन्नत परिचालन मिशनों व व्यापक पेशेवर संवाद के माध्यम से दोनों वायु सेनाओं के बीच गहन परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना।

ड्रोनाथॉन-2026-



- संस्करण- पहला
- आयोजन तिथि- 14 से 16 सितंबर 2026 (तीन दिवसीय)
- आयोजन स्थल- पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर
- आयोजक- भारतीय वायु सेना
- उद्घाटन- आशुतोष दीक्षित (शुभारंभ वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल)
- उद्देश्य- भारत की बिना पायलट वाली हवाई प्रणालियों के उद्योग से सीधे जुड़ना, वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में उभरती नई तकनीकों का परीक्षण करना तथा मानवरहित हवाई प्रणालियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाना।
- 'वायु उत्तम'- स्वदेशी रूप से विकसित बहु-आयामी मानवरहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली (यूटीएम) 'वायु उत्तम' की वास्तविक समय की क्षमता का सफल प्रदर्शन किया गया, जो सैन्य व असैन्य मानवरहित विमानों की निगरानी और हवाई क्षेत्र सुरक्षा में सहायक है।

ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट-

- कार्यवाहीकर्ता एजेंसी- राजस्व खुफिया निदेशालय
- बरामदगी- पाकिस्तान मूल के 362 मीट्रिक टन से अधिक सूखे खजूर

विविध

'भारत इनोवेट्स 2026' स्मारक पुस्तक का विमोचन-



- विमोचन तिथि- 9 सितंबर 2026
- विमोचनकर्ता-प्रह्लाद जोशी (केंद्रीय शिक्षा मंत्री)
- यह पुस्तक पूरे देश से डीप-टेक नवोन्मेषकों के चयन से लेकर नीस (फ्रांस) में उनके अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन, आपसी सहभागिता और उससे निकले परिणामों का पूर्ण दस्तावेजीकरण करती है।
- **भारत इनोवेट्स-**
  - यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है।
  - उद्देश्य-भारत के उच्च शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े इकोसिस्टम से उभरने वाले उच्च-क्षमता वाले डीप-टेक नवाचारों की पहचान करना और उन्हें पोषित करना।
  - विजन- 'प्रयोगशाला से बाजार'और 'परिसर से दुनिया' तक एक निर्बाध और सुगम मार्ग तैयार करना।

- **'भारत इनोवेट्स' का आयोजन-**
  - संस्करण- पहला
  - आयोजन तिथि- 14 से 16 जून,2026
  - आयोजन स्थल- नीस, फ्रांस

जोहेरी मोला-

- डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोला मिस वर्ल्ड-2026 बनीं है।
- मिस वर्ल्ड 2026 का 73वां संस्करण वियतनाम में आयोजित किया गया। स्पेन की एलिजाबेथ रेयनेस पहली रनर-अप और मलेशिया की तानुसिया चेट्टी दूसरी रनर-अप रहीं।

क्राकाटोआ ज्वालामुखी-

- सुर्ख़ियों में- हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है।
- अवस्थित- सुंडा जलडमरूमध्य में (इंडोनेशिया)

सारंगटीम-

- यह भारतीय वायुसेना की पाँच हेलिकॉप्टरों वाली टीम थी। इस टीम नें 8 -10 सितंबर,2026 तक ए-अलमीन इंटरनेशनल एयरशो, मिस्रमें हिस्सा लिया।

रोमांच महाजन 'ट्री ऑफ लाइफ' में जगह पाने वाले पहले भारतीय-

- हाल ही में पठानकोट के रोमांच महाजन कोअमेरिका में मरणोपरांत सम्मान मिला है। वहयह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं।
- पेटा (पशु अधिकार संस्था) ने अपने वर्जीनिया स्थित मुख्यालय के ट्री ऑफ लाइफ मेमोरियल में एक पत्ती पर रोमांच का नाम उकेरा है।

झांग यिमिंग-

- टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस के संस्थापक झांग यिमिंग ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।
- उन्होंने गौतम अडाणी को पीछे छोड़ दिया है। इनकी संपत्ति 105 अरब डॉलर से अधिक हो गई है।

राघव चड्ढा-

- यह राज्यसभा सांसद है। इन्होंने उज्बेकिस्तान केसमरकंद में युवा सांसदों के वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- आयोजन तिथि- 4-6 सितंबर, 2026

■■■■■

महत्वपूर्ण दिवस

दिनांक	दिवस	उद्देश्य/महत्व	2025 की थीम	स्थापना/विशेष तथ्य
2 सितम्बर	विश्व नारियल दिवस	नारियल की खेती और उपभोग के लाभों के बारे में जागरूकता	Coconuts in times of uncertainty: Securing food, energy, and livelihoods	प्रतिवर्ष 2 सितम्बर को मनाया जाता है
5 सितम्बर	शिक्षक दिवस (भारत)	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षकों के योगदान को सम्मान	–	प्रथम उपराष्ट्रपति (1952-62), द्वितीय राष्ट्रपति (1962-67)
8 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस	शिक्षा और साक्षरता के महत्व पर जागरूकता	Literacy for people, the planet and prosperity	1966 में UNESCO द्वारा घोषित
8 सितम्बर	विश्व फिजियोथेरेपी दिवस	स्वास्थ्य सुधार और गतिशीलता में फिजियोथेरेपिस्टों की भूमिका को मान्यता	स्वस्थ वृद्धावस्था: कमजोरी और गिरने से बचाव	1996 से विश्व फिजियोथेरेपी संगठन द्वारा
10 सितम्बर	विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस	आत्महत्या रोकथाम और जागरूकता	Changing the Narrative on Suicide	2003 से IASP और WHO के सहयोग से
11 सितम्बर	राष्ट्रीय वन शहीद दिवस	प्राकृतिक विरासत की रक्षा हेतु बलिदानों को याद करना	–	2013 में MoEFCCद्वारा घोषित
13 सितम्बर	विश्व प्राथमिक उपचार दिवस	प्राथमिक उपचार और जलवायु आपात स्थितियों पर जागरूकता	प्राथमिक उपचार और जलवायु परिवर्तन	IFRC द्वारा, सितंबर का दूसरा शनिवार
14 सितम्बर	हिंदी दिवस	हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना और राजभाषा के रूप में स्थापित करना	–	14 सितम्बर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला
15 सितम्बर	राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस	इंजीनियरिंग क्षेत्र के योगदान का सम्मान	–	भारत रत्न एम. विश्वेश्वरैया की जयंती
16 सितम्बर	विश्व ओजोन दिवस	ओज़ोन परत की सुरक्षा और जागरूकता	Global Action for a Cooler Planet	मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) की याद में
17 सितम्बर	विश्व रोगी सुरक्षा दिवस	स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा को बढ़ावा देना	-	WHO द्वारा 2019 में स्थापित
18 सितम्बर	विश्व बांस दिवस	बांस को सतत और बहुउपयोगी संसाधन के रूप में बढ़ावा देना	Bamboo Beyond Borders	प्रतिवर्ष 18 सितम्बर को मनाया जाता है
21 सितम्बर	अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस	वैश्विक शांति के आदर्शों को मजबूत करना	–	UN द्वारा स्थापित
21 सितम्बर	विश्व अल्ज़ाइमर दिवस	अल्ज़ाइमर रोग के प्रति जागरूकता	–	रोग का पहला वर्णन डॉ. एलोइस अल्ज़ाइमर (1906)

22 सितम्बर	विश्व गैंडा दिवस	गैंडों के संरक्षण पर जागरूकता	Keep the Five Alive	भारतीय गैंडा: Rhinoceros unicornis
22सितम्बर	विश्व गुलाब दिवस	कैंसर रोगियों और देखभाल करने वालों को सम्मान	–	प्रतिवर्ष 22 सितम्बर को मनाया जाता है
23 सितम्बर	सांकेतिक भाषा दिवस	सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता	-	प्रतिवर्ष 23 सितम्बर को मनाया जाता है
23 सितम्बर	आयुर्वेद दिवस	आयुर्वेद को बढ़ावा देना	Ayurveda for a Healthier Tomorrow	2025 से निश्चित तिथि 23 सितम्बर, AIIA गोवा में आयोजन
24 सितम्बर	विश्व गोरिल्ला दिवस	गोरिल्ला और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण पर जागरूकता	–	प्रतिवर्ष24 सितम्बर को मनाया जाता है
25 सितम्बर	विश्व फेफड़ा दिवस	फेफड़ों के स्वास्थ्य पर जागरूकता	-	प्रतिवर्ष 25 सितम्बर को
25 सितम्बर	विश्व फार्मासिस्ट दिवस	स्वास्थ्य सेवा में फार्मासिस्टों की भूमिका को मान्यता	-	FIP (International Pharmaceutical Federation) द्वारा
25 सितम्बर	अंत्योदय दिवस	समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के विचार का सम्मान	–	पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती
26 सितम्बर	यूरोपीय भाषा दिवस	बहुभाषावाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन	–	2001 में यूरोप परिषद द्वारा शुरू
27 सितम्बर	विश्व पर्यटन दिवस	सतत पर्यटन पर जागरूकता	Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism	UNWTO, 2025 आयोजन मलक्का (मलेशिया)
29 सितम्बर	विश्व हृदय दिवस	हृदय रोग और स्ट्रोक पर जागरूकता	-	प्रतिवर्ष 29 सितम्बर को



भारत में परमाणु ऊर्जा

डॉ॰ हेमेन्द्र कुमार सिंह

- परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) वह शक्ति है जो किसी परमाणु के केंद्र यानी नाभिक से निकलती है। यह ऊर्जा परमाणुओं को आपस में बांधकर रखने वाले बलों से आती है। इसे परमाणु के टूटने या जुड़ने की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकाला जाता है

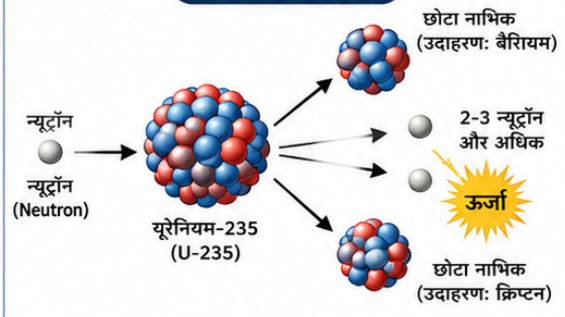
परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने की विधियाँ

परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत

परमाणु विखंडन (Nuclear Fission)

इसमें यूरेनियम जैसे भारी परमाणु का नाभिक दो छोटे भागों में टूटता है। इस प्रक्रिया में अपार गर्मी और ऊर्जा पैदा होती है। बिजली घरों में इसी तकनीक का उपयोग होता है।

यह कैसे होती है?



मुख्य विशेषताएँ

- भारी नाभिक (जैसे यूरेनियम-235) टूटता है।
- इसमें न्यूट्रॉन निकलते हैं और और विखंडन की श्रृंखला आरंभ हो सकती है।
- अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है।
- उपयोग: परमाणु बिजली घरों में विद्युत उत्पादन।

उदाहरण

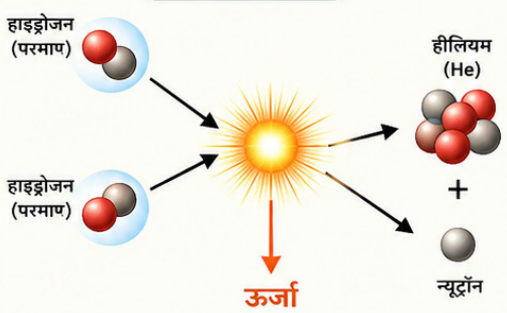
परमाणु विद्युत संयंत्र
(जैसे – तारापुर, काकरापार, रावतभाटा)



परमाणु संलयन (Nuclear Fusion)

इसमें हल्के परमाणु (जैसे हाइड्रोजन) आपस में जुड़कर भारी परमाणु (जैसे हीलियम) बनाते हैं। सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा इसी प्रक्रिया से बनती है।

यह कैसे होती है?



मुख्य विशेषताएँ

- हल्के नाभिक (जैसे हाइड्रोजन) जुड़ते हैं।
- अत्यधिक ताप और दाब की आवश्यकता होती है।
- बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
- उपयोग: भविष्य में स्वच्छ और असीमित ऊर्जा का स्रोत।

उदाहरण

सूर्य और अन्य तारे
(जहाँ हाइड्रोजन से हीलियम बनता है)





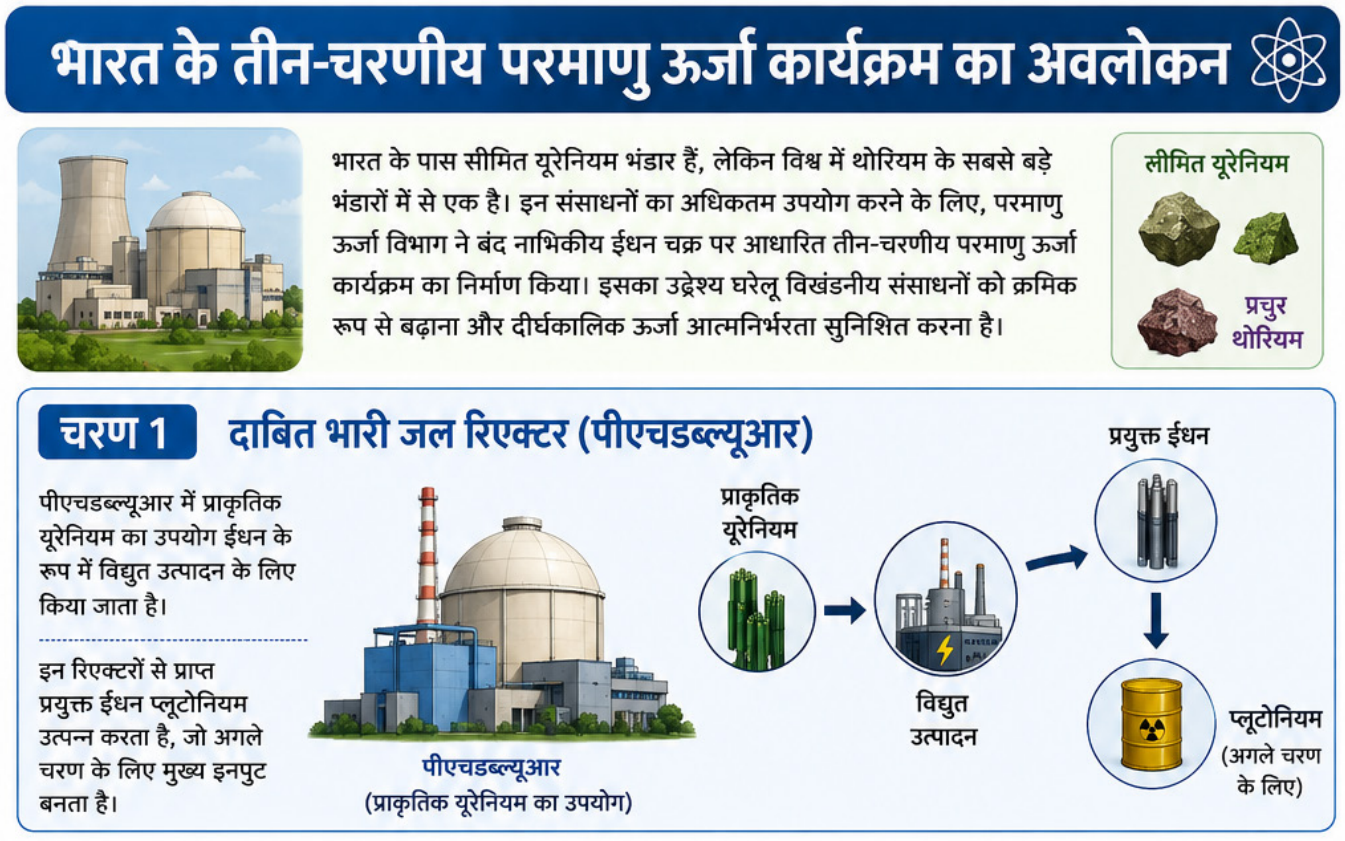
- भारत की ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ रही है और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति उसकी प्रतिबद्धताएँ दृढ़ हैं। परमाणु ऊर्जा विद्युत का एक बेस लोड स्रोत है, जो चौबीसों घंटे उपलब्ध रहता है, और इसके जीवनचक्र उत्सर्जन जल और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों के तुलनीय हैं। यह डेटा केंद्रों, उन्नत उद्योगों और उभरती प्रौद्योगिकियों की निरंतर बनी रहने वाली विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है। इसलिए परमाणु क्षमता का विस्तार भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के लिए केवल एक रणनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक आवश्यकता है।

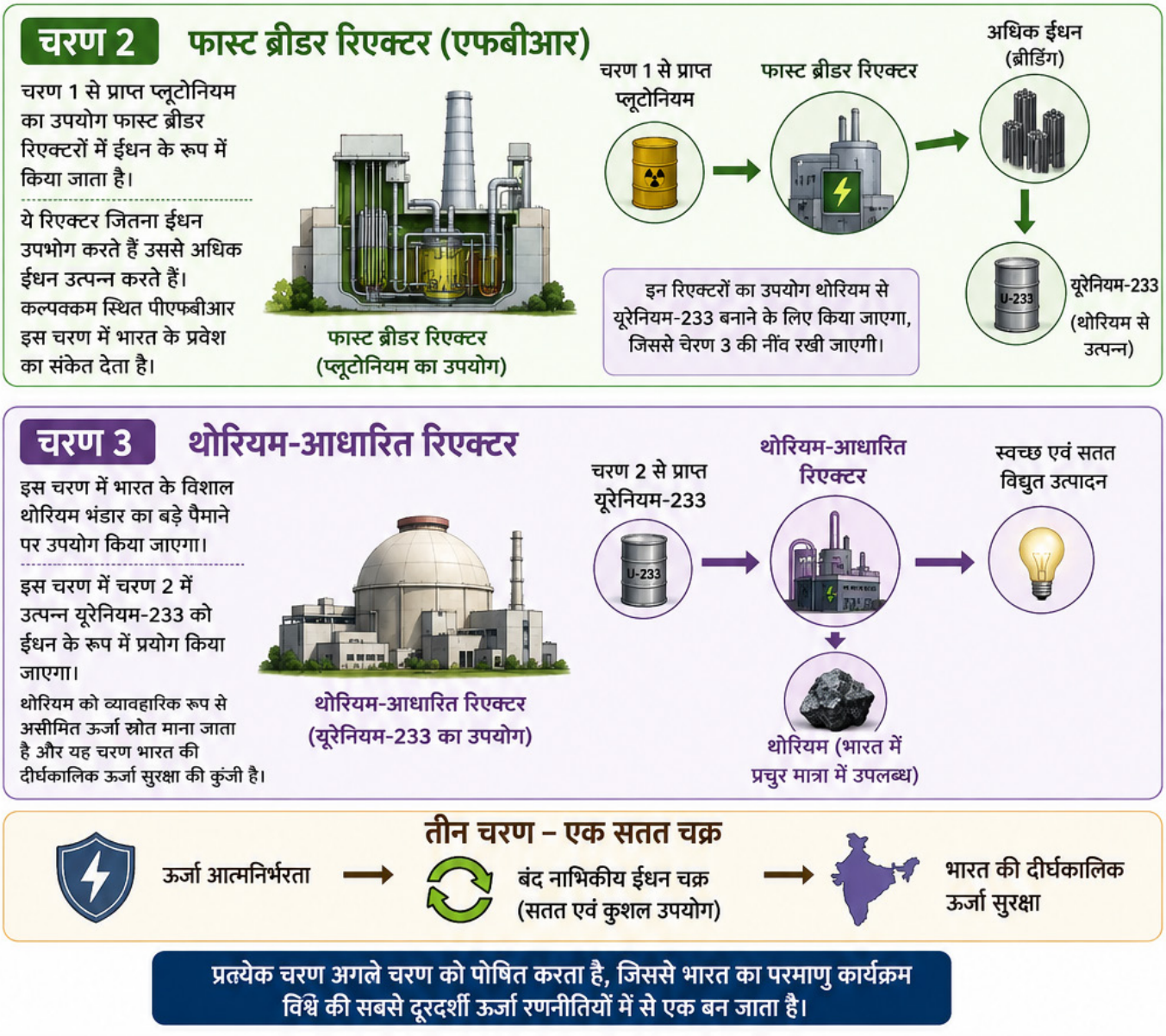


- भारत ने वर्ष 2047 तक परमाणु विद्युत क्षमता को 8.78 GW से बढ़ाकर 100 GW करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य विकसित भारत, 2070 के नेट-ज़ीरो लक्ष्य तथा विश्वसनीय कम-कार्बन बिजली की आवश्यकता से जुड़ा है।
- जुलाई 2026 तक भारत में 24 परिचालित परमाणु रिएक्टरों की कुल स्थापित क्षमता 8.78 GW थी और 2025–26 में कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 3.1% थी।
- भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के 6 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक अपनी प्रथम क्रिटिकैलिटी (स्व-धारित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की स्थिति) प्राप्त कर की, जो एक सतत् परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया की शुरुआत का संकेत है। यह पीएफबीआर एक 500 मेगावाट विद्युत (एमडब्ल्यूई) रिएक्टर है, जिसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) द्वारा कल्पक्कम नाभिकीय परिसर में निर्मित किया गया है।
- इस उपलब्धि के साथ, भारत आधिकारिक रूप से अपने तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है, जिसकी परिकल्पना सबसे पहले भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार डॉ. होमी जहाँगीर भाभा ने की थी। यह कीर्तिमान वैश्विक स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से संचालन में आने के बाद, भारत रूस के बाद दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा जो एक वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संचालन करेगा। यह भारत को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य के और निकट लाता है।

क्रिटिकैलिटी क्या है?

- क्रिटिकैलिटी वह बिंदु है जिस पर एक सतत् और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ होती है। इस अवस्था में विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन की संख्या अवशोषण और रिसाव के चलते खोए गए न्यूट्रॉनों के बराबर होती है, जिससे स्थिर ऊर्जा उत्पादन प्राप्त होता है। यह निर्माण चरण से संचालन चरण में परिवर्तन को दर्शाता है और ऊष्मा तथा अंततः विद्युत उत्पादन की दिशा में पहला आवश्यक कदम है।





पीएफबीआर: एक अवलोकन

- पीएफबीआर स्वदेशी अनुसंधान, डिजाइन और अभियांत्रिकी में लगे दशकों के प्रयास को दर्शाता है। इसकी प्रौद्योगिकी का विकास परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) द्वारा किया गया था।

पीएफबीआर: एक अवलोकन

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

पीएफबीआर स्वदेशी अनुसंधान, डिजाइन और अभियांत्रिकी में लगे दशकों के प्रयास को दर्शाता है। इसकी प्रौद्योगिकी का विकास इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) द्वारा किया गया था।

1 ईंधन और डिजाइन

यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (एमओएक्स) ईंधन का उपयोग। प्रयुक्त विखंडनीय पदार्थ डाबर भारी जल रिएक्टरों से प्राप्त प्रयुक्त ईंधन के पुनर्संसाधन से। चरण 1 का चक्र पूर्ण।

2 जितना उपभोग करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है

कोर यूरेनियम-238 की ब्लैंकेट से घिरा। तीव्र न्यूट्रॉन उपजाऊ पदार्थ को विखंडनीय प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित करते हैं। रिएक्टर अपने उपभोग से अधिक ईंधन उत्पन्न करता है।

3 चरण 3 के लिए सेतु

ब्लैंकेट में थोरियम-232 के उपयोग के लिए डिजाइन।
ट्रांसम्यूटेशन से थोरियम-232 को यूरेनियम-233 में परिवर्तित।
थोरियम आधारित तीसरे चरण का ईंधन।

4 बंद ईंधन चक्र

प्रयुक्त ईंधन का पुनर्संसाधन कर पुनः उपयोग।
दूसरे चरण का ईंधन चक्र पूर्ण। भारत के प्रचुर थोरियम भंडार के बड़े पैमाने पर उपयोग का मार्ग।

भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र

स्वच्छ, विश्वसनीय और सतत ऊर्जा की दिशा में भारत का महत्वपूर्ण कदम

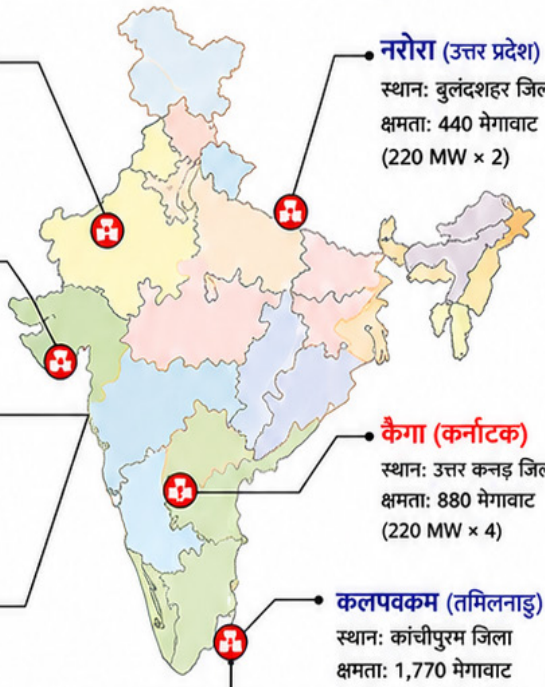
परमाणु ऊर्जा क्या है?

परमाणु ऊर्जा, परमाणु नाभिक को अभिक्रियाओं (विखंडन और तदनुकर) के प्रयोग द्वारा, बिजली उत्पादन किसी उत्सर्जन के लिए किया जाता है। यह स्वच्छ, विश्वसनीय और उच्च दक्षता वाली ऊर्जा का स्रोत है।

भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति (2025 तक)

परिचालित रिएक्टर	स्थापित क्षमता	कुल बिजली उत्पादन में योगदान	लक्ष्य
24	8,780 मेगावाट (8.78 GW)	लगभग 3.1%	2031-32 तक 22,480 मेगावाट

भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र



रावतभाटा (राजस्थान)
स्थान: चित्तौड़गढ़ जिला
क्षमता: 1,180 मेगावाट
(220 MW × 5 + 100 MW × 1)

काकरापार (गुजरात)
स्थान: तापी जिला
क्षमता: 1,880 मेगावाट
(220 MW × 2 + 700 MW × 2)

तारापुर (महाराष्ट्र)
स्थान: पालघर जिला
क्षमता: 1,400 मेगावाट
(160 MW × 2 + 540 MW × 2)

जेतापुर (महाराष्ट्र)
स्थान: रत्नागिरी जिला
क्षमता: 6,600 मेगावाट
(1650 MW × 4)

नरोरा (उत्तर प्रदेश)
स्थान: बुलंदशहर जिला
क्षमता: 440 मेगावाट
(220 MW × 2)

कैगा (कर्नाटक)
स्थान: उत्तर कन्नड़ जिला
क्षमता: 880 मेगावाट
(220 MW × 4)

कलपक्कम (तमिलनाडु)
स्थान: कांचीपुरम जिला
क्षमता: 1,770 मेगावाट
(220 MW × 2 + 540 MW × 2)

कुडनकुलम (तमिलनाडु)
स्थान: तिरुनेलवेली जिला
क्षमता: 2,000 मेगावाट
(1000 MW × 2)

परमाणु ऊर्जा केंद्र

नोट: सभी आंकड़े लगभग हैं। स्रोत: NPCIL, PIB, सरकारी आंकड़े

भारत किन देशों के सहयोग से परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं चला रहा हैं?

रूस (Russia)
- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (KKNPP)
- 1000 मेगावाट के VVER-1000 रिएक्टर
- रूस के ROSATOM के सहयोग से

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
- तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र (TAPS)
- बाईलिंग वॉटर रिएक्टर (BWR)
- जनरल इलेक्ट्रिक (GE) की तकनीक

फ्रांस (France)
- जेतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना (JAPS)
- EPR-1650 रिएक्टर
- फ्रांस की EDF कंपनी के सहयोग से

कनाडा (Canada)
- रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र (RAPS)
- CANDU (PHWR) रिएक्टर
- कनाडा की AECL कंपनी के सहयोग से

IAEA तथा अन्य देशों से सहयोग
- सुरक्षा मानकों, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सतत सहयोग।

भारत में प्रमुख रिएक्टर तकनीक/प्रौद्योगिकी

रिएक्टर का प्रकार	उपयोगी केंद्र	प्रयोग में प्रमुख क्षेत्र	विशेषताएँ
PHWR (प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर)	रावतभाटा, नरोरा, काकरापार, कैगा	सभी चालू केंद्र (स्वदेशी यूरेनियम तकनीक) का आधार	स्थानीय यूरेनियम पर आधारित, सस्ती तकनीक, उच्च सुरक्षा
BWR (बॉइलिंग वाटर रिएक्टर)	तारापुर (TAPS)	GE (USA) तकनीक	पानी को ही कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में उपयोग
VVER (प्रेशर वॉटर इनर्जी रिएक्टर)	कुडनकुलम (KKNPP)	ROSATOM (रूस) तकनीक	उच्च सुरक्षा मानक, दक्षता एवं लोड, स्वीचसनीयन एंड्रायन
EPR (यूरोपियन प्रेसराईज्ड रिएक्टर)	जेतापुर (निर्माणाधीन)	EDF (फ्रांस) तकनीक	तीसरी पीढ़ी की अत्य तकनीक, उच्च सुरक्षा और दक्षता है।
CANDU (कनाडियन PHWR)	रावतभाटा (RAPS)	AECL (कनाडा) तकनीक	भारी जल रिएक्टर, उच्च्य ऊर्जा लचीला ईंधनुनिय मी तकनीक

भारत का तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

चरण-1
प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग (PHWR)
ईंधन: प्राकृतिक यूरेनियम

चरण-2
प्लूटोनियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR)
ईंधन: U-233

चरण-3
थोरियम आधारित रिएक्टर (U-233 का उपयोग)
ईंधन: थोरियम का उनेधिवयम अत्यधिक और सस्ती आत्मनिर्भरता

भारत का लक्ष्य
- स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना
- ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण
- 2031-32 तक 22,480 मेगावाट क्षमता प्राप्त करना
- वैज्ञानिकी वे इंजीनियर आपपरित ख़र्ता में अग्रणी बनना

परमाणु ऊर्जा के लाभ

स्वच्छ ऊर्जा
उत्सर्जन रहित और पर्यावरण के अनुकूल

विश्वसनीय आपूर्ति
24×7 विश्वसनीय बिजली का स्रो ऊर्जा

ऊर्जा सुरक्षा
आयात पर निर्भरता कम करनां रो

आर्थिक विकास
औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में सहायक

रोजगार एवं कौशल
उच्च गुणतनीह आशाजिव रोजगार के अवसर

परमाणु ऊर्जा – आज की आवश्यकता, कल की समृद्धि

भारत का वर्तमान परमाणु ऊर्जा परिदृश्य



भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम देश के विद्युत मिश्रण में लगातार उपस्थिति बनाए हुए है और तेज विस्तार की ओर अग्रसर है।

1. स्थापित क्षमता



- भारत की वर्तमान परमाणु क्षमता **8.78 गीगावाट** (जीडब्ल्यू) है।
- वर्ष 2024–25 में, पूरे देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने **56,681 मिलियन यूनिट** विद्युत का उत्पादन किया।

2. स्थिर योगदान



- परमाणु ऊर्जा ने भारत के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग **3%** हिस्सा लगातार प्रदान किया है।
- वर्ष 2024–25 में इसका हिस्सा **3.1%** रहा।

3. नियोजित विस्तार

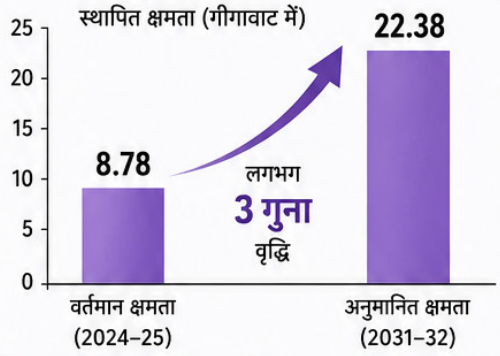
आने वाले वर्षों में भारत की परमाणु क्षमता लगभग **3 गुना** बढ़ने वाली है।



स्वदेशी **700 मेगावाट** (एमडब्ल्यू) रिएक्टर



अंतरराष्ट्रीय सहयोग से विकसित **1,000 मेगावाट** (एमडब्ल्यू) रिएक्टर



स्थापित क्षमता वर्ष 2031–32 तक **22.38 गीगावाट** (जीडब्ल्यू) तक पहुंचने का अनुमान है।

4. अंतराष्ट्रीय सहयोग

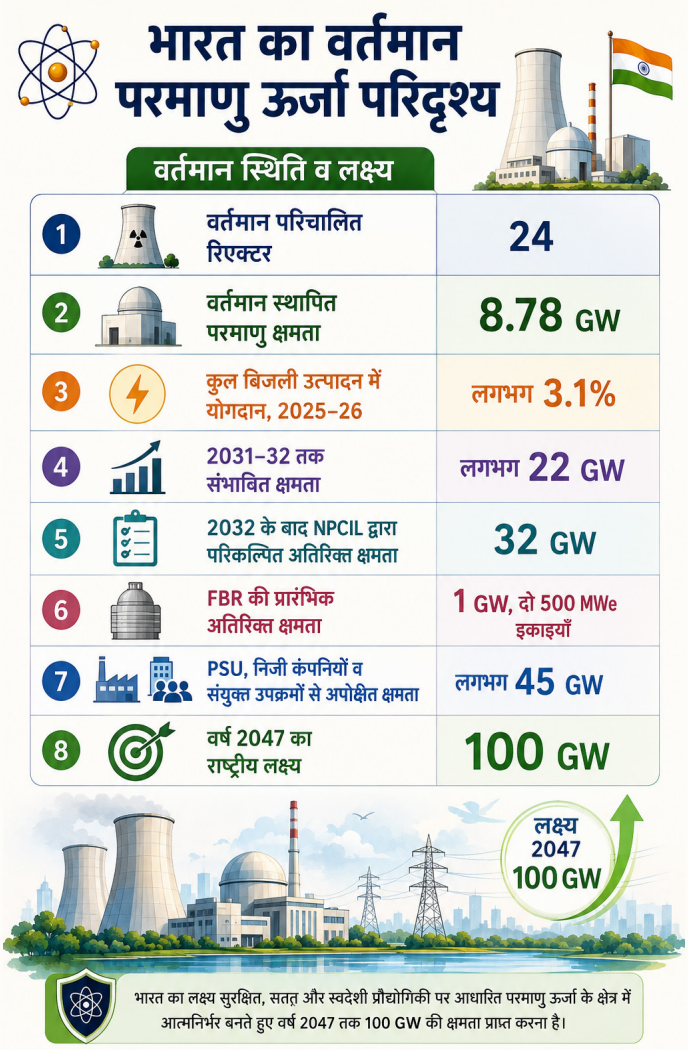
भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नागरिक परमाणु सहयोग पर **18 देशों** के साथ अंतर-सरकारी समझौतों (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।

भारत के साथ परमाणु सहयोग समझौता करने वाले देश (18)



परमाणु ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है, और आने वाला दशक भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई ऊँचाई पर ले जाएगा।

वर्तमान स्थिति व लक्ष्य :



परमाणु विस्तार की आवश्यकता :

1. **बढ़ती बिजली मांग :-** औद्योगीकरण, शहरीकरण, एयर-कंडीशनिंग इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर निर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन तथा डिजिटलीकरण के कारण भारत की बिजली मांग तेजी से बढ़ेगी। परमाणु ऊर्जा कोयले पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ाए बिना इस बढ़ती मांग के एक भाग की पूर्ति कर सकती है।

2. **24×7 निम्न-कार्बन बिजली :-** सौर और पवन ऊर्जा की उत्पादन-प्रकृति मौसम और समय पर निर्भर है। इसके विपरीत, परमाणु संयंत्र लंबी अवधि तक लगातार बिजली प्रदान कर सकते हैं, केवल नियोजित ईंधन-भराई और रखरखाव अवरोधों को छोड़कर।

3. **नेट-ज़ीरो एवं डीकार्बोनाइजेशन :**भारत ने 2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा जीवन-चक्र स्तर पर कम-कार्बन स्रोत है और इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन में किया जा सकता है:
   - विद्युत परिवहन और रेल।
   - इस्पात, उर्वरक तथा रसायन उद्योग।
   - भवनों का ताप एवं शीतलन।
   - विलवणीकरण।
   - कम-कार्बन हाइड्रोजन उत्पादन।
   - औद्योगिक प्रक्रिया-ऊष्मा।

4. **ऊर्जा सुरक्षा :** तेल और LNG के विपरीत, परमाणु ईंधन की ऊर्जा-घनता बहुत अधिक है। कम मात्रा में ईंधन से वर्षों तक बिजली उत्पादन संभव हो सकता है। इससे समुद्री मार्गों, युद्धों, प्रतिबंधों और अल्पकालिक आपूर्ति व्यवधानों के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

5. **कच्चे तेल की तुलना में परमाणु ऊर्जा :** कच्चे तेल की तुलना में यूरेनियम का भंडारण और ऊर्जा अधिक मात्रा में आशानी से प्राप्त की जा सकती है।

100 GW लक्ष्य की चुनौतियाँ :

1. **अभूतपूर्व विस्तार की चुनौती:** भारत को 2047 तक 8.78 GW से 100 GW तक पहुँचना है, अर्थात लगभग 91 GW से अधिक नई क्षमता जोड़नी होगी। इसके लिए भारत को अपनी ऐतिहासिक निर्माण और कमीशनिंग गति से कई गुना तेजी लानी होगी।

2. **लंबी परियोजना अवधि** :परमाणु परियोजनाओं में निम्न चरण समय लेते हैं:
   1. स्थल चयन और भूमि अधिग्रहण।
   2. पर्यावरणीय और नियामकीय स्वीकृति।
   3. डिजाइन, उपकरण निर्माण और निर्माण कार्य।
   4. सुरक्षा समीक्षा।
   5. ईंधन लोडिंग और फर्स्ट क्रिटिकलिटी।
   6. ग्रिड समकालिकरण।
   7. शक्ति-वृद्धि परीक्षण।
   8. वाणिज्यिक संचालन।

3. **वित्तपोषण और लागत वृद्धि :** 100 GW तक पहुंचने के लिए बहु-लाख-करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। परमाणु परियोजनाओं की समस्या यह है कि उनका आरंभिक पूंजी-व्यय बहुत अधिक होता है और विलंब होने पर ब्याज तथा निर्माण लागत तेजी से बढ़ती है।

   मुख्य जोखिम:- निर्माण में देरी, विदेशी उपकरण की आपूर्ति में बाधा, विनिमय दर जोखिम ,ठेकेदार क्षमता की कमी ,डिस्कॉम द्वारा महंगी बिजली के लिए दीर्घकालिक PPA करने में अनिच्छा, निजी निवेशकों के लिए अस्पष्ट दायित्व और नियामकीय जोखिम।

4. **आयातित यूरेनियम पर निर्भरता :** 100 GW के परमाणु बेड़े के लिए यूरेनियम की आवश्यकता काफी बढ़ेगी। भारत के पास कज़ाखस्तान, कनाडा, उज़्बेकिस्तान, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ आपूर्ति-सहयोग है, लेकिन कुछ आपूर्तिकर्ताओं पर अधिक निर्भरता जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

- **संभावित जोखिम: भू-राजनीतिक संघर्ष और प्रतिबंध।**
  - युद्ध या समुद्री मार्गों में व्यवधान।
  - परिवहन और बीमा की बाधाएँ।
  - भुगतान प्रणाली पर प्रतिबंध।
  - यूरेनियम रूपांतरण और संवर्द्धन क्षमता का वैश्विक संकेंद्रण।
  - रिएक्टर-विशिष्ट ईंधन-असेंबली की निर्भरता।
  - बाधाएँ:- कई क्षेत्रों में निम्न-ग्रेड अयस्क।
  - उच्च खनन और प्रसंस्करण लागत।
  - भूमि अधिग्रहण।
  - भूजल और पर्यावरणीय चिंताएँ।
  - खनन अपशिष्ट।
  - स्थानीय समुदायों का विरोध।

5. **विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता**
6. **रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन**

भारत के संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग

- भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक संवैधानिक, सांविधिक, गैर-सांविधिक, विनियामक एवं अर्द्ध-न्यायिक निकायों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये निकाय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत विधि द्वारा संचालित होते हैं और ये सभी निकाय लोकतंत्र के महत्त्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं।

निर्वाचन आयोग (Election Commission)

- चुनाव व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है जहाँ केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर चुनाव होते रहते हैं। 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान के माध्यम से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की रक्षा एवं संवर्द्धन हेतु निष्पक्ष व नियमित निर्वाचन करवाने हेतु एक स्वतंत्र एवं तटस्थ निर्वाचन आयोग की अत्यंत आवश्यकता होती है।
- निर्वाचन की दृष्टि से भारत ने अपने सभी वयस्क नागरिकों, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो और जो किसी विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण या अपराध के आधार पर अयोग्य घोषित न हो, को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार है।
- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अनुसार, मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। भारत में मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है।

  भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग-15 में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान करके एक संवैधानिक निकाय के रूप उपबंध किया है।

निर्वाचन आयोग की संरचना

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) में प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे। अर्थात् मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त आयुक्तों की संख्या भारत सरकार की इच्छा पर निर्भर है।
- वर्ष 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त (एकल सदस्यीय) था।
- वर्ष 1989 में इसे तीन सदस्यीय (1+2) बना दिया।
- वर्ष 1990 में पुनः एक सदस्यीय बना दिया।
- वर्ष 1993 में पुनः तीन सदस्यीय (1+2) निकाय बना दिया गया। (अर्थात् अब ये बहुसदस्यीय निकाय है)
- भारत के हृदयनाथ कुंजरू ने कहा है कि "निर्वाचन लोकतंत्र में एक पर्व है" निर्वाचन आयोग एक स्थायी, स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य के विधानमण्डल, राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनाओं से इस निर्वाचन अयोग का कोई संबंध नहीं है।

गठन:

- भारत में सर्वप्रथम 25 जनवरी, 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। (25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नाम	कार्यकाल
सुकुमार सेन	21 मार्च 1950-19 दिसंबर 1958
के. वी. के. सुंदरम	20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967
एस. पी. सेन वर्मा	01 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972
डॉ. नागेंद्र सिंह	01 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973
टी. स्वामीनाथन	07 फरवरी 1973 से 17 जून 1977
एस.एल. शकधर	18 जून 1977 से 17 जून 1982
आर. के. त्रिवेदी	18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985
आर. वी. एस. पेरिशास्त्री	01 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990
श्रीमती वी. एस. रमा देवी	26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990
टी. एन. शेषन	12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996
एम. एस. गिल	12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001
जे. एम. लिंगदोह	14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004
टी. एस. कृष्णमूर्ति	08 फरवरी 2004 से 15 मई 2005
बी. बी. टंडन	16 मई 2005 से 29 जून 2006
एन. गोपालस्वामी	30 जून 2006 से 20 अप्रैल 2009
नवीन चावला	21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010

एस. वाई. कुरैशी	30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012
वी. एस. संपत	11 जून 2012 से 15 जनवरी 2015
एच. एस. ब्रह्मा	16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015
डॉ. नसीम जैदी	19 अप्रैल 2015 से 05 जुलाई, 2017
श्री ए.के. जोति	06 जुलाई, 2017 से 22 जनवरी 2018
श्री ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी 2018 से 01 दिसंबर 2018
श्री सुनील अरोड़ा	02 दिसंबर 2018 से 12 अप्रेल 2021
सुशील चंदा	13 अप्रेल 2021 से 14 मई 2022
राजीव कुमार	15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025
ज्ञानेश कुमार	19 फरवरी, 2025 से अब तक

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बैठकों की अध्यक्षता करता है, निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है।
- **नियुक्ति :** राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
- **पद विमुक्ति :** राष्ट्रपति द्वारा उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जिस रीति व प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- (अन्य आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा।)
- **कार्यकाल/सेवा शर्तें :** संसद की विधि के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण
- 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की पदावधि जो भी पहले है। (पद ग्रहण की तारीख से) वह चाहे तो इससे पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है।
- **वेतन भत्ते :** निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व कार्य संचालन अधिनियम 1991 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान, वर्तमान में वेतन 2.5 लाख प्रतिमाह है।
- इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 में, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, पदावधि आदि का विस्तृत उल्लेख है।

कार्य व भूमिका (अधिकार)

- अनुच्छेद 324 (1) के अनुसार, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का तथा सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में होगा।
- विधायक/सांसद व राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन, इनके लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करना।
- **प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त :** राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्वाचन आयोग के कार्यों व शक्तियों का विस्तृत प्रावधान किया गया है, मुख्य कार्य निम्न हैं-

(1) निर्वाचन करवाना : राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सांसद व विधायकों का निर्वाचन करवाना।

(2) चुनाव तिथियों का निर्धारण : संविधान पीठ के अनुसार चुनाव करवाना, निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है तथा चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग है। न्यायालय के अनुसार सार्वजनिक अशांति चुनाव स्थगित करने की वजह हो सकती है, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने गुजरात में किया।

(3) निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन (अनुच्छेद 82 में निर्देश) : निर्वाचन आयोग का महत्त्वपूर्ण कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन या प्रादेशिक विभाजन होता है।

- संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात् राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन एवं राज्य में प्रादेशिक विभाजन प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।
- संसद ने परिसीमन अधिनियम 1952, 1962, 1972 एवं 2002 पारित किए। (2002 में जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन हुआ) मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। अब तक चार परिसीमन आयोग गठित हुए हैं।
- परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकार निकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

(4) मतदाता सूचियाँ तैयार करना : प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियाँ तैयार करवाई जाती हैं।

- संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है।
- संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार धर्म, मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के योग्य नहीं होगा।
- कोई योग्य व्यक्ति मताधिकार से वंचित न हो, इसलिए मतदाता सूचियाँ तैयार होती हैं।

S.I.R. - विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)

- भारत निर्वाचन आयोग का एक अभियान है जिसका उद्देश्य भारत की मतदाता सूचियों का सत्यापन और अद्यतन करना है ताकि सटीकता, समावेशिता और निष्पक्ष चुनावी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसका कानूनी आधार संविधान के अनु- 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधि नियम-1950 की धारा 21(3) में निहित है, जो आयोग को 'मतदाता सूची का विशेष संशोधन' करने की अनुमति देता है।
- 1951 से 2004 तक 8 बार S.I.R. हो चुका है। अंतिम S.I.R. वर्ष 2002-2004 में हुआ था। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं को जोड़ना, डुप्लीकेट प्रविष्टियों को ठीक करना, मृत, स्थानान्तरिक व्यक्तियों के नाम या फर्जी नाम हटाए जाते हैं।
- वर्ष 2025 में S.I.R. की शुरूआत बिहार से की गई है। (फेज प्रथम)
- **फेज द्वितीय** - 12 राज्य/संघ क्षेत्र
- **अनु.** 326- निर्वाचक की योग्यता :-
  - भारत का नागरिक
  - न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र हो
  - विधानसभा में सामान्य निवास
  - किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित न हो।

(5) राजनीतिक दलों को पंजीकरण व चुनाव चिह्न आवंटन- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राजनीतिक दलों के पंजीकरण का कार्य एवं उन्हें चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। दलों को राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करना।

(6) सांसद/विधायकों की अयोग्यता संबंधी परामर्श देना: सांसदों की अयोग्यता का विनिश्चिय राष्ट्रपति और विधायकों की अयोग्यता का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श (क्रमशः अनुच्छेद 103 व 192) से करता है।

(7) आदर्श चुनाव आचार संहिता का निर्माण व घोषणा - 1960 से आदर्श चुनाव आचार संहिता का प्रयोग किया जा रहा है। 1990 के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन.शेषन के समय से आचार संहिता का प्रभावी और महत्त्वपूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- **इसका मुख्य उद्देश्य-** सत्ताधारी दल चुनाव में सत्ता का लाभ प्राप्त न करे तथा चुनाव में सभी को समान अवसर प्रदान कराना।

आदर्श चुनाव आचार संहिता का आरम्भ आम चुनाव में 1971 में एवं राज्यों में 1960 में केरल विधानसभा से हुआ।

(8) मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना।

(9) उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में व्यय की राशि निश्चित करना।

(10) चुनाव याचिकाओं इत्यादि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता बनाए रखने वाले प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 324 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में प्रावधान किया गया है।
- **पदावधि** - राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत नहीं है बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी आधार और प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। जिन आधारों और प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया बेहद जटिल है। (उल्लेख न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968 में किया गया है।)
- **हटाने के आधार-** दुर्व्यवहार व अक्षमता (सिद्ध कदाचार व अक्षमता), प्रक्रिया- दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा ही हटा सकते हैं।
- अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता।
- नियुक्ति के पश्चात् सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

नियुक्ति संबंधित सुझाव

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023 के अनुसार नियुक्ति समिति की सिफारिश पर। जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री (मुख्य न्यायाधीश को हटाकर) तथा विपक्ष का नेता होगा।

नीति आयोग (NITI)
(National Institution for Transforming India, Aayog)

- राष्ट्रीय रूपान्तरण संस्था, जिसे, नीति आयोग भी कहा जाता हैं। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के संकल्प द्वारा (by Resolution), 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई।
- **प्रकृति** :- गैर-संवैधानिक सलाहकारी निकाय। नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक

संगठन

- **अध्यक्ष** :- प्रधानमंत्री
- **पूर्णकालिक संगठन** :- उपाध्यक्ष तथा सदस्य
- **उपाध्यक्ष:-** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति, केबिनेट मंत्री का दर्जा होगा
- **वर्तमान में उपाध्यक्ष-** अशोक कुमार लाहिड़ी, (नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष-अरविंद पनगड़िया)
- **नीति आयोग उपाध्यक्ष की सूची** :-
  1. अरविंद पनगढ़िया (2015 से 2017)
  2. राजीव कुमार (2017 से 2022)
  3. सुमन बेरी (2022 से अप्रैल, 2026 तक)
  4. अशोक कुमारी लाहिड़ी (मई, 2026 से)
- **सदस्य:-** पूर्णकालिक - राज्यमंत्री दर्जा (4 सदस्य), अंशकालिक- अधिकतम दो (विश्वविद्यालय, शोध संगठन से, चक्रानुक्रम)

- **पदेन सदस्य** - प्रधानमंत्री द्वारा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों में से नामित (अधिकतम 4)
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer)** CEO प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल हेतु सचिवालय की आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जाता है।

  वर्तमान में CEO : निधि छिब्बर
- **शासकीय परिषद (Governing Council) -** इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
- **क्षेत्रीय परिषदें :-** एक से अधिक राज्यों से गठन विशिष्ट मुद्दों के समाधान हेतु क्षेत्रीय परिषद् का गठन किया जायेगा। जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है।
- **विशिष्ट आमंत्रित सदस्य :-** विशेषज्ञ, अनुभवी संबंधित क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता एवं ज्ञान हों, इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।

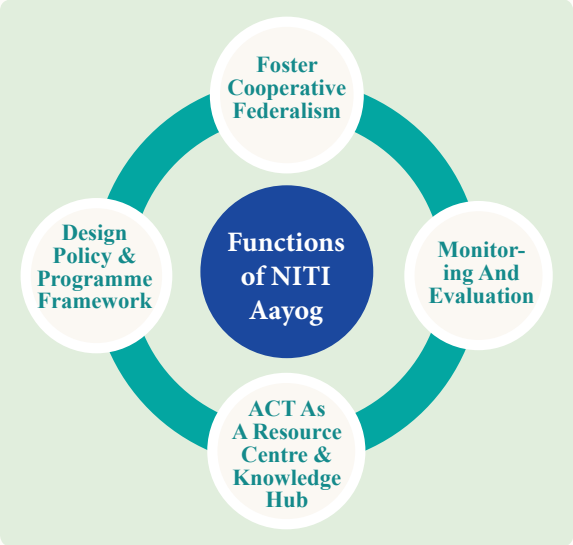
विशिष्ट प्रकोष्ठ (शाखा)

- **शोध शाखा :-** विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों का समूह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
- **परामर्शदात्री शाखा :-** जिन विषयों में परामर्श मांगा जाए, वहां परामर्श देना।
- **टीम इंडिया शाखा :-** इसमें प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकारिता के एक स्थाई मंच के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के मत को नीति आयोग में सतत् रूप से सुना जाए यह सुनिश्चित करता है।
- **सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) :-** आयोग सतत् विकास लक्ष्यों को सहकारी संघवाद के साथ प्राप्त करने और उसमें राज्य सरकारों की सहभागिता से आर्थिक नीतियाँ बनाने की प्रक्रिया निर्धारित करने की सलाह देना।

नीति आयोग के उद्देश्य

1. राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना।
2. सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
3. गाँव स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उतरोत्तर विकसित करना।
4. आर्थिक रणनीति व राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों से संबंधित क्षेत्रों को शामिल करना।
5. आर्थिक प्रगति से वंचित समाज के वर्गों पर ध्यान देना।
6. रणनीतिक और दीर्घकालीन नीति एवं कार्यक्रमों के नवाचारों को डिजाइन करना, प्रगति की निगरानी करना, सुधार के सुझाव देना।
7. प्रमुख हित धारकों और राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी की सलाह को प्रोत्साहित करना।
8. विकास के एजेंण्डे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अन्तरक्षेत्रीय और अन्तर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
9. अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना, सुशासन, टिकाऊ और सतत् विकास में सर्वोत्तम प्रणालियों के साथ-साथ हितधारकों को उनके प्रसार में मदद करने के लिए एक अनुसंधान भंडार है।
10. कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी विकास और उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना।

नीति आयोग के कार्य (Functions of NITI Aayog)



कृत्यों को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है :-

1. नीति डिजाइन करना व कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
2. सहकारी संघवाद के पालक के रूप में कार्य करना।
3. थिंक टैंक एंड नॉलेज हब के रूप में कार्य करना।
4. योजनओं की निगरानी करना व मूल्यांकन करना तथा सुझाव देना।

सहकारी संघवाद के विकास में नीति आयोग -

- आयोग की स्थापना के समय ही लक्ष्य के रूप में सहकारी संघवाद को रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने **'सहकारी संघवाद'** का नारा दिया। शासी परिषद की 11वीं बैठक (11 जून, 2026) को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । इस बैठक का मुख्य विषय 'विकसित भारत /2047 के लिए समावेशी मानव विकास' था ।
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में राज्यों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिया।

- केन्द्र राज्य साझेदारी मॉडल और कार्यक्रम स्थापित किए जैसे :- डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स (DSSS) और सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन केपिटल (SATH) प्रोग्राम जो राज्यों को तकनीकी सहयोग प्रदान करके उनके सामाजिक क्षेत्र के संकेतकों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए बनाया गया।
- आयोग की कार्यप्रणाली में संस्थागत रूप से निम्न माध्यमों से सहकारी संघवाद प्रत्यक्ष रूप से दिखता है :-
  1. आयोग की शासी परिषद् (16 फरवरी 2015 से प्रभाव में)
  2. विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्रियों का उपसमूह
  3. उत्तरी-पूर्वी राज्यों, द्वीप राज्यों व पहाड़ी - हिमालयी राज्यों को अपने विशिष्ट बाधाओं को पहचान करने के लिए विशेष मंचों का गठन करके, विशेष नीतियाँ बनाना।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)

- भ्रष्टाचार निवारण के सुझाव देने हेतु गठित की गई संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केन्द्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत् भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 11 सितम्बर, 2003 को मिली थी।
- वर्ष 2004 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को "सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले की सुरक्षा प्रस्ताव" के तहत सूचना देने वालों से भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों के किसी भी प्रकार के खुलासे या शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने हेतु अभिकरण बनाया गया उसे व्हीसल ब्लोअर (Whistle Blowers) के नाम से जाना जाता है।

संरचना (Structure)

- केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जो एक मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्तों से मिलकर बनेगा।
- वर्तमान में सीवीसी- श्री पी.के. श्रीवास्तव
- **नियुक्ति :** राष्ट्रपति द्वारा - (तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर - समिति में, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता)
- **कार्यकाल :** 4 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो,
- **शर्त:** कार्यकाल के बाद किसी के अधीन नियोजन का पात्र नहीं।
- **हटाने का तरीका :** केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी सतकर्ता आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में हटाये जा सकता है-
  - यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो।
  - कार्यक्षेत्र से बाहर सवेतनिक नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा होने पर।
  - शारीरिक मानसिक शैथिल्य के कारण अयोग्य हो।
  - सिद्ध दोष में कारावास तथा सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जाँच के आधार पर हटाया जा सकता है।

योग्यता :

- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे जिन्हें अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी लोक सेवा में या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर रह चुके हैं या हैं और उनके पास सतर्कता, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित विषय का ज्ञान और अनुभव है।
- **वेतन भत्ते, सेवा शर्तें -** केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन व भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान और अन्य आयुक्तों के वेतन और भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होते है।

कार्य (Function) :

(i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के निर्देश पर केन्द्र सरकार के कर्मचारी या प्राधिकरण के कर्मचारी के विरुद्ध जाँच करना।

(ii) अखिल भारतीय सेवा, ग्रुप-ए के कर्मचारियों, केन्द्र सरकार के प्राधिकरणों के अधिकारियों की जाँच करना, जिन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत् अपराध किया हो। इस अधिनियम से संबंधित CBI के कामकाज की देखरेख करना, जाँच से संबंधित निर्देश देना।

(iii) लोकहित का उद्घाटन व सूचना के संरक्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों की जाँच करना तथा कार्यवाही की अनुशंसा करना।

(iv) मनी लॉड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत् संदेहास्पद कार्यों व लेन-देन संबंधी सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार दिया गया है।

(v) लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों की जाँच करना।

(vi) केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को भ्रष्टाचार से सम्बन्धित किसी मामले में परामर्श देना।

(vii) केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन की निगरानी रखना।

(viii) निदेशक (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो), निदेशक (प्रवर्तन निदेशालय) और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक और इसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों की चयन समितियों की अध्यक्षता करना।

(ix) केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(x) जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जाँच करना या करवाना और उचित कार्यवाही की सिफारिश करना।

कार्यक्षेत्र: केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है-

(i) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो संघ सरकार से संबंधित अधिकारी हैं, और ग्रुप 'A' के अधिकारी।
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल-V से ऊपर के अधिकारी।
(iii) RBI, नाबार्ड एवं सिडबी के ग्रुप डी और इससे ऊपर के अधिकारी।
(iv) सरकारी क्षेत्र प्रक्रमों के बोर्डो के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी अधिकारी तथा अनुसूची क, ख और ई-7 व ऊपर के अन्य अधिकारी।
(v) साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक एवं ऊपर के अधिकारी।
(vi) भारतीय जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिवीजनल प्रबंधक एवं उससे ऊपर के अधिकारी।

- यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, और वह उस रिपोर्ट को संसद में रखता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

प्रमुख धाराएँ-

- **धारा**-3-केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन, जिसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अधिकतम 2 सदस्य सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यरत होंगे।
- **धारा**-4-इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी वारंट के द्वारा होगी।
- **धारा**-5- CVC तथा VC को 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान (पदावधि)
- **धारा**-6-साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाना।
- **धारा**-8-कार्य तथा शक्तियाँ प्रदत हैं।

केन्द्रीय सूचना आयोग
(Central Information Commission)

- सूचना का अधिकार का अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई।
- उल्लेखनीय है कि Right to Information (RTI) Act 2005, The Freedom of Information Act, 2002 के स्थान पर लागू हुआ।
- सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जो कि इस अधिकार को लागू करने वाला देश अपने नागरिकों को प्रदान करता है। RTI द्वारा राज्य अपने नागरिकों को, अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र को पारदर्शिता प्रदान करता है तथा जवाबदेही तय करता है।
- शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 में सरकार को यह अधिकार दिया कि वह किसी भी सूचना को गोपनीय रख सकती है। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू होने पर भी इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया।
- उत्तरप्रदेश सरकार बनाम राज नारायण वाद 1975 में उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 (a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के अन्तर्गत माना।

संरचना

- केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं।
- वर्तमान में राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त है।
- प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त - वजाहत हबीबुल्लाह थे।

नियुक्ति

- केंद्रीय सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर होती है।
- समिति में, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता (विपक्ष नहीं तो सबसे बड़े दल का नेता) एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक केबिनेट मंत्री होता है।

प्रमुख धाराएँ

- धारा-12 - केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन
- धारा-13 - सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवा शर्तें
- धारा-14-सूचना आयुक्तों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान
- धारा-20 - शास्ति (जुर्माना/दंड)
- धारा-18, 19 एवं 25 - केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है।

योग्यता

- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो, विधि विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए।
- विधायक और सांसद न हो, राजनीतिक दल से संबंधित न हो, लाभ के पद पर न हो।

कार्यकाल

- केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित या 65 वर्ष जो भी पहले हो। (5 वर्ष निर्धारित किया गया)

पद से पूर्व हटाना

- सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा (उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जाँच के उपरान्त)
- यदि वे दिवालिया हो गये हो
- कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो, यदि वह नैतिक कदाचार के संबंध में दोषी करार दिया हो।
- यदि वे शारीरिक मानसिक रूप से कर्त्तव्य निर्वहन में अक्षम हो, आदि आधार पर भी हटाया जा सकता है।
- **पुनर्नियुक्ति** : पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं (सदस्य - मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है किंतु दोनों कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं)

- **सेवा शर्तें/वेतन भत्ते :** मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन व भत्ते अन्य निर्वाचन सदस्यों के समान होते हैं उनमें सेवा काल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

क्षेत्राधिकार

- द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में क्षेत्राधिकार है।
- केन्द्र सरकार के अधीन एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, गठित, संचालित और नियंत्रित सभी संस्थान तथा केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रशासन, सभी मंत्रालय/विभाग, लोक उद्यम आदि।

मुख्य कार्य - शिकायतों की जाँच करना

ऐसे व्यक्तियों की शिकायत प्राप्त कर जाँच कर सकता है, जो-

(1) व्यक्ति को प्राप्त सूचना, अपूर्ण, भ्रामक एवं मिथ्या हो।
(2) समय सीमा के अन्तर्गत प्रत्युत्तर प्राप्त न करने वाले व्यक्ति।
(3) जानकारी प्राप्त नहीं कर पाने वाले व्यक्ति।
(4) लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण किसी सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहा हो।
(5) व्यक्ति से ऐसी फीस अदा करने की अपेक्षा की गयी हो जो अनुचित है या वह उसे अनुचित समझता है।
(6) अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच (Access) प्राप्त करने से संबंधित अन्य विषय।
(7) आयोग को यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रकरण में जाँच के लिए युक्तिसंगत आधार हैं तो वह उसके संबंध में जाँच आरंभ कर सकेगा।

- **शक्तियाँ -** कृत्य के निर्वहन में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- यथा- किसी व्यक्ति को हाजिर होने, लिखित या मौखिक गवाही लेने तथा शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेने।
- किसी दस्तावेज की तलाश करवाने और प्रस्तुत करवाने।
- अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख/प्रति प्राप्त करने, आदि की शक्तियाँ होंगी।

आयोग के निर्णय बाध्यकारी होंगे (Binding).

- द्वितीय अपील - 90 दिन में (90 दिन बाद भी स्वीकार कर सकता है)

निर्णय हेतु आयोग की शक्तियाँ

- लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय कराना जो इस अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हो :-

यथा- लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के लिए सार्वजनिक प्राधिकार को आदेश देना।

- कतिपय सूचना प्रकाशित करना।
- सूचना तक पहुँच उपलब्ध करवाना।
- RTI संबंधी प्रशिक्षण।
- RTI से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करवाना।
- नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करना।
- शक्ति अधिरोपित करना।
- आवेदन को अस्वीकृत करना।

शक्तियाँ (Powers)

- आयोग की राय में यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिना उचित कारण के आवेदन लेने से इंकार किया गया हो, निर्धारित समय में सूचना नहीं दी गई हो या असद्भावना पूर्वक सूचना का आवेदन लेने से इंकार किया हो, जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी गई है या ऐसी सूचना नष्ट कर दी है, जो आवेदन से संबंधित थी, सूचना देने की प्रक्रिया में बाधा डाली है तो, आवेदन प्राप्ति या सूचना देने के दिन से 250 रूपये प्रतिदिन की शक्ति (अधिकतम 25000/-) अधिरोपित की जा सकती है।

भारत के मुख्य सूचना आयुक्त

नाम	कार्यकाल
वजाहत हबीबुल्लाह	26 अक्टूबर 2005-19 सितम्बर 2010
ए.एन. तिवारी	30 सितम्बर 2010-18 दिसम्बर 2010
सत्यानंद मिश्र	19 दिसम्बर 2010-4 सितम्बर 2013
दीपक संधू	5 सितम्बर 2013-18 दिसम्बर 2013
सुषमा सिंह	19 दिसम्बर 2013-21 मई 2014
राजीव माथुर	22 मई 2014 - 22 अगस्त 2014
विजय शर्मा	10 जून 2015 - 1 दिसम्बर 2015
राधा कृष्ण माथुर	4 जनवरी 2016 - 24 नवम्बर 2018
सुधीर भार्गव	1 जनवरी 2019 - 11 जनवरी 2020
विमल जुल्का	19 फरवरी 2020-31 अक्टूबर 2020
यशवर्धन कुमार सिन्हा	7 नवम्बर 2020-3 अक्टूबर 2023
हीरालाल सामरिया	5 नवम्बर 2023 से सितंबर 2025
राजकुमार गोयल	15 दिसंबर 2025 से वर्तमान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Right Commission)

- मानवाधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। मानवधिकारों के संरक्षक के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 के अन्तर्गत हुई जो कि राष्ट्रपति द्वारा 28 सितम्बर 1993 को जारी हुई। यह अध्यादेश ही मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना। जिसे 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतो के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अन्तरराष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया था तथा 20 दिसम्बर 1993 को UN महासभा द्वारा संकल्प 48/134 रूप में समर्थित किया गया था।

आयोग की स्थापना

- राष्ट्रीय मानवीय आयोग एक सांविधिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993ए 2006 तथा 2019 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है।

आयोग की संरचना

- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अनुसार, आयोग की संरचना है -(2019 के संशोधन के अनुसार)

(क) एक अध्यक्ष जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो;

(ख) एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो;

(ग) एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो:

(घ) तीन सदस्य (जिनमें से कम से कम एक महिला होगी) मानव अधिकारो से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएँगे।

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और दिव्यांगजन आयोग के अध्यक्ष धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य माने जाएँगे।
- एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
- 1993 और 2019 के अधिनियमों के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

विशेषता	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993	संशोधन अधिनियम, 2019
अध्यक्ष की योग्यता	NHRC के अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकते थे।	सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अध्यक्ष हो सकते हैं।
सदस्यों की संख्या	आयोग में मानवाधिकारों का ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो सदस्य होते थे।	ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पाँच कर दी गई है, जिनमें से एक महिला होना अनिवार्य है।
पदेन सदस्य	इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते थे।	उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के अध्यक्षों को भी पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है

- **अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति :** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है।

चयन समिति के 6 सदस्य :-

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- लोकसभा अध्यक्ष
- राज्य सभा उप-सभापति
- लोक सभा में विपक्षी दल का नेता एवं राज्यसभा का विपक्षी दल का नेता
- संघ का गृहमंत्री
- **त्यागपत्र या हटाया जाना :-** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा पद त्याग सकता है।
- **हटाने के आधार :-** सिद्ध कदाचार या असमर्थता, उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जाँच के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाएगा तथा दिवालिया घोषित किया जाता हो, कर्त्तव्यों के बाहर सवेतन नियोजन में हो, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अयोग्य हो, विकृतचित घोषित हो (सक्षम न्यायालय द्वारा) अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया हो, कारावास से दण्डित किया हो, जिससे राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता हो।
- **कार्यवाहक :-** पद रिक्ति/अनुपस्थिति आदि पर सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक नियुक्त।
- **पदावधि :-** पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
- **पुनर्नियुक्ति :-** पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।
- **अन्य नियोजन :-** अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहने पर राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।
- **प्रक्रिया:-** स्वयं आयोग तय करेगा समय व स्थान आदि।

आयोग के कार्य

1. स्वप्रेरणा से या प्रार्थना किए जाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने या उल्लंघन के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत के बारे में जाँच करना।
2. किसी लंम्बित कार्यवाही में न्यायालय के अनुमोदन से मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जाँच करना।
3. जेल, सुधारगृह में वहाँ के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना।
4. संविधान या अन्य विधियों में मानवाधिकारों के रक्षोपायों का पुनरवलोकन करना और प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की सिफारिश करना।
5. ऐसे कारकों, जिनके अन्तर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और मानवाधिकारों के उपयोग में विघ्न डालते हैं, का पुनरवलोकन करना, समुचित उपायों की सिफारिशें करना।
6. मानवाधिकारों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन करना, क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना।
7. मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी का प्रसार करना।
8. मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत NGO व संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
9. कृत्य जो मानवाधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझें।

शक्तियाँ :- (प्रकृति अर्द्ध न्यायिक)

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ धारण करता है, यथा किसी व्यक्ति को हाजिर होने, समन जारी करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, गवाही देने के निर्देश दे सकता है।
- लोक अभिलेख की प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा।
- बयान दर्ज कर सकेगा/शपथ पत्र
- भारतीय दण्ड संहिता/दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

आयोग की कार्यप्रणाली

- आयोग का प्रधान कार्यकाल दिल्ली में स्थित है तथा वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है।
- आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं तथा इसका चरित्र भी न्यायिक है। आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी या रिपोर्ट की मांग कर सकता है।
- आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकारों की किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है।
- आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए एक वर्ष से अधिक हो गया हो।

आयोग जांच के दौरान निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है:

1. यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
2. यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है।
3. यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
4. आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रमुख धाराएँ (अध्याय-2 में)

धारा-3 - राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन।
धारा-4 - अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति।
धारा-5 - अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना।
धारा-6 - अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।
धारा-30- मानवाधिकार न्यायालय।

- **आयोग की भूमिका :-** मुख्यत: सलाहकारी है, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को आयोग द्वारा दण्डित नहीं किया जा सकता। सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती।
- सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की भूमिका और शक्तियाँ सीमित हैं। आयोग केन्द्र से रिपोर्ट प्राप्त कर सलाह दे सकता हैं, जाँच नहीं कर सकता है। आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के संदर्भ में तीन माह में सरकार आयोग को अवगत करवाएगी।

आयोग का कार्य निष्पादन

मानवाधिकार से संबंधित अनेक विषय हैं उनमें से आयोग के पास निम्नलिखित हैं:

1. मातृत्व रक्ताल्पता तथा मानवाधिकार।
2. बंधुआ मजदूरी की समाप्ति।
3. यौन तस्करी एवं अवैध व्यापार पर रोक के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम।
4. राँची, आगरा और ग्वालियर में मानसिक अस्पतालों का संचालन।
5. महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार: लैंगिक संवेदीकरण के लिए न्यायपालिका के लिए नियम पुस्तक।
6. आगरा स्थित सरकारी सुरक्षा गृह (महिला) का संचालन।
7. बाल श्रम की समाप्ति।
8. भोजन का अधिकार से संबंधित मुद्दे।
9. वृंदावन परित्यक्त महिलाओं का पुनर्वास।
10. बाल विवाह रोक अधिनियम, 1929 की समीक्षा।

11. बाल अधिकार पर अभिसमय से संबंधित प्रोटोकॉल।
12. सरकारी सेवकों द्वारा बच्चों को रोजगार में जाने से रोकना; सेवा नियमावली में संशोधन।
13. बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए मार्गदर्शिका।
14. अनधिसूचित तथा घुमंतू जनजातियों की समस्याएँ।
15. स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले।
16. कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न को रोकना।
17. रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों का उत्पीड़न।
18. हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का अंत।
19. गुजरात भूकम्प 2001 के बाद राहत उपायों का अनुश्रवण।
20. दलितों से संबंधित मामले उन पर किए जाने वाले अत्याचार सहित।
21. हिरासत में मौत, बलात्कार तथा यंत्रणा को रोकने के लिए उठाए गए कदम।
22. जिला परिवाद प्राधिकार।
23. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार।
24. मानवाधिकार संबंधी कानूनों की समीक्षा, संधियों का कार्यान्वयन तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों की समीक्षा।
25. एच.आई.वी./एड्स संक्रमित व्यक्तियों के अधिकार।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा	1993-1996
न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचैलेया	1996-1999
न्यायमूर्ति जे.एस.वर्मा	1999-2003
न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद	2003-2006
न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू	2007-2009
न्यायमूर्ति के.जी.बालाकृष्णन	2010-2015
न्यायमूर्ति एच.एल. दतू	2016-2020
न्यायमूर्ति ए.के. मिश्रा	2.6.2021 से 2024
न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन	दिसंबर, 2024 से अब तक

राष्ट्रीय महिला आयोग

- राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में की गई।

इसके मुख्यतः तीन उद्देश्य थे-

(1) महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।

(2) उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना ।

(3) शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना और महिलाओ को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

- प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था, हालांकि इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 30 अगस्त 1990 को मिली थी।

आयोग की संरचना

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का प्रावधान हैं। जिसमें -

1. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कार्यों का पालन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी

2. **आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगें-**

(अ) महिलाओं के हित में प्रतिबद्ध एक अध्यक्ष, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(ब) पाँच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित किए जाएंगे जिन्हे कानून या विधान, ट्रेड यूनियनवाद, महिलाओ की उद्योग क्षमता के प्रबंधन, महिला स्वेच्छिक संगठनों प्रशासन आर्थिक विकास स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण में अनुभव हो।

(स) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एक सदस्य सचिव जो निमन्वत होगा। (1) प्रबंधन, संगठनात्मक सरंचना या समाजशास्त्रीय आंदोलन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ या (2) ऐसा अधिकारी जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो।

- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना ' भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (CSWI) तथा 'मि. हलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988-2000) की सिफारिशों के फलस्वरूप की गई थी।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के अध्यक्ष या सदस्य सभी का कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)
- वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करती है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त है।
- यह अर्ध न्यायिक संस्था है। लेकिन प्रवर्तन सम्वन्धी सीमित शक्तियों के कारण इसे 'टूथलेस टाइगर ' कहा जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष

- सुश्री जयंती पटनायक – 03.02.1992–30.01.1995
- डॉ..वी.मोहनी गिरी – 21.07.1995–20.07.1998
- विभा पार्थसारथी – 18.01.1999–17.01.2002
- डॉ. पूर्णिमा आडवाणी – 25.01.2002–24.01.2005
- डॉ.गिरिजा व्यास – 16.02.2005–15.02.2008
  09.04.2008–08.04.2011
- ममता शर्मा – 02.08.2011–01.08.2014
- ललिता कुमारमंगलम – 29.09.2014–28.09.2017
- रेखा शर्मा (कार्यवाहक) – 29.09.2017–06.08.2017
- रेखा शर्मा – 07.08.2018–06.08.2021
  07.08.2021–06.08.2024
- श्रीमती विजया के.रहाटकर–22.10.2024– वर्तमान तक

नोट :

1. **आयोग के पहले सदस्य सचिव सचिव** – उमा पिल्लई
2. **आयोग के पहले दो सदस्य**– मोनिका दास और बनोज सेनापति थे।
3. शिकायत संबंधी प्रश्नों के लिए 24X7NCW महिला हेल्पलाइन नंबर 14490 हैं।
4. NCW ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और दहेज प्रतिषेध अधि नियम 1961 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधि नियम 2013 जैसे महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन को मजबूत करने में मदद की है।

- राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष, भारत में महिलाओं के अधिकारो से वंचित करने या महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कोई भी व्यक्ति मामला दर्ज करवा सकता है। शिकायत में मामले का पूरा विवरण होना चाहिए ।
- राष्ट्रीय महिला आयोग विभन्न श्रेणी की शिकायतों पर विचार करता है। जैसे-अपहरण, एसिड प्रहार, गर्भपात का कारण, आपराधिक धमकी, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, महिलाओं को मातृत्व लाभ से वंचित करना, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, लिंग भेदभाव, महिलाओं के साथ छेड़-छाड़, बहु विवाह, तीन तलाक, बलात्कार, महिलाआ. ं के प्रति पुलिस की उदासीनता, विवाह में चुनाव करने का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, महिलाओं से जबरन वेश्यावृति करवाना, महिलाओ का अमानवीयकरण और कलंक, महिलाओं के लिए निशुल्क कानूनी सहायता हेतु अनुरोध और इज्जत के लिए प्यार करने वालों की हत्या करना आदि।
- इस प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग नीतिगत समर्थन , शिकायत निवारण और संस्थागत सुधारों के माध्यम से लैंगिक न्याय सु. निश्चित करने वाली एक शीर्ष निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) भारत सरकार के मं. हला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 5 मार्च 2007 में बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। यह इस अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित किया गया है।
- यह आयोग 0–18 वर्ष की आयु के बच्चों के अधिकारों की रक्षा, शिक्षा, और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे POCSO अधिनियम का कार्यान्वयन भी शामिल है।
- आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकारों के प्रावधानों के साथ साथ सयुक्त राष्ट्र कन्वेंसन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हों।
- NCPCR **का लोगो/आदर्श वाक्य**– भविष्यों रक्षति रक्षित: है।
- इस आयोग की स्थापना न्यायमूर्ति वी.आर कृष्णा अय्यर समिति की मसौदा रिपोर्ट के आधार पर की गई थी।
- NCPR **अधिनियम की धारा** – 4 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान हैं तथा धारा –7 में पद से निष्कासन का प्रावधान हैं धारा –8 में अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद त्याग का उल्लेख है।
- NCPR अधिनियम 2005 की धारा 13 के तहत निर्धारित कार्यों में एक में, आयोग को बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करने और उनके प्रभावी कार्यन्वयन के उपयों की जांच और समीक्षा करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौपा गया है।
- आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं।
- मुख्यत: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल अधि कारों के संरक्षण और समवर्धन के लिए कार्य करने का दायित्व सौपा गया है। आयोग शिकायतों की जांच कर सकता है और निम्नलिखित मामलों का स्वत: संज्ञान ले सकता है–
  (1) बाल अधिकार का हनन और उल्लंघन
  (2) बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन ना होना।
  (3) बच्चों की कठिनाइयों को कम करने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने तथा ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए नीतिगत निर्णयों, दिशा-निर्देशों का अनुपालन ना करना या
  (4) ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को उचित अधिकारियों के समक्ष उठाए।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बाल संरक्षण अधि

नियम (POCSO) 2012 और किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 जैसे विभिन्न बाल केंद्रित अधिनियम बनाए हैं। किशोर न्याय अधिनियम-2015 के अंतर्गत किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 भी बनाए गए हैं। 2021 में किशोर न्याय संशोधन अधि नियम भी आया ।

- यह NCPCR लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बच्चों की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है।
- इस आयोग मे एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिनमें से कम से कम दो महिलाये होनी चाहिए ।
- इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा तीन साल के लिए की जाती है, आयोग में सेवा करने की अधिकतम आयु अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 60 वर्ष है।
- इस आयोग का अध्यक्ष, जो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जिन्होंने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया हो।
- निम्नलिखित क्षेत्रों से 6 सदस्य (जिनमें से कम से कम दो महिलाये हो) जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जायगी।
  (1) शिक्षा
  (2) बाल स्वास्थ्य, देखभाल कल्याण और विकास
  (3) किशोर न्याय अथवा वंचित अथवा दिव्यांग बच्चों की देखभाल
  (4) बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन
  (5)बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान में ख्याति प्राप्त
  (6) बच्चों से संबंधित कानून में अनुभवशील व्यक्ति ।
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु गठित तीन सदस्यीय चयन समिति होगी जिसका अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग का मंत्री होगी।
- **इस आयोग के मुख्यतः तीन उद्देश्य हैं-**
  (1) बच्चों के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
  (2) यह सुनिश्चित करना कि सभी कानून, नीतीयां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र संवैधानिक रूप से और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संहिता के तहत बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हो।
  (3) बाल अधिकारों के उल्लघंन से संबंधित शिकायतों के निवारण में सहायता प्रदान करना।
  - वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को ।
  - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष- वलेटी प्रेमचंद ।
- **NCPCR अब तक के अध्यक्ष-**
  1. शांता सिन्हा
  2. श्रीमती कुशल सिंह
  3. श्रीमती स्तुति नारायण कक्कड़
  4. प्रियांक कानूनगो
  5. सुश्री तृप्ति गुरहा
  6. वलेटी प्रेमचंद (दिसंबर 2025 से निरंतर)

नोट

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अशीम श्रीवास्तव
- NCPCR की प्रमुख पहले – घर (GHAR) पोर्टल ,बाल स्वराज और सहारा (SAHARA) है।
- आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के साथ मिलकर काम करता है।
- इस आयोग के प्रथम सदस्य सचिव शालिनी प्रसाद थे।

लोकपाल (Lokpal)

- ओम्बुड्समैन का भारतीय रूप लोकपाल है।
- स्वीडिश शब्द ''ओम्बुड'' (किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला) से ओम्बुड्समैन बना है, जिसका तात्पर्य उस संस्था से है जो कुप्रशासन से नागरिकों की रक्षा करती है।
- विश्व में स्केण्डिनेवियन देशों में ओम्बुड्समैन का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले 1809 में स्वीडन, 1919-फिनलैण्ड, 1955-डेनमार्क, 1962 में नॉर्वे में स्थापना हुई। इनके अतिरिक्त न्यूजीलैण्ड (1962) ब्रिटेन (1967), कनाडा व अमेरिका में यह कार्यरत है। ब्रिटेन में इसे संसदीय आयुक्त प्रणाली कहा जाता है।
- यह एक निष्पक्ष व कार्यकुशल संस्था मानी जाती है। जो किसी मुद्दे की जाँच कर सरकार को कार्यवाही की अनुशंसा करती है।
- गेराल्ड ई. केडन ने कहा है कि ''ओम्बुड्समैन संस्था जनता के अन्त:करण का संस्थागत स्वरूप है।''

भारत में लोकपाल अध्यक्ष

- 23 मार्च, 2019 से 27 मई, 2022 तक- **पिनाकी चन्द्र घोष** (प्रथम लोकपाल)
- वर्तमान में लोकपाल-**अजय माणिकराव खानविलकर**

लोकपाल की पृष्ठभूमि

- भारत में सर्वप्रथम 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (हरीशचन्द्र माथुर) ने यह सुझाव दिया था कि भारत में भी ओम्बुड्समैन जैसी संस्था होनी चाहिए।

- एल.एम. सिंघवी ने यह मांग संसद में उठाई व लोकपाल देने की मांग की।
- 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग-I ने केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की सिफारिश की

आयोग की सिफारिश पर :-

I. संसद में लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम 9 मई 1968 को प्रस्तुत किया, लोकसभा में पारित, राज्यसभा में अपारित, (लोकसभा भंग) (इसमें राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को बाहर रखा था।)

II. वर्ष 1971 में पुन: लोकसभा में प्रस्तुत (लोकसभा भंग के कारण बिल लेप्स)

III. वर्ष 1977- लोकपाल विधेयक (प्रधानमंत्री क्षेत्राधिकार में) पेश, पारित नहीं

IV. अगस्त 1985 में पुन: पेश (प्रधानमंत्री को बाहर रखा) - वापिस ले लिया (राजीव गांधी सरकार)

V. वर्ष 1989 में वी.पी सिंह सरकार ने संसद में पेश किया (प्रधानमंत्री क्षेत्राधिकार में)

VI. वर्ष 1996 - संयुक्त मोर्चा सरकार ने पेश किया।

VII. वर्ष 1998 वाजपेयी सरकार ने पेश किया

VIII. वर्ष 2001 में पुन: पेश, लेकिन पारित नहीं

इस प्रकार यह आठ बार पेश हुआ लेकिन पारित नहीं हुआ।

- राष्ट्रपति अब्दुल कलाम (2004) ने अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'लोकपाल संस्था की शीघ्र स्थापना हो तथा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री इसके दायरे में हों।
- अप्रैल 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, अन्ना ने आमरण अनशन किया, तब सरकार ने गंभीरता दिखाई तथा प्रणब मुखर्जी (तत्कालीन वित्त मंत्री) की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया।
- सिविल सोसायटी की ओर से 'जन लोकपाल' नाम से एक ड्राफ्ट बनाया था। इसे प्रारूप समिति को सौंपा गया। (प्रारूप समिति ने सरकार की ओर से -प्रणब मुखर्जी, पी. चिदम्बरम, वीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल तथा सलमान खुर्शीद थे।)
- (सिविल सोसाइटी की ओर से - अन्ना हजारे, संतोष हेगडे, शांतिभूषण, प्रशांत भूषण तथा अरविंद केजरीवाल सदस्य थे।)
- 4 अगस्त 2011 को नौवीं बार लोकपाल विधेयक संसद में पारित किया गया था।
- 01 जनवरी 2014 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ अधिसूचित हुआ।
- 16 जनवरी, 2014 से यह प्रभावी हुआ।
- 19 मार्च, 2019 को इसका गठन हुआ।

उद्देश्य

- यह कानून सरकारी कार्मिकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच हेतु संघ के मामले में लोकपाल तथा राज्यों हेतु लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना हेतु लाया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार विरोधी कन्वेंशन को अपना चुका है, अत: भ्रष्टाचार प्रकरणों में तुरंत एवं निष्पक्ष जाँच तथा अभियोजन हेतु प्रभावी कानून आवश्यक हैं।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की प्रमुख बातें

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं-

(i) केंद्र में लोकपाल राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना होगी। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और A, B, C और D श्रेणी के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होंगे।

(ii) लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। सदस्यों में 50 प्रतिशत सदस्य न्यायिक सेवा के होंगे। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और स्त्रियों में से होंगे।

(iii) अध्यक्ष व सदस्यों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(iv) इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- लोकसभा में विपक्ष का नेता
- भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश
- कोई प्रतिष्ठित न्यायविद् जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के चार सदस्यों की अनुशंसा पर नामित हो।

(v) एक सर्च समिति, चयन समिति की मदद करेगी सदस्यों के चयन में सर्च समिति के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा स्त्रियों के वर्ग से आते हैं।

(vi) प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है लेकिन बहुत सारे विषयों में वे लोकपाल से बाहर हैं। उनके खिलाफ आरोप के निपटारे के लिए विशेष प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

(vii) इसके अंतर्गत वे प्रावधान शामिल हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई संपत्ति को जप्त करेंगे तब भी जबकि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो।

(viii) लोकपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकार या किसी समर्थ अधिकारी की जगह खुद सरकारी कर्मचारियों के अभियोजन की अनुमति दे।

(ix) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से लेकर 365 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधायिका द्वारा कानून पारित कर लोकायुक्त गठित करने का अधिकार प्राप्त है।

(x) यह ऐसे कोई प्रावधानों से युक्त है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सशक्त बनाते हैं:-

(a) एक अभियोजन निदेशक मंडल का गठन जिसके शीर्ष पर अभियोजन निदेशक हों और सब केंद्रीय पाँच ब्यूरो के पूर्ण नियंत्रण में हो।

(b) केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा पर अभियोजन निदेशक की नियुक्ति।

(c) सरकारी वकीलों से इतर अन्य वकीलों का पैनल बनाएँ जो लोकपाल की सहमति से लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जाँच करी।

(d) लोकपाल के अनुमोदन से लोकपाल द्वारा भेजे केस की जाँच करने वाले केंद्रीय जाँच ब्यूरो के अधिकारियों का स्थानांतरण।

(e) लोकपाल द्वारा प्रेषित केसों की जाँच के लिए आयोग को पर्याप्त राशि (फंड) की व्यवस्था।

लोकपाल का संगठन

- लोकपाल संस्था का अध्यक्ष या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा और प्रकाण्ड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिये, उसके पास भष्ट्राचार निरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, बैकिंग, बीमा, और कानून प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षो का विशिष्ट ज्ञान व अनुभव हो।
- लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य नहीं हो।
- लाभ का पद न धारण किया हो।

नियुक्ति-

- सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी।
- चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा उसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और प्रसिद्ध न्यायविद् से मिलकर गठित होती है।
- लोकपाल और सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम-से-कम 8 व्यक्तियों का एक पैनल गठित करती है। इसे खोजबीन समिति के नाम से जाना जाता है।

लोकपाल खोजबीन समिति

- लोकपाल अधिनियम 2013 के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग उन सभी की सूची बनाता है जो लोकपाल संस्था का अध्यक्ष या सदस्य बनने का इच्छुक हो।
- इसके पश्चात् यह सूची उस प्रस्तावित 8 सदस्यीय खोजबीन समिति के पास जायेगी जो नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी एवं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के सामने प्रस्तुत करेगी।
- खोजबीन समिति के द्वारा सुझाये गये नामों को चयन समिति चुन सकती है या नहीं भी चुन सकती है।
- राष्ट्रपति, अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल पूरा होने से तीन माह पूर्व नई नियुक्ति की कार्यवाही करवाएँ।

कार्यकाल-

- पाँच वर्ष या 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो
- संघ व राज्य के अधीन लाभ के पद पर नहीं
- पदमुक्ति- त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित

कदाचार-

- इनसे संबंधित कदाचार की शिकायत को संसद के न्यूनतम 100 सदस्य राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित याचिका देंगे। जिसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को भेजेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच में कदाचार प्रमाणित होने पर राष्ट्रपति आरोपी को हटा सकेंगे।
- जाँचाधीन होने के दौरान राष्ट्रपति आरोपी को निलम्बित रख सकेंगे।

वेतन, भत्ते और पेंशन

- लोकपाल के वेतन, भत्ते और पेंशन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान होते हैं।

लोकपाल का क्षेत्राधिकार

- लोकपाल के क्षेत्राधिकार में निम्नांकित के विरूद्ध शिकायतें सम्मिलित हैं-

(1) प्रधानमंत्री (वर्तमान प्रधानमंत्री है या भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहा हो)
  - प्रधानमंत्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष से संबंधित मामले लोकपाल के दायरे से बाहर होंगे।
  - प्रधानमंत्री के विरूद्ध जाँच होने या न होने का निर्णय, अध्यक्ष सहित पूर्ण पीठ के 2/3 बहुमत से किया जाएगा।
  - जाँच को कैमरे में दर्ज किया जायेगा।
  - यदि शिकायत को निरस्त किया जाना है तो यह रिकॉर्ड किसी को भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

(2) संघ के वर्तमान या पूर्व मंत्री, संसद सदस्य (पूर्व/वर्तमान)

(3) संघ के मामलों से जुडे समूह A, B, C और D के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी सम्मिलित होते हैं।

(4) संसदीय कानून से गठित या केन्द्र द्वारा वित्त पोषित नियंत्रित निकाय बोर्ड, प्राधिकरण, निगम, कंपनी सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्तशासी निकाय के कार्यरत पूर्व अध्यक्ष, सदस्य अधिकारी, कार्मिक।

- ऐसे प्रकरणों में कोई व्यक्ति, राज्य सरकार से संबंधित हो तो राज्य सरकार की अनुमति ली जाएगी।
- किसी भी संगठन, संघ ट्रस्ट समिति के कार्यरत/पूर्व निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य कार्मिक जो विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियमन, 2010 के अन्तर्गत विदेशी स्रोतों से दस लाख रू अधिक राशि का अंशदान प्राप्त करते हैं।

- किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध उन कृत्यों या आचरण की जाँच करेगा जो रिश्वत लेने या देने या उकसाने या ऐसा षड्यंत्र करने या भ्रष्टाचार से किसी भी तरह संबंधित होगा।
- **अपवाद-** अनुच्छेद 105 संसद सदस्य द्वारा सदन में कही गई बात के संबंध में किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप की जांच नहीं करेगा।

नोट-लोकपाल को की गई शिकायत की जाँच, "जाँच आयोग अधिनियम 1952" (Commission for Inquiry Act. 1952) के अन्तर्गत नहीं की जाएगी।

शक्तियाँ या कृत्य

(1) वे मामले लोकपाल द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (C.B.I.) को भेजे जाएंगे, उनकी निगरानी या निर्देशन लोकपाल करेगा। तथा उन मामलों में CBI द्वारा लोकपाल की अनुमति के बिना जाँच अधिकारी नहीं बदला जाएगा। तथा अधिवक्ताओं का पैनल लोकपाल की सहमति से तैयार होगा। इन प्रकरणों के व्यय की पूर्ति केन्द्र सरकार CBI को करेगी।

(2) लोकपाल की राय में किसी प्रकरण से संबंधित दस्तावेज छिपाए गए हैं तो वह किसी अभिकरण (C.B.I सहित) को उनकी खोज तथा जब्त करने को प्राधिकृत कर सकेगा। जब्त दस्तावेजों को वह स्वयं या जाँच अधिकारी की अभिरक्षा में रख सकेगा या प्रतिलिपि रख सकेगा।

(3) प्रारंभिक जाँच के प्रयोजन हेतु लोकपाल किसी भी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी, संगठन या जाँच अभिकरण की सेवाएँ ले सकेगा। तथा निर्धारित अवधि में रिपोर्ट माँग सकेगा।

(4) लोकपाल या अधिकृत अधिकारी की राय में आरोपी व्यक्ति की सम्पत्ति भ्रष्ट तरीके से संबंधित है तो वह प्रथमत: 90 दिनों के लिए सम्बद्ध (Attach) कर ली जाएगी, आगे की अवधि विशेष कोर्ट निर्धारित करेगा।

(5) यदि लोक सेवक दोषमुक्त घोषित होता है तो सम्बद्ध सम्पति संभावित देय लाभों के साथ वापिस की जाएगी।

(6) यदि लोक सेवक 'भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988' के अन्तर्गत दोषी करार दिया जाता है तो उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाएगी तथा केन्द्र सरकार के अधीन रहेगी।

(7) प्रथम दृष्टया लोकसेवक भ्रष्टाचार में लिप्त लगे तो उस कार्मिक के स्थानान्तरण या निलम्बन की सिफारिश (अवधि सहित) केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी। केन्द्र सरकार यह सिफारिशें स्वीकार करेगी किंतु प्रशासनिक कारणों से यह संभव न हो तो इसका लिखित में कारण बताएगी।

विशेष न्यायालय

- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रकरण निस्तारित करने के लिए केन्द्र सरकार लोकपाल की सिफारिशानुसार विशेष कोर्ट गठित करेगी।

कार्यप्रणाली-

- क्षेत्राधिकार बैंचों के माध्यम से होगा, दिल्ली में बैठेगी, चाहे तो अन्यत्र भी स्थापित हो सकेगी। बैंच की संरचना अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। एक अध्यक्ष तथा दो या अधिक सदस्य हो सकेंगे।

  एक न्यायिक सदस्य अनिवार्य। जिस बैंच में अध्यक्ष नहीं हो, उसमें न्यायिक सदस्य अध्यक्षता करेगा।

झूठी शिकायतों पर कार्यवाही

- किसी व्यक्ति द्वारा झुठी, तुच्छ तथा चिढाने वाली (False, Frivolous and Vexations) शिकायत करने पर उसे एक वर्ष तक की सजा तथा एक लाख रूपयें के अर्थदंड का प्रावधान किया है।
- लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्मिक लोक सेवक माने जाएंगे।
- सात वर्ष से पुराने भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण की जाँच लोकपाल नहीं करेगा।
- अधिनियम लागू होने के एक वर्ष में राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाएगी।
- **न्यायिक शक्तियाँ-** कर्त्तव्यों के निर्वहन में लोकपाल को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत, सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी। यथा- हाजिर होने, गवाहों का सम्मन, शपथ साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख, साक्ष्य जाँच हेतु कमीशन नियुक्त करना आदि।
- लोकपाल के सम्मुख होने वाली कार्यवाहियाँ भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 193 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएँगी।
- लोकपाल प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन देगा। लोकपाल द्व ारा दी गई सलाहों को नहीं मानने के कारणों सहित रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखेगा।

लोकपाल की कमियाँ

लोकपाल तथा लोकायुक्त कानून 2013 की निम्नलिखित कमियाँ है-

1. प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत को निपटाने की बेहद अपारदर्शी विधि।
2. 7 साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता।
3. जोर शिकायत के रूप पर है, विषयवस्तु पर नहीं।
4. अनाम शिकायत की अनुमति नहीं है-सादे कागज पर शिकायत नहीं कर सकते भले ही उसके साथ सहयोगी दस्तावेज हों और उसे डब्बे में गिरा दिया गया हो।
5. जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है उसको कानूननी सहायता का प्रावधान।
6. गलत और धोखेभरी शिकायतों के लिए कड़े दंड। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें लोकपाल के यहाँ शिकायत पर लगाम लगाती हैं।

लोकपाल की सीमाएँ

- संसद के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के 5 वर्ष बाद किसी प्रकार के लोकपाल की नियुक्ति हो पाई, यह राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी का संकेतक है।
- लोकपाल राजनीतिक प्रभावों से रहित नहीं है क्योंकि स्वयं नियुक्ति समिति राजनीतिक दलों के सदस्यों से ही निर्मित है।
- लोकपाल के लिए नियुक्त होने वाले प्रख्यात न्यायविद् या सत्यनिष्ठा का व्यक्ति के लिए कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं है।
- लोकपाल को कोई संवैधानिक आधार नहीं दिया गया है और लोकपाल के विरुद्ध अपील करने का कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत उस तिथि से 7 वर्ष के बाद पंजीकृत नहीं की जा सकती है जिस तिथि को ऐसी कोई शिकायत में अपराध किये जाने का उल्लेख हो।

सुझाव :-

- लोकपाल की नियुक्ति ही स्वयं में पर्याप्त नहीं है साथ ही सरकार को उन मुद्दों को भी हल करना होगा जिसके आधार पर लोग लोकपाल की मांग करते हैं। केवल जाँच एजेन्सियों की संख्या में बढोतरी करना सरकार के आकार में तो बढोतरी करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रशासनिक कार्यो में भी सुधार आये।
- लोकपाल की नियुक्तियाँ पारदर्शिता से होनी चाहिये ताकि गलत प्रकार के लोगों के पदस्थापित होने की संम्भावना को कम किया जा सके।
- भष्ट्राचार की समस्या से निपटने के लिये कार्यात्मक स्वायत्तता और मानव शक्ति की उपलब्धता दोनों मामलों में लोकपाल संस्था को मजबूत किया जाए।
- लोकपाल वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्रों से अवश्य होने चाहिए जिनकी जाँच और जिन्हें दण्डित करने के लिए उन्हें कहा जाता है।

सम्यक् करेंट अफेयर्स - अक्टूबर - 2026 अंक पर आधारित टेस्ट

कुल प्रश्न: 100 **अंक: 200**

1. भरतपुर-ब्यावर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।

1. इस एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई तीन सौ अस्सी किलोमीटर है।
2. यह जयपुर जिले के दूदू स्थित झाग ग्राम से शुरू होगा है।
3. इसका विस्तार जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर में है।

कूट:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल-2026 में पुरस्कार श्रेणी और उसके विजेता के सन्दर्भ में सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए-

कैटेगरी		विजेता
1.बेस्ट डायरेक्टर	-	अनिंदम सील
2. बेस्ट एक्टर मेल	-	जिम्मी शेरगिल
3. बेस्ट एक्टर फीमेल	-	रिंकु राजगुरु

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

3. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में श्रेणी-I (10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर) क्रमश: शीर्ष तीन स्थानों पर रहने वाले शहर है-

(a) लखनऊ, इंदौर, जबलपुर (b) लखनऊ, इंदौर, कानपुर
(c)लखनऊ, सूरत, इंदौर (d) लखनऊ, इंदौर, सूरत

4. 33वें मथुरादास माथुर अवॉर्ड के तहत सब-जूनियर वर्ग में किसे सम्मानित किया गया है-

(a) निशाद खान (अलवर) (b) शिफान खान (जयपुर)
(c) कुशाग्र ओझा (भीलवाड़ा) (d) अशोक शर्मा (जयपुर)

5. खगांतक-243 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथन/कथनों में से सत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।

1. यह भारतीय वायु सेना के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लंबी दूरी का ग्लाइड बम है।
2. इसका परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में किया गया था।
3. इसका कुल वजन लगभग 300 किलोग्राम था।

कूट:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

6. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन 2026 के सन्दर्भ में असुमेलित युग्म का चयन करे-

1. आयोजन तिथि	-	9-10 सितंबर,2026
2. आयोजन स्थल	-	जापान
3. भागीदारी	-	लगभग 120 देश

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3

7. महिला टी-20 एशिया कप, 2026 का आयोजन कहां हुआ है-

(a) आस्ट्रेलिया में (b) श्रीलंका में
(c)संयुक्त अरब अमीरात में (d) भारत में

8. अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड-2026 के सन्दर्भ में असत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए।

1. इसके 20वें संस्करण का आयोजन किया गया था।
2. इसे अंतरराष्ट्रीय भूविज्ञान संगठन द्वारा आयोजित करवाया गया था।
3. इसमें भारत ने कुल 11 पदक (4 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य) जीते है।

कूट:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

9. 68वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार-2026 के विजेता और संबंधित देश को दर्शाने वाले सही सुमेलित युग्मों का चयन करे-

1. टॉमी कोह	-	म्याँमार
2. रुना खान	-	बांग्लादेश
3. बो की	-	सिंगापुर

कूट:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

सम्पूर्ण टेस्ट पेपर देने के लिए SAMYAK एप डाउनलोड करे---

QR Code

Samyak
An Institute For Civil Services

RAS-2024 RESULT

सम्यक् मार्गदर्शन सर्वश्रेष्ठ परिणाम


RANK 2
Virendra Charan


RANK 3
Navneet Sharma


RANK 4
Ravindra Singh


RANK 5
Vikash Siyag


RANK 6
Aishwarya Kanwar


RANK 7
Dinesh


RANK 9
Bhoopender Singh

07 RANKS in TOP 10 | **56** RANKS in TOP 100 | **690+** SELECTION in RAS-2024

IAS | RAS

FOUNDATION &

क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ
2 & 3 वर्षीय कोर्स

PSI

PAPER 1st & PAPER 2nd

COURSE FEATURE

- विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लासेज
- प्रिंटेड बुकलेट्स / ई-नोट्स*
- टेस्ट सीरीज
- पर्सनल मेंटरशिप
- लाइब्रेरी सुविधा*
- ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोर्स निःशुल्क

Offline & Online Separate Batches For Hindi & English Medium

HEAD OFFICE: NEAR RIDDHI - SIDDHI, JAIPUR 9875170111

सम्यक् मार्गदर्शन = सर्वश्रेष्ठ परिणाम

RAS 2024 में TOP 10 में 7, TOP 100 में 56, सहित 690+ चयन

सभी सफल प्रतिभाओं को हार्दिक बधाई!

RANK 2

VIRENDRA CHARAN

RANK 3

NAVNEET SHARMA

RANK 4

RAVINDRA SINGH

RANK 5

VIKASH SIYAG

RANK 6

AISHWARYA KANWAR

RANK 7

DINESH

RANK 9

BHOOPENDER SINGH

RANK 12

KULDEEP SHARMA

RANK 13

KAILASH KUMAR

RANK 16

KAILASH RANWA

RANK 18

UMANG RAWAL

RANK 23

SAHDEV BIDADA

RANK 24

PARAMVEER SINGH

RANK 25

SWAROOP SINGH

RANK 26

AANCHAL NAGPAL

RANK 27

MAMTA LIMBA

RANK 28

ARIHANT JAIN

RANK 29

SIMRAN SHEKHAWAT

RANK 30

VINAY MOHAN

RANK 31

ANSHIKA AGARWAL

RANK 33

LOKENDRA SINGH

RANK 34

VIKAS CHOUDHARY

RANK 35

SANJU

RANK 36

KRISHANPAL SHEKHAWAT

RANK 43

JITENDRA

RANK 45

AMAR SINGH RATHORE

RANK 46

MANASVINI VERMA

RANK 48

TULSI

RANK 49

RAMAVTAR MUNDEL

RANK 50

DHARMRAJ SINGH RAO

RANK 52

BHOOMIKA TRIVEDI

RANK 55

RONAK

RANK 57

POONAM

RANK 58

SACHIN AGRAWAL

RANK 59

PARUL CHOUDHARY

RANK 61

KAMLESH KR SHARMA

RANK 65

ARIMARDAN CHAUHAN

RANK 66

UNNAT KISHOR RAJORA

RANK 70

KRITIKA GAUR

RANK 71

URMILA VISHNOI

RANK 73

JAYESH PRAJAPAT

RANK 74

MAHENDRA DAN

RANK 76

SIDDHARTH DHAKAD

RANK 77

JYOTSANA RANAWAT

RANK 78

CHOUDHARY MADHU ROOPARAM

RANK 79

NITESH GUPTA

RANK 80

VIKASH BISHNOI

RANK 82

DAMODAR PAREEK

RANK 83

KAILASH KUMAR

RANK 84

SHYAM SUNDER MEENA

RANK 85

MOHIT GODARA

RANK 86

NARASI RAM BISHNOI

RANK 87

RAM RATAN BATESAR

RANK 88

MAHENDRA CHOUDHARY

RANK 99

GHAMANDA RAM

RANK 100

VANDANA PATEL

+690...